चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 18 अप्रैल-24 अप्रैल 2016 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बेहोश प्रधानमंत्री!

भारत सरकार की जासूसी

हचिसन-शाओमी ने कराई भारतीय सेना और सुरक्षा तंत्र की जासूसी

आईएसआई को पठानकोट बेस की महत्वपूर्ण सूचनाएं चीन ने दी थीं

वायुसेना की रिपोर्ट पर भी सोई रही नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सरकार

भारतीय सेना ने स्मार्ट फोन्स और स्मार्ट एप्स पर लगाई पूर्ण रोक

थल, वायु और नौसेना में नहीं होगा किसी भी स्मार्ट फोन का इस्तेमाल

अर्ध सैनिक बलों से भी इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया

प्रभात रंजन दीन

साल का पहला बड़ा ख़ुलासा

खुद को नहीं, देश को स्मार्ट बनाएं मोदी जी!

जो नेता संचार तकनीक के अत्याधुनिक माध्यमों का सटीक इस्तेमाल कर चुनाव जीतता हो और देश का प्रधानमंत्री बन जाता हो. जो प्रधानमंत्री स्मार्ट फोन, ट्विटर, फेसबुक समेत तमाम सोशल साइटों और एप्लिकेशंस के जरिए दुनिया पर छा जाने का उपक्रम करता हो. जो प्रधानमंत्री अपने नाम से तरह-तरह के स्मार्ट एप्लिकेशंस बाजार में उतारता हो. वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश में स्मार्ट फोन्स का जंजाल बिछा कर चीन की सेना चीनी कंपनियों के माध्यम से भारतीय सुरक्षा प्रणाली की जासूसी करती रही हो, भारतीय सेना सरकार से बार-बार इसकी शिकायत करती रही हो और उसकी कोई सुनवाई नहीं होती हो, आखिरकार विवश होकर सेना की तीनों शाखाओं को स्मार्ट फोन्स और स्मार्ट एप्लिकेशंस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगानी पड़ती हो ...यह देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं है तो क्या है? यह सवाल हम सत्ता अलमबरदार से नहीं, देश के आम लोगों से बांट रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं. इन सवालों का जवाब सत्ता-साधक मोदी जी के पास नहीं है. मोदी जी के पास इसका भी कोई ठोस जवाब नहीं है कि वे यह पक्के तौर पर बता सकें कि उनका अपना फोन जासूसी के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? जब सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को पता नहीं चल पाया कि वे जिस स्मार्ट फोन और जिस स्मार्ट एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह उनकी और उनके तमाम सरोकारों की जासूसी कर रहा है तो प्रधानमंत्री खुद अपने स्मार्ट फोन और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक के स्मार्ट फोन्स के बारे में गारंटी कैसे ले सकते हैं? सेना की तीनों शाखाओं में तो फिर भी इतना अनुशासन है कि उन्होंने खतरा पकड़ा तो बीमारी की तत्काल फौजी-स्टाइल की सर्जरी कर दी. लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे संवेदनशील महकमों में काम करने वाले सिविलियन स्टाफ को स्मार्ट फोन्स के इस्तेमाल से कौन रोक लेगा? यह सवाल नहीं है. यही भारत देश का अराजक यथार्थ है. आप खबर के मुख्य हिस्से में विस्तार से पढ़ेंगे कि किस तरह स्मार्ट फोन्स और स्मार्ट एप्लिकेशंस के जरिए भारतीय सेना और भारतीय सुरक्षा तंत्र की चीन की दो कंपनियों ने चीन की सेना की मिलीभगत से जासूसी की. विडंबना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशभर के लोगों तक स्मार्ट फोन्स, स्मार्ट एप्लिकेशंस और सोशल मीडिया की पहुंच कराने की बातें करते हैं. मोदी नए-नए स्मार्ट फोन्स की लॉन्चिंग करते भी देखे जाते हैं. मोदी नाम के कई एप्लिकेशंस तो वे लॉन्च करते ही रहते हैं. मोदी जहां भी जाते हैं वहां खूब सेल्फी खींचते-खिंचवाते हैं और उसे ट्विटर-फेसबुक के जरिए खूब प्रचारित-प्रसारित भी करते हैं. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश की सेना के गिरते मनोबल को तनिक भी नहीं भांप पाते कि सेना को किस ग्लानि और विवशता में सैनिकों के स्मार्ट फोन्स छीनकर फौज की चारदीवारी से बाहर फेंकने का निर्णय लेना पड़ा होगा! मोदी सरकार फौज के लिए ऐसी कोई कारगर स्मार्ट तकनीक क्यों नहीं मुहैया करा पाई कि हमारे फौजी देश के आम लोगों की तरह स्मार्ट फोन्स का इस्तेमाल करते और कोई चुंधियाई आंखों वाला जासूस उसे बेधने की हिम्मत नहीं कर पाता? फौज के लोगों को देश के आम नागरिक का दर्जा हासिल है कि नहीं? या मोदी जी आप इससे ही खुश हो लेना चाहते हैं कि नेता मंडली और अन्य लोग सारी आधुनिक सुख-सुविधाओं का भोग करते रहें, पर जिनके बूते हम सड़क पर ऐंठे-ऐंठे चल रहे हैं, वे खुद पुरातनकाल की सड़ियल-सुविधाओं और उपेक्षाओं के बीच बंदूकें लिए सीमा पर शहादत की अपनी बारी का इंतजार करते रहें! यह वाकई दुखद है और शर्मनाक भी. मोदी जी आप इसे महसूस करें, न करें...

पठानकोट एयरबेस हमले की साजिश रचने में अकेले पाकिस्तान नहीं बल्कि उसके साथ चीन भी शामिल था. चीन ने पाकिस्तान को भारत के पठानकोट एयरबेस से सम्बन्धित कई महत्वपूर्ण खुफिया जानकारियां मुहैया कराई थीं. चीन अपने कुछ खास स्मार्ट फोन्स और स्मार्ट एप्लिकेशंस के जरिए भारतीय सेना की संवेदनशील सूचनाएं हासिल कर रहा है और उसे लगातार आईएसआई को उपलब्ध करा रहा है. इस काम में चाइनीज़ कंपनियां हचिसन-वैमपोआ और शाओमी स्मार्ट फोन चीन की मदद कर रही हैं. चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ मिल कर दुनियाभर में साइबर-जासूसी करने में हचिसन-वैमपोआ कंपनी पहले से मशहूर रही है. पाकिस्तान के बंदरगाहों पर चीन ने हचिसन-वैमपोआ के जरिए ही दखल बनाई है. इस कंपनी से पाकिस्तान को भारी आर्थिक मदद मिल रही है. हचिसन कंपनी कुछ अर्सा पहले तक भारत में काम करती रही, लेकिन 2005-07 में अचानक उसने भारत का कारोबार बंद कर दिया. वोडाफोन ने उसे खरीद लिया. हच के इस तरह भारत से काम समेट लेने के पीछे भारी कर चोरी के अतिरिक्त कई और संदेहास्पद वजहें थीं, लेकिन भारत सरकार ने और भारत की खुफिया एजेंसियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. वही हचिसन प्रतिष्ठान अपनी साझीदार शाओमी के साथ भारतीय सेना की जासूसी में फिर से सक्रिय है. उसने चीन और पाकिस्तान को बहुत सारी खुफिया सूचनाएं मुहैया कराईं जिसका नतीजा पठानकोट जैसे आतंकी हमले के रूप में सामने आया और चीन ने आतंकवादी मसूद अजहर के बचाव में वीटो तक ठोकने से परहेज नहीं किया.

हम यह महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं कि हचिसन को भारत में घुसने की इजाजत किसने दी थी? हचिसन के जरिए भारत के चप्पे-चप्पे में चीनी सेना के कम्युनिकेशन-नेटवर्क स्थापित होने का मौका आखिर किसने दिया था? क्या भारत सरकार के अलमबरदारों को यह नहीं पता था कि हचिसन-वैमपोआ और चीन की सेना साथ मिल कर क्या काम करती है? भारत सरकार की बेधड़क जासूसी हो रही थी और केंद्र की सत्ता बेहोश बैठी थी? ये ऐसे सवाल हैं, जिसका जवाब देश के समक्ष आना ही चाहिए, क्योंकि इससे पूरी सरकार का दोयम दर्जे का राष्ट्र-चरित्र खुल कर सामने आ जाएगा. इसकी तत्काल सीबीआई जांच होनी चाहिए. हच के नाम से हचिसन कंपनी का भारत में आना ही अपने आप में एक बड़ा पैंडोरा-बॉक्स है, जिसे कायदे से खोला जाए तो कई विचित्र तथ्य उजागर होंगे. हचिसन कंपनी का भारत में निवेश किन शर्तों पर हुआ था, उस निवेश को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ने ठीक से मॉनिटर क्यों नहीं किया और कंपनी जब भारत से काम समेट कर जाने लगी तो उसकी (असली) वजहें जानने की भारत सरकार ने कोशिश क्यों नहीं की? यह मसला केवल करोड़ों या अरबों रुपये का टैक्स हड़पनेभर का नहीं है, यह मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है कि हचिसन को न केवल भारत में घुसने की इजाजत मिल गई बल्कि भारत की जमीन से ही हचिसन ग्रुप और चीनी सेना (पीएलए) के बीच कम्युनिकेशन-लिंक स्थापित करने की भी इजाजत मिल गई! हैरत है कि 90 के दशक से लेकर आज तक भारत सरकार इस मसले पर आंखें मूंदे रही. जाहिर है कि पूरे व्यवस्था-तंत्र को अपने ही देश के दीमक चाट रहे हैं और उसे खोखला कर रहे हैं. हचिसन के वेश में चीनी सेना को देश के घर-घर में घुसने का रास्ता भारत सरकार ने ही खोला और उसे लिबरल पॉलिसी और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी बता-बता कर अपनी पीठ खुद ही ठोकती रही. यह भी नहीं देखा कि राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाने के साथ-साथ वह देश का कितना अकूत धन सोख कर ले जा रही है. भारत सरकार और उसके तंत्र ने इसके नतीजे भी देखे, इसके बावजूद ऐसी कंपनियां भारत में अब भी खुला खेल रही हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है. सरकारें कभी लेह-लद्दाख तो कभी अरुणाचल में चीनी सेना की घुसपैठ की नियोजित नौटंकी खेलती हैं और देश के लोगों को भरमाती हैं. असलियत यह है कि हमारे चप्पे-चप्पे पर चीनी सेना की नजर है. हमारी प्रत्येक गतिविधियों पर चीनी जासूसों की निगरानी है. देश का एक-एक नागरिक चीन के लिए जासूसी का उपकरण अपने हाथ में लिए घूम रहा है. ऐसे हालात में हमारे यहां मुम्बई और पठानकोट जैसे आतंकी हमले नहीं होंगे तो क्या हम पर फूल बरसेंगे!

हमारी सूचना कहती है कि हचिसन और उसकी साझीदार शाओमी और रेडमी के स्मार्ट फोन्स व स्मेश'एप और वी-चैट जैसे स्मार्ट एप्लिकेशंस के जरिए चीन ने भारत के खिलाफ खूब जासूसी की और उसे पाकिस्तान से साझा किया. भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय से लगातार यह कहती रही कि चीन का बना स्मार्ट फोन शाओमी और रेडमी उनके खिलाफ जासूसी के काम आ रहा है. लेकिन भारतीय वायुसेना की सूचना को भारत सरकार ने गंभीरता से लिया ही नहीं. संसद में मामला भी उठा, फिर भी केंद्र सरकार ने विवादास्पद चाइनीज़ स्मार्ट फोन्स को प्रतिबंधित करने या मामले की खुफिया पड़ताल कराने की जरूरत नहीं समझी. हां, शिकायत मिलने पर सर्च इंजन गूगल ने स्मेश'एप जैसे एप्लिकेशन को अपने प्ले-स्टोर से जरूर हटा दिया और यह माना कि इस एप्लिकेशन का इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी भारत के खिलाफ जासूसी के लिए कर रही थी. पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में पठानकोट एयरबेस पर हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र की कार्रवाई के भारतीय प्रस्ताव पर चीन ने वीटो क्यों लगाया, इसकी वजह स्पष्ट है.

चीन के बने मोबाइल फोन्स की करतूतों पर भारत सरकार को चुप्पी साधे देख आखिरकार भारतीय सेना की तीनों इकाइयों ने स्मार्ट फोन्स के इस्तेमाल पर ही पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया. भारतवर्ष की लचर साइबर सुरक्षा व्यवस्था का खामियाजा भी आखिरकार सेना को ही भुगतना पड़ा. थलसेना, वायुसेना और नौसेना में स्मार्ट फोन्स के इस्तेमाल पर रोक के साथ-साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्स'एप, स्मेश'एप, ऑरकुट, वी-चैट, लाइन'एप जैसे स्मार्ट फोन एप्लिकेशंस, मैसेंजर एप्लिकेशंस और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इस्तेमाल पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है. सेना की तीनों इकाइयों के सैनिकों, जूनियर कमीशंड अफसरों और कमीशंड अफसरों से कहा गया है कि वे अपना ई-मेल आईडी भी तत्काल प्रभाव से बदल लें.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

बेहोश प्रधानमंत्री!

भारत सरकार की जासूसी

यह अब बीते दिन की बात हो गई...

पृष्ठ 1 का शेष

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) जैसे अर्ध सैनिक बलों से भी ऐसा करने को कहा गया है. पठानकोट हमले की पड़ताल के नाम पर पाकिस्तानी जांच दल के भारत आने के पहले देश की तीनों सैन्य इकाइयां स्मार्ट फोन्स, स्मार्ट एप्लिकेशंस और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इस्तेमाल से अलग हो चुकी थीं. भारतीय वायुसेना को इस बात पर गहरी नाराजगी है कि पठानकोट एयरबेस पर हमले की साजिश करने वाले मुल्क पाकिस्तान के षडयंत्रकारी अधिकारियों को ही भारतीय एयरबेस में घुसने की इजाजत कैसे दे दी गई!

सर्च इंजन गूगल ने अभी पिछले ही दिनों स्मेश'एप को अपने प्ले-स्टोर से हटाया है. इसकी आधिकारिक पुष्टि हुई कि इस एप्लिकेशन का इस्तेमाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई भारतीय सेना के खिलाफ जासूसी के लिए कर रही थी. इस एप से भारतीय सेना के कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही थी. दूसरे स्मार्ट एप्लिकेशन की तरह यह भी फ्री-एप्लिकेशन की तरह उपलब्ध था. इसे डाउनलोड करने के पहले करेंट लोकेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मीडिया गैलरी से जुड़ी कई सूचनाएं दर्ज करनी पड़ती थीं. इन सूचनाओं के जरिए और करेंट लोकेशन के आधार पर सम्बन्धित व्यक्ति की जासूसी आसान हो जाती थी. भारतीय सेना में इस एप्लिकेशन का खूब इस्तेमाल हो रहा था. सस्ते में उपलब्ध होने वाले शाओमी और रेडमी जैसे चाइनीज़ स्मार्ट फोन और मुफ्त में मिलने वाले स्मार्ट एप्लिकेशन का इस्तेमाल करके भारतीय सेना के अधिकारी और कर्मचारी चीनी और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी का आसान औजार बन गए थे. सेना की तकनीकी शाखा के अधिकारी कहते हैं कि शाओमी स्मार्टफोन में बाकायदा स्पाई-चिप्स फिट पाए गए जिससे खुफियागीरी आसानी से हो रही थी. यह देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील मुद्दा था, जिसकी तरफ भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया, और अब भी नहीं दे रही है. जबकि इस दरम्यान पठानकोट हमले जैसी आतंकी घटनाएं घटित हो चुकी हैं. शाओमी और रेडमी स्मार्ट फोन्स पर पाबंदी की बात तो छोड़िए, उसके और भी नए-नए संस्करण और मॉडल्स बाजार में उतारे जा रहे हैं. बड़े जोर-शोर से इन फोन्स के विज्ञापन भी दिखाए जा रहे हैं. हचिसन और शाओमी की एशियाई साझेदारी के बड़े-बड़े समाचार प्रकाशित कराए जा रहे हैं. लेकिन इस ओर भारत सरकार की नजर नहीं है. स्मार्ट फोन्स और एप्लिकेशंस के जरिए जासूसी की बात खुलने पर पता चला कि स्मेश'एप जैसे मैसेंजर एप्लिकेशन के जरिए यूज़र का पूरा डाटा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मुहैया कराया जा रहा था. स्मेश'एप का सर्वर जर्मनी में था, जिसे कराची का रहने वाला पाकिस्तानी एजेंट साजिद राना पीबीएक्समोबीफ्लेक्स.कॉम के नाम से चला रहा था. इस एप्लिकेशन की तकनीक चीन द्वारा डेवलप की गई थी. इसे इतने शातिराना तरीके से तैयार किया गया था कि उसे डाउनलोड करते ही यूज़र के फोन में दर्ज सारे डीटेल्स, एसएमएस रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो और यहां तक कि किन-किन लोगों से उसकी बातें हो रही हैं, उसका ब्यौरा भी सर्वर को मिल जाता था. इसी तरह शाओमी और रेडमी फोन्स द्वारा भी यूज़र-डाटा चीन में स्थापित सर्वर्स को भेजे जा रहे थे.

सेना में सोशल नेटवर्किंग साइट्स के इस्तेमाल पर पाबंदी के बारे में जानकारी देते हुए एक आला सेना अधिकारी ने बताया कि फेसबुक जैसी सोशल साइट्स या स्मार्ट एप्लिकेशन के इस्तेमाल से सेना के कर्मचारी या अफसर अनजाने में ही खुद ब खुद जासूसी के टूल के रूप में इस्तेमाल हो रहे थे. सेना के सामान्य अफसर या सैनिक तकनीकी तौर पर विशेषज्ञ नहीं होते, लिहाजा वे समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी सूचनाएं किस तरह बाहर लीक हो रही थीं. इसे देखते हुए सेना में स्मार्ट फोन्स के इस्तेमाल पर ही पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया. हाल के दिनों में यह चलन भी बढ़ गया था कि सेना के जवान या अफसर अपनी तैनाती की जगह की तस्वीरें और अपने हथियार के साथ खींची गई फोटो अपलोड कर रहे थे. उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो सारी सूचनाएं और तस्वीरें चीन होती हुई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हाथ तक पहुंच रही हैं और देश का नुकसान हो रहा है.

भारतीय सेना ने डायरेक्टर जनरल (मिलिट्री ऑपरेशंस) के जरिए सेना के सारे कमान को बाकायदा यह निर्देश दिया कि सैनिक (अफसर और जवान) या उनके परिवार के कोई भी सदस्य वी-चैट जैसे एप्लिकेशन का इस्तेमाल न करें. इस निर्देश में उन सारे एप्लिकेशंस का प्रयोग न करने की हिदायत दी गई है जिसके सर्वर विदेश में हों. सेना ने स्पष्ट कहा है कि इनके इस्तेमाल से गंभीर नुकसान हो सकता है और संवेदनशील सूचनाएं बाहर जा सकती हैं. सेना मुख्यालय ने आधिकारिक तौर पर माना है कि चीन के टेलीकॉम ऑपरेटर्स वी-चैट जैसे एप्लिकेशंस के जरिए सूचनाएं हासिल कर उसे चीन सरकार को दे रहे हैं. इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रेसपॉन्स टीम से मिली जानकारियों के आधार पर भारतीय वायुसेना की खुफिया शाखा ने भी यह रिपोर्ट दे रखी है कि शाओमी और रेडमी स्मार्ट फोन्स अपने सारे यूज़र डाटा चीन में बैठे आकाओं को मुहैया करा रहे थे. रेडमी फोन के अपने आप चीन स्थित आईपी एड्रेस से कनेक्ट होने के कई प्रमाण भी सामने आए. तब यह रहस्य खुला कि सर्वर (डब्लूडब्लूडब्लू.सीएनएनआईसी.सीएन) का मालिक चीन सरकार का सूचना उद्योग मंत्रालय खुद है. चीन की शह और मदद से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भारतीय सेना के कई छद्म नामों मसलन, इंडिया आर्मी न्यूज़, इंडियन डीफेंस न्यूज़ वगैरह के नाम से कई वेबसाइट्स खोलीं और एप्लिकेशंस लॉन्च किए. सेना के तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन एप्लिकेशंस की वास्तविकता जांचे बगैर उसे सही मान कर अपने स्मार्ट फोन्स में डाउनलोड कर लिया और जासूसी के ट्रैप में आसानी से फंस गए. बाद में पता चलने पर सेना अधिकारियों के सैकड़ों फोन्स फॉरमैट किए गए, लेकिन अधिक तादाद में यह संभव नहीं पाया गया. लिहाजा, स्मार्ट फोन्स के इस्तेमाल से ही परहेज करने को कह दिया गया. अब स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि सेना के अफसर से लेकर सैनिक तक अपने परिचितों से और बाजार में नोकिया या सैमसंग के पुराने की-पैड वाले मोबाइल फोन खोजते पूछते फिर रहे हैं, वह भी मिल जाए तो उससे वे अपने घर वालों से संवाद में रह सकें. ■

feedback@chauthiduniya.com

अब फौजियों के हाथ में नहीं रह पाएगा स्मार्ट फोन

भारत के लिए खतरनाक 'वैम्प' की तरह है वैम्पोआ

रिसर्च एंड अनालिसिस विंग (रॉ) के अधिकारी हचिसन-वैम्पोआ कंपनी को भारत के लिए खतरनाक वैम्प (खलनायिका) बताते हैं. हचिसन-वैमपोआ और शाओमी काफी करीब हैं और एशिया में साझा कारोबार करते हैं. हच के नाम से भारत में हचिसन का कारोबार था, लेकिन उसने भारत में व्यापार का अधिकार वोडाफोन को बेच डाला. भारत सरकार ने कभी इस बात की छानबीन नहीं कराई कि संचार का सहारा लेकर हचिसन कंपनी भारत में क्या-क्या धंधे करती रही और अचानक काम समेट कर क्यों चली गई. हचिसन कंपनी अरबों रुपये का कैपिटल गेन टैक्स हड़प कर चली गई, इस पर किसी को कोई दर्द ही नहीं हुआ. ऐसी ताकतें भारत की रीढ़ में किस हद तक घुसपैठ कर चुकी हैं, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं. हचिसन-वैमपोआ के मालिक ली का शिंग के चीन की सत्ता और चीन की सेना (पीएलए) से गहरे सम्बन्ध हैं. ली का शिंग की कंपनी हचिसन-वैमपोआ चीनी सेना की साइबर रेजिमेंट के साथ मिल कर साइबर वारफेयर और साइबर जासूसी के क्षेत्र में काम करती रही है. चीन के कम्युनिज्म का सच यही है कि चीन की सेना दुनियाभर में फैली कई नामी कॉरपोरेट कंपनियों की मालिक है या हचिसन-वैमपोआ जैसे कारपोरेट घरानों के साथ मिल कर काम करती है. इस तरह चीन की सेना दुनियाभर में जासूसी भी करती है और धन भी कमाती है. हचिसन-वैमपोआ और चीन की सेना ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका समेत दुनिया के तमाम देशों के बंदरगाहों को अपने हाथ में ले रखा है. बंदरगाहों का काम हचिसन पोर्ट होल्डिंग (एचपीएच) के नाम से किया जा रहा है. बंदरगाहों के जरिए हथियारों की आमद-रफ्त बेधड़क तरीके से होती रहती है. हचिसन-वैमपोआ लिमिटेड के चेयरमैन ली का शिंग चीन की सेना के लिए बड़े कारोबार में बिचौलिए की भूमिका भी अदा करते हैं. अमेरिका की ह्यूज़ कॉरपोरेशन और चाइना-हॉन्गकॉन्ग सैटेलाइट (चाइनासैट) के बीच हुए कई बड़े सैटेलाइट करारों में ली का शिंग ने अहम भूमिका अदा की थी. यहां तक कि चाइनासैट और एशियासैट में अपना धन भी लगाया. चाइनासैट और एशियासैट कंपनियां चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कंपनियां हैं. इसी तरह चाइना ओसियन शिपिंग कंपनी (कॉसको) भी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की है, जिसमें हचिसन-वैमपोआ लिमिटेड का धन लगा हुआ है. लीबिया, ईरान, इराक और पाकिस्तान समेत कई देशों में आधुनिक हथियारों की तस्करी में कॉसको की लिप्तता कई बार उजागर हो चुकी है. कुख्यात आर्म्स डीलर और अत्याधुनिक हथियार बनाने वाली चीन की पॉलीटेक्नोलॉजीज़ कंपनी के मालिक वांग जुन और हचिसन-वैमपोआ के मालिक ली का शिंग के नजदीकी सम्बन्ध हैं. पॉलीटेक्नोलॉजीज़ कंपनी का संचालन भी पीएलए द्वारा ही होता है. चीन के प्रतिष्ठित द चाइना इंटरनेशनल ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में वांग जुन और ली का शिंग,ये दोनों कुख्यात हस्तियां बोर्ड मेम्बर्स हैं.

चौथी दुनिया ने पहले भी कहा था चीन कितना खतरनाक

कुछ अर्सा पहले भी चौथी दुनिया ने यह खुलासा किया था कि चीन केउपकरणों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भरता बड़ी आपदा को न्यौता दे रही है. रणनीतिक विशेषज्ञ इस बात को लेकर चिंतित रहे हैं कि दूरसंचार क्षेत्र में हो रहा चीनी अतिक्रमण चीनी सेना की सोची-समझी रणनीति है.देश में अधिकांश बेस ट्रांसमिशन स्टेशन (बीटीएस) में चीनी कंपनियों हुआवेई और जेडटीई के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है. सबसे बड़ा खतरा यह है कि सभी चीनी बीटीएस को जीपीएस सिग्नल के लिए चीनी उपग्रहों पर स्थानांतरित कर दिया गया है. यह खतरनाक है, क्योंकि मोबाइल बीटीएस के जीपीएस मॉड्यूल में बदलाव करने से पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ढह सकता है. किसी आपात स्थिति में जीपीएस पल्स को ब्लॉक किया जा सकता है. यहां तक कि इसके रास्ते में बदलाव करके इसकी टाइमिंग बदली जा सकती है. देश का 60 प्रतिशत सीडीएमए और जीएसएम मोबाइल कम्युनिकेशन चीनी वेंडर्स ही चलाते हैं. इसलिए 60 प्रतिशत मोबाइल नेटवर्क पर सीधा खतरा है. यदि एक बार यह धराशाई हो गया तो बाक़ी 40 प्रतिशत पर इसका बोझ पड़ेगा. इस वजह से सारा मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क ठप्प पड़ जाएगा. सरकार के पास इससे उबरने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है. यानी देश के जीपीएस नेटवर्क में थोड़ी सी भी खराबी आती है तो सारा कम्युनिकेशन नेटवर्क अचानक बैठ जाएगा. हमने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल रखा है.

फिर उजागर हुआ चीन कितना हीन

चीन के राष्ट्रपति शी जिन पिंग

कुख्यात आतंकी सरगना मसूद अजहर

पठानकोट हमले को अंजाम देने वाले आतंकी सरगना मसूद अजहर के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में लाए गए भारतीय प्रस्ताव पर चीन के वीटो का मतलब साफ है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह किस तरफ खड़ा है. मसूद अजहर को पाक-साफ बता कर चीन ने दुनियाभर के सामने यह जाहिर कर दिया कि वह खुद कितना पाक-साफ है. भारत ने मसूद अजहर के खिलाफ प्रतिबंध के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति से आग्रह किया था. संयुक्त राष्ट्र के नियम-1267 के तहत सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाता तो पाकिस्तान व जिस भी देश में जहां मसूद अजहर की सम्पत्ति होती उसे जब्त कर लिया जाता और उसके आवागमन पर प्रतिबंध लग जाता. लेकिन चीन द्वारा वीटो लगने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया, जबकि समिति के अन्य सभी सदस्य इस प्रस्ताव से सहमत थे. मुम्बई हमले के सरगना जकी उर रहमान लखवी पर प्रतिबंध का प्रस्ताव भी चीन के अड़ंगे के कारण ही रुक गया था. चीन की इस हरकत के बाद भारत सरकार उसे चिंता वाले देशों की सूची में फिर से शामिल करेगी. अभी हाल ही चीन को उस सूची से अलग कर दिया गया था. पाकिस्तान चिंता वाले देश की सूची में शामिल है.भारत सरकार मसूद अजहर मामले को फिर से संयुक्त राष्ट्र ले जाने की तैयारी कर रही है.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 08 अंक 07
18 अप्रैल-24 अप्रैल 2016
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कोलकाता के भीड़-भाड़ वाले इलाके में निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरने से मच गया त्राहिमाम

मानुषेर-राजनीति पर गिरा भ्रष्टाचार का पुल

- नेताओं ने आपस में ही बांट लिए थे सारे ठेके
- मूल कंपनी भी है आंध्र और यूपी में ब्लैक-लिस्टेड

विनय बिहारी सिंह

कोलकाता के बड़ाबाजार इलाके के विवेकानंद रोड पर बन रहे फ्लाईओवर का डेढ़ सौ मीटर का हिस्सा पिछले 31 मार्च को दिन के 12 बजकर 32 मिनट पर अचानक धराशाई हो गया. बेहद खतरनाक ढंग से गिरे इस फ्लाईओवर के नीचे लोगों से भरी एक बस, तीन टैक्सियां, तीन प्राइवेट कारें, एक ट्रक, दो मोटर साइकिलें, दो हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शे और एक रिक्शा वैन दब और पिस गए. घोषित तौर पर इस हादसे में 27 लोगों की मृत्यु हो गई. लेकिन वहां मौजूद लोगों का कहना है कि मृतकों की संख्या इससे अधिक हो सकती है. इसके अलावा हादसे में लगभग 50 लोग बुरी तरह घायल हो गए जो कोलकाता के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं. इस पुल का निर्माण आईवीआरसीएल लिमिटेड नाम की हैदराबाद की एक कंपनी कर रही है. इस कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज हो चुकी है. घटना के अगले ही दिन कलकत्ता हाईकोर्ट में इस घटना के खिलाफ एक जनहित याचिका भी दाखिल हो गई. याचिका के दाखिल होते ही राज्य सरकार ने अपनी ही एजेंसी कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया. उसके दो इंजीनियरों से पूछताछ हुई है. इस फ्लाईओवर के निर्माण के लिए सब-कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनियों को दिया गया है जो छोटी हैं और उन्हें फ्लाई ओवर बनाने का कोई अनुभव नहीं है. आरोप है कि सब-कॉन्ट्रैक्ट वाली कंपनियां सत्तारूढ़ दल के नेताओं या उनके रिश्तेदारों की हैं.

केएमडीए के चेयरमैन, राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम हैं. उनका कहना है कि ठेका तो सीधे दिया नहीं जाता. अब तो ऑनलाइन हो गया है, इसलिए भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता. पुल के गिरने के लिए मुख्य निर्माता कंपनी ही जिम्मेदार है. इस घटना पर आईवीआरसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जो कहा उससे देश ही नहीं समूची दुनिया के लोग हैरत में पड़ गए. कंपनी के ग्रुप हेड (एचआर और प्रशासन) के. पांडुरंगा राव ने कहा, यह भगवान की करतूत है (दिस इज एक्ट आफ गॉड). हम 27 साल से काम कर रहे हैं, आज तक ऐसी घटना नहीं हुई. लोग आश्चर्य और क्षोभ से इस आदमी की बातें सुन रहे थे. उधर केएमडीए के कर्मचारी यूनियन के एक पूर्व नेता (वे अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं) ने कहा कि जब से फिरहाद हाकिम केएमडीए के चेयरमैन हुए हैं, इस ऑफिस के सारे अधिकार उन्हीं के पास चले गए हैं. छोटी-छोटी बातों का भी फैसला वही करते हैं. यहां अधिकारी कुछ नहीं कर सकते. उनका आदेश केएमडीए का नियम है. एक टेंडर को कई टुकड़ों में बांट देना, गैर अनुभवी व्यक्ति को काम दे देना अब केएमडीए का नियम बन गया है. पुल गिरने के सालों पहले केएमडीए का ढांचा चरमरा कर टूट गया है. यह संस्था वन मैन शो बन गई है. उधर तृणमूल कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हैं. सारे काम नियम से होते हैं. जो लोग फिरहाद हाकिम पर आरोप लगा रहे हैं, वे चुनाव में फायदा उठाना चाहते हैं.

आईवीआरसीएल लिमिटेड अपनी घटिया गुणवत्ता और अपारदर्शिता के लिए कुख्यात होती जा रही है. इस कंपनी के लिए काम कर रहे दो मजदूरों की 2009 में मौत हो गई थी. इस लापरवाही को देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रम विभाग ने जांच कराई थी और कंपनी को फटकार लगाई थी. इस कंपनी ने इसके पहले 2007 में पुडुचेरी सरकार से ठेके पर एक काम लिया जिसमें सुनामी तूफान से प्रभावित लोगों के लिए 5,400 घर बनाने थे. इसे नाम दिया गया सुनामी हाउसिंग प्रोजेक्ट. जब यह प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो इस कंपनी पर घटिया सामान का प्रयोग करने और डिजाइन में अवैध परिवर्तन करने का आरोप लगा. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2011 में इस कंपनी (आईवीआरसीएल लिमिटेड) के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कहते हैं. अब प्रश्न है कि जिस कंपनी के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है, उसे इस फ्लाईओवर को बनाने से क्यों नहीं रोक दिया गया और क्यों नहीं इसका ठेका किसी और बड़ी कंपनी को दिया गया?

इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें पीछे मुड़कर संक्षेप में देखना पड़ेगा कि यह कंपनी कब से पुल बना रही है. विवेकानंद रोड फ्लाईओवर की प्रस्तावित लंबाई है 2.2 (दो दशमलव दो) किलोमीटर. इसके निर्माण कार्य की डेड लाइन यानी काम पूरा होने की तारीख आठ बार बढ़ाई जा चुकी है. क्या दो किलोमीटर से कुछ ही ज्यादा लंबा फ्लाईओवर बनाने में आठ साल लगते हैं? और वह भी इतना घटिया निर्माण? छह बार तारीख बढ़ने के बाद इसे फरवरी 2016 में पूरा होना था, जो नहीं हो पाया. इसके बाद मई में पूरा होने की बात कही गई. हैदराबाद की इस कंपनी आईवीआरसीएल लिमिटेड को यह काम 24 फरवरी 2009 को दिया गया. तब प्रदेश में वाममोर्चा सरकार थी और मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य. इसका बजट था 164 करोड़ रुपये. इस काम को पूरा करवाने की जिम्मेदारी केएमडीए की है, क्योंकि वही इम्प्लिमेंटिंग एजेंसी है, यानी उसे ही काम की देखरेख, धन मुहैया और समय पर काम पूरा कराना था. फ्लाईओवर के गिरने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने कहा कि इस घटना के लिए केएमडीए जिम्मेदार है.

यहां यदि सिंडिकेट की चर्चा न की जाए तो यह रिपोर्ट अधूरी रह जाएगी. सिंडिकेट में वे लोग हैं जो किसी भी ऑफिस या फ्लाईओवर या बिल्डिंग के लिए ईंट, बालू, सीमेंट, छड़ और अन्य सामग्री आपको अपने यहां से लेने के लिए बाध्य करते हैं. चाहे आप अपना ही मकान क्यों न बना रहे हों. आपको भवन निर्माण का सामान उन्हीं के यहां से लेना पड़ेगा. आप यह नहीं कह सकते कि सामान किस क्वालिटी का है. जिस क्वालिटी का सामान वे देंगे, आपको वही लेना पड़ेगा. कीमत भी सिंडिकेट के लोग ही तय करते हैं. जब वाममोर्चा सत्ता में था तब उनके अपने सिंडिकेट थे. अब अनेक सिंडिकेट के लोग सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ गए हैं. आरोप तो यह भी है कि बड़े नेता भी इस सिंडिकेट के पीछे हैं. यह खेल बहुत ही चालाकी से होता है. इसी सिंडिकेट के लोग इस फ्लाईओवर के लिए भी निर्माण सामग्री उपलब्ध करा रहे थे.

फ्लाईओवर निर्माण का जिन कंपनियों ने सब-कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है, उनमें सबसे पहला नाम संध्यामणि प्रोजेक्ट लिमिटेड का है. यह रजत बक्शी की कंपनी है जो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय बक्शी के रिश्तेदार हैं. संजय बक्शी की पत्नी स्मिता बक्शी तृणमूल कांग्रेस की विधायक हैं. संध्यामणि प्रोजेक्ट ने ही घटना वाले दिन काम करने वाले मजदूरों को फ्लाईओवर पर भेजा था. पुलिस की नज़र संध्यामणि प्रोजेक्ट और रजत बक्शी दोनों पर है. इस कंपनी को सब-कॉन्ट्रैक्ट 2011 में मिला, जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई. एक समाचार पत्र को दिए बयान में रजत बक्शी ने कहा है कि दूसरे कई लोग हैं जिन्हें 2011 और 2012 के बीच राजनीतिक कारणों से सब-कॉन्ट्रैक्ट मिले. मेरा नाम इसलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि मेरा टाइटिल बक्शी है. मैं तो सिर्फ मजदूर सप्लाई करता हूं. अन्य 20 लोग भी सब-कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी भी जांच कीजिए.

रोनी कंस्ट्रक्शन अगस्त 2011 में बनी. इसके डायरेक्टर हैं समीर भट्टाचार्य व अन्य. भट्टाचार्य कहते हैं कि उनका तृणमूल कांग्रेस के किसी नेता से कोई संपर्क नहीं है. लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि भट्टाचार्य शशि पांजा (श्यामपुकुर की तृणमूल कांग्रेस की विधायक) और स्मिता बक्शी (जोड़ासांको की विधायक) के काफी करीब हैं. पड़ोस के एक व्यक्ति ने कहा कि समीर बाबू, उनके भाई प्रबीर बाबू और उनके परिवार के लोग इन दोनों विधायकों के साथ अक्सर देखे जाते हैं. समीर भट्टाचार्य कहते हैं कि हम तो सिर्फ मजदूर सप्लाई करते हैं. निर्माण कार्य दूसरे लोग करते हैं. विधायक शशि पांजा का कहना है, न तो मैंने कभी रोनी कंस्ट्रक्शन का नाम सुना है और न ही समीर भट्टाचार्य को जानती हूं. ऐसे ही मां कंस्ट्रक्शन, आशा कंस्ट्रक्शन व अनिंदिता कंस्ट्रक्शन को मिलाकर तकरीबन 20 सब-कॉन्ट्रैक्टर हैं जो इस फ्लाईओवर के निर्माण से जुड़े हैं. आरोप है कि ये सभी कंपनियां उन लोगों की हैं जो तृणमूल कांग्रेस से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं. आरोप है कि गैर अनुभवी सब-कॉन्ट्रैक्टर इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं. केएमडीए के एक पूर्व कर्मचारी ने कहा कि सब लूट लेना चाहते हैं. फ्लाईओवर की किसे चिंता है. बजट हर साल बढ़ रहा है. लोग मलाई खा रहे हैं. फ्लाईओवर में माल नहीं लगाया गया, इसलिए उसका हिस्सा टूट कर गिर गया. इस हादसे में जो अनाथ हो गए या जो स्त्रियां विधवा हो उन्हें इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप से क्या हासिल होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

आईवीआरसीएल लिमिटेड अपनी घटिया गुणवत्ता और अपारदर्शिता के लिए कुख्यात होती जा रही है. इस कंपनी के लिए काम कर रहे दो मजदूरों की 2009 में मौत हो गई थी. इस लापरवाही को देखते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रम विभाग ने जांच कराई थी और कंपनी को फटकार लगाई थी. इस कंपनी ने इसके पहले 2007 में पुडुचेरी सरकार से ठेके पर एक काम लिया जिसमें सुनामी तूफान से प्रभावित लोगों के लिए 5,400 घर बनाने थे.

आंध्र और यूपी में ब्लैक लिस्टेड है कंपनी

महेंद्र अग्रवाल

कोलकाता के बड़ाबाजार इलाके में हुए फ्लाईओवर हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. फ्लाईओवर बना रही कंपनी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सालों पहले से ब्लैक लिस्टेड है. यह कंपनी हैदराबाद की है और खुद अपने ही राज्य में ब्लैक-लिस्टेड. आइए देखते हैं कि इन दो राज्यों में यह कंपनी कब और क्यों ब्लैक लिस्टेड हुई थी. फ्लाईओवर बनाने वाली हैदराबाद की कंपनी आईवीआरसीएल अपने ही राज्य (आंध्र प्रदेश) में वर्ष 2009 में बैन कर दी गई थी. कंपनी को स्टेट लेबर डिपार्टमेंट की सिफारिश पर अगस्त 2009 में ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था. फरवरी 2011 में कंपनी को उत्तर प्रदेश जल निगम की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ब्लैकलिस्ट कर दिया. आईवीआरसीएल और एसपीएमएल नाम की कंपनियों पर वाटर एंड सीवरेज प्रोजेक्ट में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप था. आईवीआरसीएल कंपनी एनटीपीसी के पूर्व सीएमडी अरूप रॉय चौधरी की साठगांठ से मेजा पावर प्लांट का काम कर रही है जहां बीते साल मार्च के महीने में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर गिर गया था. इसमें एनटीपीसी को करोड़ों का नुकसान हुआ था. वही अरूप रॉय चौधरी एनटीपीसी से हटने के बाद ममता बनर्जी के सलाहकार बनाए गए हैं. ■

सरकार को चलाता है सिंडिकेट

पश्चिम बंगाल के एक स्थानीय टीवी चैनल का रिटंग-ऑपरेशन चर्चा में है. चैनल ने विधाननगर के मेयर और न्यू टाउन के विधायक सव्यसाची दत्त का स्टिंग किया है, जिसमें दत्त ने कहा है कि सिंडिकेट (सिंडिकेट क्या है, मुख्य रिपोर्ट में इसे बताया जा चुका है) के बाइस हजार लोग उनकी जी-जान से मदद कर रहे हैं. वे मतदाताओं को लाएंगे. उन्होंने यह भी कहा है कि सीपीएम (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी))और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) के पास भी सिंडिकेट हैं. लेकिन ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि यह पार्टी अभी सत्ता में है.

बहरहाल, जिस कोलकाता के जिस इलाके में फ्लाईओवर गिरा है, वहां की प्रत्याशी रिमता बक्शी हैं. राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस की प्रत्याशी रिमता बक्शी के चुनाव प्रचार में इस इलाके के लोग खास रुचि नहीं ले रहे हैं. लोग सदमे से उबर नहीं पाए हैं. इलाके के एक व्यक्ति ने कहा, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बैनर और झंडे उठाने वालों की कमी नहीं है. लेकिन ये लोग तब कहां थे, जब फ्लाईओवर के पीड़ितों के लिए राहत कार्य किया जा रहा था? मलबा हटाया जा रहा था? पीड़ितों को अस्पाल पहुंचाया जा रहा था? यह तो गुरुद्वारा छोटा सिख संगत और बड़ाबाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के स्वेच्छा सेवी लोग थे जिन्होंने पीड़ितों के लिए भोजन-पानी की व्यवस्था की और तीन दिन तक लगातार खटते रहे. तब हमारी विधायक कहां थीं? फ्लाईओवर बनाने वाली कंपनी आईवीआरसीएल लिमिटेड के लगभग आठ लोग यह रिपोर्ट लिखे जाने तक गिरफ्तार हो चुके थे. इनमें ए गोपाल कृष्णमूर्ति (डायरेक्टर आफ ऑपरेशन), एस के रत्नम (डीजीएम- प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल), दो इंजीनियर (श्याम मन्ना और वियुत मन्ना) जो घटना के समय वेल्डिंग की जांच कर रहे थे शामिल हैं. प्रोजेक्ट हेड- तन्मय सील को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. इस कंपनी से जुड़े बाकी तीन लोगों को हादसे के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया था. अभी भी कई लोगों की गिरफ्तारी होनी है. पुलिस उन्हें तलाश रही है. राज्य सरकार ने टेक्निकल जांच कमेटी बनाई है जो इस हादसे के सारे पहलुओं की जांच करेगी और संबंधित लोगों से पूछताछ करेगी. कोलकाता का आईवीआरसीएल लिमिटेड का कस्बा और बिडन स्ट्रीट का कार्यालय सील कर दिया गया है. फॉरेंसिक लैब ने घटना स्थल से नमूने ले लिए हैं. एक मुख्य जांच अधिकारी का कहना है कि हम जांच करेंगे कि जब मजदूरों ने कहा कि पलाईओवर से पानी रिस रहा है और बोल्ट बार-बार गिर रहे हैं तब किसने निर्माण कार्य जारी रखा.

जब फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हुआ तो केएमडीए के कुछ इंजीनियरों ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस तरह फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, कोई न कोई दुर्घटना हो सकती है. इसकी तकनीक और इस्तेमाल होने वाले सामान के प्रति बहुत सतर्क रहने की जरूरत है. लेकिन इसे सरकार और निर्माता कंपनी ने हल्के में लिया. ■

शराबबंदी के दौर में ताड़ी और महुआ

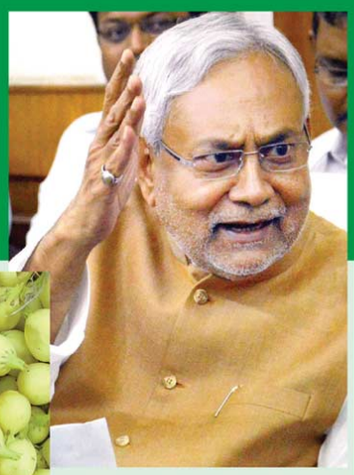

सरोज सिंह

बिहार में इस अप्रैल की पहली किरण के साथ शराबबंदी का पहला चरण शुरू हुआ और एक हफ्ते के भीतर ही सूबे में पूर्ण शराबबंदी घोषित कर दी गई. नए वित्त वर्ष के साथ अर्थात एक अप्रैल 2016 से देशी और मसालेदार शराब का उत्पादन, वितरण और बिक्री के साथ-साथ उपयोग प्रतिबंधित हो गया. पर इस आंशिक शराबबंदी से उत्साहित नीतीश सरकार ने पांचवे दिन यानी पांच अप्रैल, 2016 को विदेशी शराब के उत्पादन, वितरण और बिक्री के साथ-साथ उपयोग पर भी रोक लगा दी. इससे बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हो गई. सरकार के फैसले के इस ताप में ताड़ी भी तपने लगी है. इससे ताड़ी को उछाल मिली है. उसकी बिक्री तो बढ़ ही गई, उसकी कीमत भी चढ़ गई है. फिर क्या, ताड़ी और महुआ को लेकर पहले के आदेश को सख्ती से लागू कराने को सरकार सक्रिय हो गई. इनकी बिक्री के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को अफसरों को कहा गया. हालांकि, ताड़ी को लेकर कुछ भ्रांति भी बन गई, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका निराकरण कर दिया है. उन्होंने साफ किया है कि एक अप्रैल, 1991 को जारी अधिसूचना में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. उन्होंने यह भी साफ किया कि ताड़ और उसके उत्पादों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है.

ताड़ी को लेकर बिहार सरकार का वह आदेश लालू प्रसाद के कार्यकाल में जारी किया गया था. इसके जरिए ताड़ी की बिक्री को नियमित किया गया है. इसके अनुसार किसी हाट-बाजार के भीतर या उनके प्रवेश स्थल पर, किसी शैक्षणिक संस्थान, धर्म-स्थल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस पड़ाव आदि के निकट और किसी उच्च पथ, मजदूरों की बस्ती, फैक्टरी के निकट ताड़ी की दुकान नहीं खोली जा सकती है. उस समय इस आदेश के साथ ही ताड़ी को उत्पाद कर से मुक्त कर दिया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि पच्चीस वर्ष पुरानी इस अधिसूचना को सख्ती से लागू किया जाएगा.

ताड़ी और महुआ को लेकर सारी परेशानी एक अप्रैल को शराबबंदी लागू होने के साथ पैदा हुई थी. उत्पाद विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक ने शराबबंदी को लागू करने के साथ इन पर भी रोक लगाने का निर्देश जारी कर दिया. कहा गया कि शराबबंदी के बाद ताड़ी की बिक्री बढ़ गई और दाम भी बढ़ गए. लिहाजा उस पर रोक लगाई जाए. उत्पाद विभाग के साथ-साथ पुलिस के जवान भी एक्शन में आ गए. ताड़ी दुकानों पर कार्रवाई तेज़ हुई. यही हाल रहा महुआ का. सरकारी आदेश के अनुसार कोई व्यक्ति पांच किलोग्राम से अधिक महुआ फूल नहीं रख सकता है. इससे अधिक मात्रा में महुआ रखना अपराध माना जाएगा. ऐसा करने वाले के ख़िलाफ कार्रवाई की जाएगी. ताड़ी पर सख्ती के सरकार के आदेश का विपक्ष ने तो विरोध किया ही, अपने भी सहमत नहीं लगते हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतनराम मांझी ने हालांकि शराबबंदी का समर्थन किया है लेकिन ताड़ी पर सख्ती का विरोध किया है और सरकार से आदेश वापस लेने की अपील की. इस मसले पर महागठबंधन के दलों में सर्व सहमति नहीं है. यहां तक कि नीतीश सरकार में खनन एवं भूतत्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी ने ही इस पर अपनी आपत्ति जताई है. वह महादलित समुदाय से आते हैं और राजद कोटे से मंत्री हैं. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी ताड़ी के मसले पर सख्ती के पक्षधर नहीं दिखते हैं. इस मसले पर पत्रकारों से उन्होंने साफ कहा है कि सरकार ताड़ी के सवाल को देखेगी. लेकिन ताड़ी को लेकर सरकारी आदेश के विरोध में इससे जुड़े लोग सड़क पर उतरने लगे हैं.

बिहार को नशा-मुक्त करने के लिए बने नए उत्पाद क़ानून में गांजा और भांग को शामिल किया गया है. इनकी खेती और किसी भी रूप में व्यापार को अपराध माना गया है और इसके लिए दस साल तक की कैद व दस लाख तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है लेकिन ताड़ी और महुआ इसके दायरे से बाहर रहे. नतीजतन, शराबबंदी लागू होते ही लोग इनकी ओर मुड़े और इनकी मांग ने नई छलांग ली. इनकी कीमत भी तेज़ी से ऊपर चढ़ी. यह खबर पाने के बाद सरकार सक्रिय हुई और उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के प्रधान सचिव ने सभी जिला अधिकारियों को पुराने आदेश को सख्ती से लागू करने को कहा है ताकि ताड़ी और महुआ की शराब के कारोबार को नियंत्रित किया जा सके. इससे ताड़ी कारोबार से जुड़े सामाजिक समूहों में हड़कंप मच गया है.

अब मुख्यमंत्री की ओर से भी बातें साफ कर दी गई हैं. इसका कैसा असर होता है, यह अभी देखना है. पर, बिहार में ताड़ी के कारोबार को नियंत्रित करने के पच्चीस साल पुराने आदेश का कोई प्रभाव कहीं नहीं दिखता है. उक्त आदेश के बावजूद ताड़ी की खपत के मामले में बिहार देश में चौथे नम्बर पर है. एक नम्बर पर आंध्र प्रदेश है. फिर असम और झारखंड हैं. इनके बाद बिहार का नम्बर आता है. बिहार में अन्य राज्यों के मुक़ाबले प्रति व्यक्ति प्रतिमाह ताड़ी पर साढ़े तीन रुपये अधिक खर्च किया जाता है. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में सूबे में ताड़ के पेड़ कम हुए हैं. पुराने पेड़ कट रहे हैं और नए पेड़ों को लगाने की गति संतोषजनक नहीं है. फिर भी ताड़ी की दुकानों में कमी नहीं रही है. सूबे की किसी भी दिशा में छोटी-बड़ी सड़कों के किनारे इसकी दुकानों का लंबा सिलसिला देखा जा सकता है. इसी तरह सरकार ने महुआ और महुआ फूल से शराब बनाने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था. लेकिन महुआ फूल के अनेक उपयोग के मद्देनजर कहा गया कि कोई दमी पांच किलोग्राम तक महुआ फूल रख सकता है. बिहार के कई हिस्से में महुआ से शराब बनाने का कारोबार चलता है. इस काम में लगे लोगों के अनुसार अच्छी क्वालिटी के एक किलोग्राम महुआ फूल से एक बीयर बोतल के बराबर शराब निकलती है. कहते हैं कि महुआ के इलाके में महुआ शराब के कारोबारी फैले हैं. ये लोगों से फूल की खरीद करते हैं और उससे शराब बनाते हैं. ऐसे कारोबार को रोकना ही उक्त क़ानून का उद्देश्य है. लेकिन बहुत सारे क़ानूनों की तरह यह भी समय के साथ बेअसर होता गया. राज्य के सुदूर ग्रामीण इलाकों की चर्चा करना ही बेमानी है जब राजधानी पटना के ही कई इलाके में महुआ की शराब बनती और बिकती है.

सरकार के शराबबंदी अभियान का सूबे के हर हलके में स्वागत किया जा रहा है. पर, ताड़ी और महुआ को लेकर इसके स्टैंड का विरोध आरंभ हो गया है. महुआ को लेकर दक्षिण-पश्चिम बिहार के कुछ हिस्सों में सरकारी कार्रवाई का विरोध किया जाता है, तो ताड़ी को लेकर सभी हाजीपुर, छपरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, बेतिया सहित कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं. महागठबंधन के दलों के नेता भी शराबबंदी को लेकर उत्साहित तो दिखते हैं, मगर ताड़ी और महुआ के नाम पर वे भी कुछ मंद हो जाते हैं. प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी शराबबंदी में ही उलझे हैं. लिहाजा ताड़ी की दुकानों की ओर नज़र डालने का मौक़ा उन्हें कम या नहीं ही मिल रहा है. फिर, इस महीने ग्रामीण इलाकों में ताड़ी की खपत काफी बढ़ गई है. इसकी कीमत भी बढ़ रही है. प्रदेश में पंचायत चुनाव का दौर आरंभ हो रहा है. इस वजह से भी ऐसा हो रहा है. ताड़ी व्यवसायी समुदाय के एक व्यक्ति पर भरोसा करें तो यह उनके कारोबार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दौर है यह मौसम के ख्याल से भी और हालात के ख्याल से भी. शराबबंदी के कारण इस ओर खरीददारों की भीड़ बढ़ी है. उनका यह भी मानना है कि सत्तारूढ़ महागठबंधन के दलों के आंतरिक अंतर्विरोध ताड़ी और महुआ की शराब के बाजार की बड़ी उम्मीद हैं. विभाग के प्रधान सचिव केके पाठक अपनी सक्रियता और सख्ती के लिए चर्चित रहे हैं. पर, राजनीति की अपनी गति होती है जो सत्ता की कुर्सी से प्रेरित-अनुप्रेरित होती है. ताड़ी और महुआ को लेकर कार्रवाई जिन सामाजिक समुदायों और आर्थिक समूहों को प्रभावित कर रही है, राजनीति को उनकी जरूरत कम नहीं है. तो क्या यह मामला इसी तरह चलता रहेगा और ताड़ी सूबे में इसी तरह बेलगाम दिखेगी? राज्य की सत्ता और राजनीति की गति पर नज़र रखनेवालों के एक बड़े तबके का जवाब हां में ही आ रहा है. महुआ और ताड़ी पर सख्ती भी रहेगी और बाजार में यह बेरोक-टोक दिखेगी भी. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

शिक्षा के मंदिर में देह व्यापार

प्रशांत श्रेयस

शिक्षा के मंदिर में यौन शोषण, सेक्स रैकेट चलने के मामले पर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन गोड्डा जिले के पथरगामा स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय की उन्नीस वर्षीय छात्रा ने विद्यालय में सेक्स रैकेट चलने का खुलासा कर सनसनी फैला दी. ग्यारहवीं कक्षा की छात्रा आयशा (बदला हुआ नाम) ने विद्यालय की वार्डन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए. छात्रा छह माह की गर्भवती थी और गर्भपात के लिए उसे दवा दी गई, ज्यादा मात्रा में गर्भपात वाली दवा लेने के कारण जब उसकी स्थिति बिगड़ी, तब यह मामला उजागर हुआ. वैसे शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले को ही बेबुनियाद बताते हुए दोनों वार्डन को क्लीन चिट दे दी. यही नहीं, इस प्रकरण में उल्टे छात्रा को ही कठघरे में खड़ा करते हुए छात्रा पर नियमित रूप से स्कूल नहीं आने का दोष मढ़ दिया. होली के बाद जब छात्रा घर से वापस लौटी तो विद्यालय की छात्राओं व शिक्षकों को इस बात की जानकारी हुई, कि छात्रा गर्भवती है. अभिभावक ने भी बदनामी के डर से इस बात को छिपाने का आग्रह शिक्षिका सहित वार्डन से किया था, इस कारण इस बात को गोपनीय रखा गया. राज्य की शिक्षा मंत्री डॉ नीरा यादव ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इससे छात्राओं के भविष्य पर ख़तरा उत्पन्न होगा, वहीं विपक्ष ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है.

इस मामले के उजागर होने के साथ ही कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिका एवं वार्डन के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने एकजुट होकर छात्राओं पर ही अनैतिक कार्य में लिप्त होने का आरोप मढ़ डाला. इन लोगों ने सरकार से यह मांग कर डाली, कि छुट्टी के बाद छात्राएं स्कूल आती हैं, तो छात्राओं का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाए. इस प्रकार के बयान से अभिभावकों में उबाल आ गया. उनकी मनोभावनाएं विचलित हो गईं. दुमका जिले के जेंडर समन्वयक अरुण कुमार भी इसे सही मानते हैं. उनका कहना है कि अवकाश के बाद स्कूल आने वाली छात्राओं का प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए जबकि जिले के उपायुक्त राहुल सिन्हा के अनुसार यह सरासर गलत है. ऐसा कोई आदेश जिला प्रशासन ने नहीं दिया है. टेस्ट पूर्णतः गैरक़ानूनी है. केवल छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण का आदेश दिया गया है, ताकि अगर कोई लड़की बीमार है, तो उसका इलाज कराया जा सके या उसे घर भेजा जा सके. नियमानुसार किसी का प्रगेनेंसी टेस्ट नहीं हो सकता है. इधर जिला शिक्षा अधीक्षक ने भी कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के वार्डन के साथ बैठक कर यह निर्देश दिया था, कि अवकाश के बाद स्कूल लौटने पर छात्राओं का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाए. इसका भारी विरोध होने पर इस निर्णय को वापस लेना पड़ा.

झारखंड शिक्षा परियोजना की निदेशक राजेश्वरी बी द्वारा दोनों वार्डन को क्लीन चिट दिए जाने से भी अभिभावक नाराज हैं. घटना के उजागर होने के बाद दोनों वार्डन को पुलिस ने हिरासत में लिया था, परंतु उन्हें रिहा कर दिया गया. जिले के पुलिस कप्तान संजीव कुमार ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर गोड्डा महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. विद्यालय के दो वार्डन के ख़िलाफ गर्भपात कराने, बलात्कार, साक्ष्य छिपाने व पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

गोड्डा हो या विशाखापत्तनम हर जगह एक ही मानसिकता बता रही है, कि चाहे क़ानून कितना भी कड़ा क्यों न बना दिया जाए, लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आने वाले हैं. पथरगामा की घटना तो शर्मसार कर देने वाली है. अविवाहित और नाबालिक छात्रा के गर्भवती होने की पोल भी खुली. छात्राएं पढ़ाई के लिए घर-परिवार छोड़कर स्कूल में दाखिला लेती हैं. इसमें अभिभावक तुल्य शिक्षक का संरक्षण नहीं मिलना अपने आप में बड़ा सवाल है. ऐसे में लाख टके का सवाल यह भी है कि जब रक्षक ही जब भक्षक बन जाएं तो फिर किसपर भरोसा किया जाए. खास बात यह भी है कि प्रदेश के सभी 83 कस्तूरबा विद्यालयों की स्थिति भी काफी दयनीय है. आबादी से दूर बने ऐसे विद्यालयों में सुरक्षा के कोई प्रबंध नही हैं. स्कूलों में चहारदीवारी नहीं होने के कारण छात्राएं हमेशा भयभीत रहती हैं. अपराधिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है व इसके अलावा छेड़छाड़ की घटनाएं तो आम बात हैं. छात्रावास होने के बावजूद रात्रि प्रहरी की व्यवस्था नहीं है. विद्यालय का ही कोई चपरासी या कर्मचारी रात्रि प्रहरी की भूमिका में रहता है. विद्यालय की वार्डन भी अपने घर चली जाती हैं. छात्राएं यहां मजबूरन भगवान भरोसे रहती हैं.

पथरगामा स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में इस घटना के उजागर होने के बाद सरकार की नींद खुली. राज्य की शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने कहा कि सभी आवासीय विद्यालयों में ऊंची चहारदीवारी का निर्माण करने के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे. रात्रि सुरक्षा की व्यवस्था करने के साथ ही संबधित थानों को गश्त तेज़ करने के निर्देश दिए जाएंगे ताकि छात्रावास में छात्राओं को सुरक्षा दी जा सके और वे निर्भीक होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें. कस्तूरबा आवासीय विद्यालयों के गठन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में होनहार छात्राओं की तलाश करना और उन्हें बेहतर शिक्षा मुहैया करना था, लेकिन अक्सर

ये विद्यालय विवादों में ही रहा. कभी छात्राएं सुविधा के आभाव में तो कभी सुरक्षा के भय से विद्यालय से भाग जाती हैं. पथरगामा का कस्तूरबा विद्यालय तो हमेशा से विवादों में घिरा रहा है. कभी शिक्षिका द्वारा छात्राओं को पीटने के मामले में तो कभी छात्राओं के विद्यालय से भागने के कारण लेकिन इस बार तो छात्रा ने ही स्कूल में सेक्स रैकेट चलने का खुलासा कर सभी को स्तब्ध कर दिया. इस खुलासे के बाद तो पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया.

सूत्रों की माने तो इस आवासीय विद्यालय में रात को जिले के शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी तो आते-जाते ही थे, साथ ही स्कूल में सामान की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार भी बेधड़क आते-जाते थे. दरअसल ये ठेकेदार उसी स्कूल की किसी शिक्षिका के पति या रिश्तेदार होते हैं. इन्हें ही ठेका भी मिलता है. ये लोग भी छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किया करते थे. पीड़ित छात्रा ने तो यहां तक आरोप लगाए हैं कि स्कूल की शिक्षिका छात्राओं को रात में वरीय अधिकारी या अन्य किसी के पास जाने के लिए विवश करती थीं. रात या दिन में भी छात्राओं को होटल तक भेजा जाता था. ज़ाहिर है कि इस स्कूल में सेक्स रैकेट चल रहा था. पीड़ित छात्रा बगल के ही गांव की रहने वाली थी. उसने दसवीं पास करने के बाद ग्यारहवीं में नामांकन कराया था. उसने बताया कि उसके गर्भवती होने की जानकारी जब शिक्षिका को हुई तो उसने मुंह बंद रखने की सलाह देते हुए गर्भपात की गोलियां खाने को दीं. गोलियां खाने के बाद गर्भपात हुआ, लेकिन उसकी स्थिति बिगड़ती देख शिक्षिका ने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया. इसके बाद उसे गांव भेज दिया. वहां उस लड़की ने परिवार को अपनी पीड़ा सुनाई. इसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उन्होंने वार्डन की गिरफ्तारी के साथ पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग करने लगे. राजनीतिक दलों ने भी इसे मुद्दा बनाया और जांच की मांग का समर्थन करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की.

इधर विद्यालय की वार्डन का कहना है, कि छात्रा होली की छुट्टी के बाद स्कूल आई थी. बाथरूम में खून के धब्बे व गर्भपात के निशान मिले तो वार्डन ने छात्राओं से इस बात की जानकारी ली तो पता चला कि आयशा की तबीयत खराब है. जब उससे बातचीत की तो हमलोगों के होश उड़ गए. छात्रा ने स्वयं को गर्भवती बताया और गर्भपात के उद्देश्य से उसने दवा खाने की बात कही. शिक्षिकाओं का कहना है कि उक्त छात्रा की उपस्थिति भी कम रहती थी. संभवत: वह गांव चली जाती थी. वहां उसका किसी के साथ अनैतिक संबंध रहा होगा. जांच टीम की मुखिया शिक्षा परियोजना निदेशक राजेश्वरी वी ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि आवासीय विद्यालय में कोई अनैतिक कार्य नहीं होता था. पीड़िता के आरोप सरासर बेबुनियाद हैं. उन्होंने वार्डन को क्लीन चिट भी दे दी. वैसे इस जांच पर उंगलियां उठने लगी हैं. निदेशक अपने पति व बच्चों के साथ वहां जांच करने गईं और दो घंटे के भीतर जांच पूरी करके रांची लौट गईं और अपनी रिपोर्ट सौंप दी. निदेशक ने पीड़िता का बयान तक दर्ज करना उचित नहीं समझा. ऐसे में सवाल यह है कि जब पीड़िता का बयान ही नहीं लिया गया तो आरोपियों को क्लीन चिट कैसे दे दी गई. छात्रा के अभिभावकों और ग्रामीणों से भी बातचीत नहीं की गई. मामले को रफा-दफा करने के लिए केवल विद्यालय की छात्राओं एवं शिक्षकों के बयान लेकर जांच रिपोर्ट सौंप दी. अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों के होश क्यों उड़ गए थे? रातोंरात जांच कमेटी क्यों बनाई गई? हर स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात क्यों उठी? इन सभी बातों पर गौर करें, तो शंका होती है कि वहां दाल में जरूर कुछ काला है. प्रदेश के विपक्षी दलों ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है. झामुमो व झाविमो सहित अन्य दलों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है. अब देखना है, कि शिक्षा मंदिर को दूषित करने वालों को सजा मिलती है या मामले को यूं ही रफा-दफा कर दिया जाता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

दमोह-निर्मल जैन

स्वयं सेवक की दुख भरी कहानी

मोहन भागवत के लिए

- 35 साल से न्याय पाने के लिए लड़ रहा है संघ का स्वयं सेवक.
- आपातकाल में जेल गए, नौकरी गई, बेटा-बेटी खोया.
- शिवराज सिंह चौहान के पास मिलने का समय भी नहीं है.
- केंद्र और राज्य में सरकार, फिर भी नहीं मिली कोई मदद.

शशि शेखर

नौ साल की उम्र से एक व्यक्ति संघ की शाखा में जाता रहा. उम्र के सातवें दशक में भी वह आदमी खुद को संघ का सिपाही बताता है. किसी संगठन के प्रति इस समर्पण की तो बस सराहना ही की जा सकती है. आपातकाल का विरोध करते हुए यही व्यक्ति जेल जाता है और, जेल से छूटने के बाद से ही उसकी जिंदगी बदल जाती है. जीते-जी उस व्यक्ति के लिए यह जीवन एक ऐसे स्याह संघर्ष में तब्दील हो जाता है, जिसका आज भी कोई समाधान होता नज़र नहीं आ रहा है. पिछले 37 सालों की इस त्रासद जिंदगी में इस व्यक्ति ने अपने बेटे को खोया, अपनी बेटी को खोया, अपनी मां को खोया, अपनी नौकरी खोई और अपनी पत्नी को बीमार होता देखा. लेकिन, इसके बाद भी कोई चीज इस आदमी ने नहीं खोई है, वह है उसका हौसला, उम्मीद और न्याय पाने की राह पर चलने की ताकत. क्या आप यकीन कर सकते है कि एक सामान्य सा आदमी न्याय पाने के लिए पिछले 38 साल से इस व्यवस्था से लगातार लड़ सकता है, वह भी इतना सब कुछ खोने के बाद. क्या आप सोच सकते हैं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक सिपाही की हालत इतनी दयनीय हो सकती है, वह भी तब जब केंद्र समेत राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है.

यह कहानी है, निर्मल जैन की. उनके संघर्ष की. मध्य प्रदेश के दमोह जिले के रहने वाले है, निर्मल जैन. आप कभी उनसे मिलें, उनसे कुछ देर बातें करें, तो आपको भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए न तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत होगी न ही बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा प्रकाशित रिसर्च पेपर पढ़ने की जरूरत महसूस होगी. क्योंकि, निर्मल जैन की हर एक बात, उनकी जिंदगी से जुड़ी हर एक घटना अपने-आप में भारतीय व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करती है. यह कहानी शुरू होती है, साल 1974 से. दमोह जिले के सहकारी बैंक में निर्मल जैन को नौकरी मिल जाती है. चूंकि, वह संघ के एक समर्पित स्वयं सेवक थे, इसलिए उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और नतीजतन उन्हें जेल जाना पड़ा. जेल से वह 1977 में बाहर आए और फिर से अपनी नौकरी उसी बैंक में शुरू की. चौथी दुनिया से बात करते हुए निर्मल जैन बताते हैं कि चूंकि उन्होंने आपातकाल का विरोध किया था और बैंक के चेयरमैन कांग्रेसी पृष्ठभूमि के थे, इसलिए 1978 में, बैंक के चेयरमैन ने उनके ख़िलाफ साजिशें शुरू कर दी. निर्मल जैन के खिलाफ चेयरमैन ने करीब 5 हजार रुपये के गबन का आरोप लगाया और उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया. निर्मल जैन को नौकरी से निकाल दिया गया. यह मुक़दमा 15 साल तक चला. 1993 में इसका फैसला आया. इस केस में निर्मल जैन बेदाग साबित हुए, लेकिन उन्हें नौकरी पर वापस नहीं रखा गया. बल्कि, बैंक मैनेजर के ख़िलाफ मुक़दमा दर्ज करने का आदेश दिया गया.

सवाल यह है कि जब अदालत ने निर्मल जैन को आरोपी नहीं माना और उन्हें बेदाग पाया बावजूद इसके उन्हें नौकरी पर वापस क्यों नहीं रखा गया? उन्हें न सिर्फ नौकरी पर वापस लिया जाना चाहिए था बल्कि उन्हें पिछले 15 साल के वेतन आदि का भुगतान भी करना चाहिए था. लेकिन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. गौरतलब है कि 1993 से 2003 तक, यानी दस सालों तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री.

सब जगह से थक-हार कर निर्मल जैन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का दरवाजा खटखटाया. उस वक्त, एनएचआरसी के अध्यक्ष जस्टिस वेंकट चलैया थे. जस्टिस वेंकट चलैया ने उनकी सारी बातें सुनी और तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर निर्मल जैन की मदद करने को कहा. लेकिन, उन्हें कोई सहायता नहीं मिली. इसके बाद, निर्मल जैन फिर से एनएचआरसी पहुंचे. तब, एनएचआरसी के चेयरमैन जस्टिस जे एस वर्मा थे. उन्होंने भी दिग्विजय सिंह को पत्र लिखकर मदद देने को कहा. इसके बाद, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यालय की तरफ से निर्मल जैन को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए बुलाया गया. दिग्विजय सिंह ने निर्मल जैन से पूछा कि वह क्या चाहते हैं तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताईं और अपने इकलौते बेटे के लिए एक अदद नौकरी की मांग की. सीएम ने आवेदन देने को कहा. आवेदन दिया भी गया लेकिन न मदद मिली, न नौकरी.

साल 2002 में मध्य प्रदेश राज्य मानवधिकार आयोग और तत्कालीन राज्यपाल भाई महावीर के हस्तक्षेप से निर्मल जैन को बैंक में दोबारा नौकरी मिली. लेकिन, यह खुशी भी ज्यादा दिनों के लिए नहीं थी. उन्हें महज 3 हजार रुपये वेतन पर सिर्फ डेढ़ साल की नौकरी के बाद साल 2004 रिटायर कर दिया गया और पिछले 25 सालों का वेतन-भत्ता आदि मिला कर उन्हें महज 1 लाख 46 हजार रुपये मिले. दूसरी तरफ, उनके समकक्ष अधिकारियों को उनसे 4 गुना ज्यादा वेतन मिल रहा था. इस पूरी संघर्ष यात्रा में निमल जैन के इकलौते पुत्र और बेटी ने आत्महत्या कर ली. उनकी मां टीबी से ग्रसित हो कर स्वर्ग सिधार गईं. निर्मल जैन की पत्नी भी मानसिक और शारीरिक तौर पर हमेशा बीमार ही रहती हैं. बावजूद, इस सब के निर्मल जैन ने हिम्मत नहीं हारी. एक बार फिर वह साल 2012 में एनएचआरसी पहुंचे. उस वक्त जस्टिस बालाकृष्णन चेयरमैन थे. निर्मल जैन ने उनके सामने अपनी बातें फिर से रखीं. लेकिन, दुर्भाग्य कहिए या भारतीय न्याय व्यवस्था की विडंबना कि अपनी शिकायत लिखित में दर्ज कराने के बाद भी 30-7-2013 को निर्मल जैन को एनएचआरसी से एक पत्र मिलता है, जिसमें लिखा गया था कि आपकी शिकायत एनएचआरसी को मिली ही नहीं है. यानी, दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी अपील को खारिज कर दिया गया.

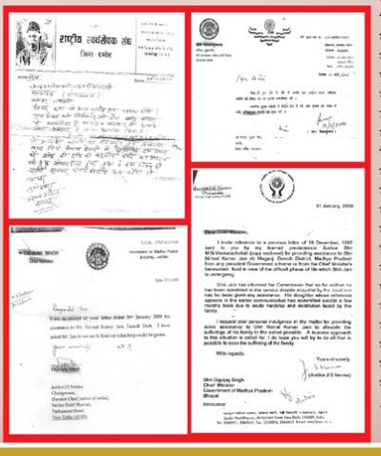

चौथी दुनिया से बात करते हुए, निर्मल जैन बताते हैं कि एक बार उन्हें मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मिला लेकिन अंतिम वक्त में उनसे मुलाक़ात नहीं हो सकी. सवाल है कि आरएसएस का एक इतना पुराना स्वयंसेवक जो आज भी गर्व से खुद को स्वयंसेवक बताता है, क्या संघ में उसकी पीड़ा को सुनने-समझने और मदद करने वाला कोई नहीं है. आज, संघ से ही निकले हुए कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री हैं. संघ के ही पुराने कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं. संघ आज देश की सबसे ताकतवर संस्था है. केंद्र समेत कई राज्य सरकारों में उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हस्तक्षेप है. फिर भी यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने एक कार्यकर्ता की दुर्दशा से परिचित नहीं है, उसकी पीड़ा को नहीं समझ रहा है, उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है तो इसे क्या कहेंगे. निर्मल जैन की इस कहानी को जानने के बाद आखिर कोई क्यों संघ का समर्पित कार्यकर्ता बनने की बारे में सोचेगा? ■

feedback@chauthiduniya.com

राजस्थान

अर्से तक दूर रहने के बाद फिर साथ आए राजस्थान के दो खांटी संघी

कहीं तो सध रही है सियासत!

सुनीता सिंह

राजस्थान की राजनीति में इन दिनों कुछ अलग तरह की सुगबुगाहट है. यह सुगबुगाहट पैदा हुई है संघ के दो पुराने स्वयंसेवकों के फिर से एक साथ आने को लेकर. दरअसल हुआ कुछ यूं है कि राज्य में ताकतवर राजनीतिक हैसियत रखने वाले गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया और एक जमाने में उनके विश्वस्त सहयोगी और करीबी मित्र विधायक घनश्याम तिवाड़ी एक बार फिर साथ आते दिखाई दे रहे हैं. इस राजनीतिक संभावना को बल तब मिला, जब मार्च के अंतिम सप्ताह में उदयपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की एक बैठक में भाग लेने के लिए प्रदेश की ये दोनों कद्दावर शख्सियतें न सिर्फ एक साथ, बल्कि एक ही गाड़ी से पहुंचीं. फिर क्या था, प्रदेश में सत्ताधारी दल के भीतर की राजनीति के एक बार फिर से करवट बदलने की सुगबुगाहट शुरू हो गई. आरएसएस के खांटी कार्यकर्ता घनश्याम तिवाड़ी राज्य की पिछली भाजपा सरकार में शिक्षामंत्री के रूप में न सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल थे, बल्कि अपनी काबीलियत और वाकपटुता से उन्होंने विरोधियों को भी मोहित कर रखा था. इससे पहले वह राज्य में भैरो सिंह शेखावत सरकार में भी बिजली मंत्री के पद रह चुके थे. लेकिन तिवाड़ी का खरापन उन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से दूर ले गया और धीरे-धीरे वह एक ऐसे गुट के नेता के रूप में स्थापित होने लगे, जो वसुंधरा विरोधी के रूप में जाना जाने लगा.

अब बात करते हैं मौजूदा गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया की. कटारिया मेवाड़ की राजनीति के बड़े नाम हैं. उदयपुर संभाग में उनका डंका बजता है. संभाग की आदिवासी आबादी समेत पूरे संभाग में कटारिया का बेहद सम्मान है. सादगीभरी राजनीति के साथ बेबाक टिप्पणी कटारिया के व्यक्तित्व की खासियत रही है. राजे के नेतृत्व में भाजपा की इससे पहले जो सरकार बनी थी, उसमें भी कटारिया को गृह मंत्रालय जैसा अहम विभाग मिला था. कटारिया भी खांटी संघी होने के साथ-साथ

गुलाबचंद कटारिया

घनश्याम तिवाड़ी

एक समय पार्टी के अंदर राजे विरोधी राजनीति की एकधुरी समझे जाते थे. पिछली राजे सरकार में गृहमंत्री रहते हुए गुर्जर आंदोलन से निपटने के तरीके को लेकर कटारिया का पार्टी के अंदर विरोध शुरू हुआ, ऐसे समय में मुख्यमंत्री का चुप्पी साधे रखना कटारिया को चुभ गया, लिहाजा यही बात कटारिया को भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से दूर ले जाने का कारण बनी.

कटारिया ने क्यों छोड़ा था तिवाड़ी का साथ

एक सवाल अक्सर कई लोगों के मन में उठता है कि आखिर तिवाड़ी और कटारिया के बीच ऐसा क्या हो गया कि कटारिया ने तिवाड़ी से अलग होने का फैसला किया? इसको लेकर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, उसमें से एक तो यही है कि कटारिया ने भी सहलियत की राजनीति को अपनाने का फैसला किया. दूसरी ओर सूत्रों की मानें तो कटारिया के पिछले कार्यकाल के दौरान सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर सीबीआई का दबाव उन्हें तोड़ गया और वह राजे के प्रभाव में आ गए.

इधर, तिवाड़ी ने नहीं बढ़ली राह

एक तरफ तो राजे गुट ने जहां कटारिया को साथ मिलाकर संघ समर्थक गुट को तगड़ा झटका दे दिया था, वहीं दूसरी तरफ खांटी संघी घनश्याम तिवाड़ी ने फिर भी अपनी राह नहीं बदली. राज्य विधानसभा के लिए हुए चुनाव में तिवाड़ी ने अन्य भाजपा उम्मीदवारों के मुकाबले ज्यादा मतों से अपनी सीट पर जीत हासिल की. यह जीत बेहद प्रभावशाली थी, लिहाजा यह माना जाने लगा कि इस बार भी राजे के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में तिवाड़ी को कोई न कोई महत्वपूर्ण पद जरूर दिया जाएगा, भले ही संघ इसके लिए दबाव बनाए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तिवाड़ी को न तो मंत्रिमंडल में स्थान मिला और न ही उन्हें संगठन में ही कोई अहम जिम्मेदारी दी गई. पिछले दो-ढाई साल के दौरान तिवाड़ी को एक तरह से अलग-थलग रखने की कोशिश ही की गई.

अपनी ही सरकार को घेरते रहे तिवाड़ी

राजे के रुख से पहले से ही नाराज घनश्याम तिवाड़ी कमजोर हो चुके विपक्ष यानी कांग्रेसी विधायकों की अपेक्षा खुद ही एक सक्षम विपक्ष की भूमिका में उतर आए और उन्होंने विधानसभा में कई मसलों पर अपनी ही सरकार को घेर लिया. फिर चाहे वह इस बार का राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान संस्कृत के गलत श्लोक पढ़ने का मामला हो या विद्युत वितरण प्रबंध उत्तरदायित्व बिल-2016 का मामला हो अथवा जयपुर सहित राजस्थान के अनेक इलाकों में मंदिरों को तोड़े जाने का मामला हो, तिवाड़ी ने अपनी ही सरकार को नाकों चने चबवा दिए. राजे के संकट मोचक कहे जाने वाले राजेंद्र राठौड़ के भी सदन के अंदर तिवाड़ी को संभालने में पसीने छूट गए.

कटारिया भी हुए नाराज

यही वह दौर रहा, जब कई कारणों से राज्य के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया भी कुछ अनमने से हो गए. चुनाव के समय और जीत के बाद भले ही वह राजे के साथ समारोहों में दिखते हों और मुख्यमंत्री भी उन्हें बेहद सम्मान देती दिखाई देती हों, लेकिन कटारिया का संघ का करीबी होना राजे समर्थकों को अखर भी रहा था. इसी दौरान कुछ ऐसी बातें भी हुईं, जिनसे कटारिया खिन्न से रहने लगे. मसलन पुलिस महकमे का प्रभारी मंत्री होने के नाते जिन चीजों पर उनका नियंत्रण होना चाहिए था, वहां भी सीधा हस्तक्षेप राजे और उनके समर्थकों का रहने लगा. ट्रांसफर-पोस्टिंग जैसे मसलों में भी कटारिया का जैसे कोई लेना-देना ही नहीं रहा. इस दौरान कटारिया अक्सर अपने भाषणों में और कई बार तो पुलिस महकमे के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक के दौरान भी यह उल्लेख करते दिखाई दिए कि राज्य की पुलिस ज़मीन-जायदाद के मामलों में उलझकर भ्रष्टाचार के कोढ़ से पीड़ित होती जा रही है. उनकी खिन्नता बढ़ती ही जा रही थी.

गैंगस्टर आनंदपाल प्रकरण से लकीर हुई गहरी

इसी दौरान कुख्यात अपराधी गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का फरारी प्रकरण हुआ, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों निशाने पर रहे कटारिया को घेरने की जबरदस्त कोशिशें हुईं. सूत्रों की मानें, तो कटारिया को यहां यह बात चुभ गई कि जब वे इस मामले में घिरते नज़र आए, तो न तो राजे के रणनीतिकारों राजेंद्र राठौड़ (संसदीय कार्यमंत्री) और मदन राठौड़ (मुख्य सचेतक) ने उनका साथ दिया और न ही खुद राजे ही मजबूती से उनके साथ खड़ी दिखाई दीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

महबूबा मुफ़्ती की दोहरी परीक्षा

भाजपा के साथ सफ़र आसान नहीं होगा

हारुन रेशी

महबूबा मुफ्ती और उनके मंत्री परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में आशा के विपरीत भाजपा के किसी भी नेता ने भारत माता जी जय का विवादास्पद नारा नहीं लगाया. हालांकि उमर अब्दुल्लाह से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा तक कई लोगों ने भाजपा को इसके लिए उकसाया था. लेकिन सियासी गलियारों में यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर दो परस्पर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां कब तक फर्जी दोस्ती और एकता का प्रदर्शन कर पाएंगी?

जहां तक पीडीपी का सवाल है तो उसे अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए और कश्मीर में अपनी साख बनाए रखने के लिए उस राजनीतिक विचारधारा को मजबूती प्रदान करनी होगी जिसकी वजह से जनता ने उसे वोट दिया था और पीडीपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई थी. पीडीपी की बुनियाद ही कश्मीरी मुसलमानों की भावनाओं को उभारकर रखी गई थी. वर्ष 1999 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस छोड़कर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी(पीडीपी) की स्थापना की थी तब उन्होंने कहा था कि वह दरअसल कश्मीर मसले के शांतिपूर्ण हल और राज्य में स्थाई शांति स्थापित करने के लिए इस पार्टी का गठन कर रहे हैं. तीन साल बाद साल 2002 में जब पीडीपी कांग्रेस के सहयोग से पहली बार सत्ता में आई और मुफ्ती मोहम्मद सईद पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री बने. इसके बाद उन्होंने श्रीनगर से सटे गंदरबल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मिलिटेंटों को अब जंगलों से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि उनके प्रतिनिधि अब विधानसभा में आ गए हैं. इस शासनकाल में पीडीपी ने कश्मीर मसले के शांतिपूर्ण हल के लिए सेल्फ-रूल के नाम का एक दस्तावेज़ तैयार किया था. पीडीपी का कहना है कि सेल्फ-रूल एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे अमल में लाने पर कश्मीर समस्या का समाधान होगा और राज्य में स्थाई शांति स्थापित होगी. इस सेल्फ-रूल फॉर्मुले में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ के कश्मीर यानी पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर और भारतीय कश्मीर में संयुक्त मैकेनिज्म के तहत एक साझा हुकूमत बनाने और इस क्षेत्र में दोहरी करेंसी यानी एक साथ भारतीय और पाकिस्तानी मुद्रा को मान्यता देने की बात की गई है. पीडीपी ने वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में अन्य वादों के साथ-साथ सेल्फ-रूल फॉर्मुले को अमल में लाने, जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा दिलवाने, संविधान की धारा-370 को उसके वास्तविक रूप में लागू करने जैसे वादे किए थे. इतना ही नहीं पीडीपी के नेताओं ने अलग-अलग जनसभाओं में कहा था कि यदि राज्य में बीजेपी के आक्रमण को रोकना है तो आपको पीडीपी को वोट देना पड़ेगा. यह है पीडीपी की वह छवि जिसकी बुनियाद पर कश्मीरी जनता ने उसे वोट दिया और उसे विधानसभा की 27 सीटें हासिल हुईं.

इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर के बारे में भाजपा का नज़रिया बिलकुल अलग है. भाजपा ने जम्मू में धर्म के नाम पर वोटरों को लुभाते हुए उनसे वादा किया था कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सबसे पहले धारा-370 को ख़त्म किया जाएगा, राज्य में हिंदू मुख्यमंत्री बनेगा, कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से शहर बनाए जाएंगे और वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थियों को राज्य की नागरिकता का प्रमाणपत्र दिया जाएगा. भाजपा के इन नारों की वजह से जम्मू में हिंदुओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, इस वजह से भाजपा को यहां 25 सीटें हासिल हुईं. ज़ाहिर है अगर भाजपा को इस वोट बैंक की हिफाज़त करनी है तो उसे इन मुद्दों पर बोलना उसकी मजबूरी है.

पीडीपी-भाजपा सरकार गठन के समय मुफ्ती मोहम्मद सईद ने स्वयं कहा था कि आज दो ध्रुवों (नॉर्थ पोल और साउथ पोल) का संगम हो गया है. लेकिन सच तो यह है कि सरकार गठन होने के दिन से ही यह सरकार विवादों में घिरी रही. 01 मार्च 2015 को शपथ ग्रहण के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने एक विवादस्पद बयान दिया जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए मिलिटेंटो और हुर्रियत नेताओं का शुक्रिया अदा किया था. उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने संसद में हंगामा किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री राजनाथ सिंह को उनके बयान से खुद को अलग करना पड़ा. इसके बाद दस महीने तक चली यह सरकार लगातार विवादों में घिरी रही. भाजपा नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के झंडे को सम्मान देने से इंकार कर दिया. राज्य में बीफ पर पाबंदी लगाने की मांग की और संविधान की धारा-370 को खत्म करने की बातें की. जिसकी वजह से कश्मीर घाटी में जनता के बीच पीडीपी की हालत हास्यास्पद हो गई. लोग उसे कश्मीर विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन बनाने के लिए ताने मारने लगे. राजनीतिक समीक्षक ज़रीफ अहमद ज़रीफ कहते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की आखिरी रस्म में महज 2000 लोगों का शामिल होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि भाजपा के साथ गठबंधन करने की वजह से पीडीपी की साख को धक्का पहुंचा है. ज़रीफ ने चौथी दुनिया को बताया कि जब लोगों ने यह देखा कि मुफ्ती भाजपा के सामने भीगी बिल्ली बन गए और इश स्थिति में पहुंच गए कि मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनके पास राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का भी अधिकार नहीं था. इसके अलावा वह भाजपा के मंत्रियों और नौकरशाहों से जम्मू और कश्मीर के झंडे को सम्मान भी नहीं दिलवा सकते, इस वजह से मुफ्ती के प्रति उनकी नाराज़गी बढ़ गई.

अब जब महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार का गठन हो गया है तो लोगों का यह मानना है कि भाजपा-पीडीपी द्वारा लाख एहतियात बरतने के बावजूद यह सरकार विवादों से नहीं बच सकती. कश्मीर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर नूर बाबा ने इस विषय पर चौथी दुनिया से बात करते हुए कहा कि यह असंभव लगता है कि गठबंधन सरकार अगले पांच साल तक बिना किसी विवाद के चल सकेगी. दोनों पार्टियां जितनी भी एहतियात बरतें, लेकिन सियासी फायदे के लिए दोनों पार्टियों को कुछ ऐसी बातें मजबूरन कहनी पड़ेंगी जो कि एक-दूसरे के हितों के खिलाफ होंगी.

सबसे दिलचस्प बात यह है कि महबूबा मुफ्ती के सामने सिर्फ भाजपा के साथ समन्वय बनाने और बिना किसी विवाद के सरकार चलाने की चुनौती नहीं है, बल्कि उनके सामने सबसे बुनियादी चुनौती अपनी पार्टी के नेताओं को काबू में रखने की है. यह बात अब खुलकर सबके सामने आ चुकी है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद जब महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए सरकार बनाने से इंकार किया और दोनों दलों को दोबारा सरकार गठित करने में तीन महीने लगे, इस दौरान भाजपा ने पीडीपी के तीन बड़े नेताओं अल्ताफ बुख़ारी, हसीब दर अबू और नईम अख्तर को बरगलाने की कोशिश की ताकि महबूबा मुफ्ती को ही पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए. इस बात की पुष्टि पार्टी के संस्थापक सदस्य और सांसद तारिक कुर्रा ने की. कुर्रा ने विरोध जताते हुए शपथ ग्रहण सामरोह में भाग नहीं लिया. बाद में उन्होंने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने महबूबा मुफ्ती को यह जानकारी दी थी कि ये तीन लोग उनके ख़िलाफ साजिश कर रहे थे. कुर्रा इस बात से नाराज़ हैं कि इसके बावजूद महबूबा ने उनमें से दो को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया है.

राज्य के राजनीतिक हल्कों यह बात जोर पकड़ रही है कि महबूबा पार्टी के बड़े नेताओं को काबू में रखने के लिए पार्टी में मुफ्ती परिवार का वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं. इस बात के इशारे भी दिए जा चुके हैं कि महबूबा मुफ्ती के मुख्यमंत्री बनने के बाद खाली हुई अनंतनाग संसदीय सीट से उनके भाई असहुक मुफ्ती चुनाव लड़ेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक महबूबा के मामा सरताज मदनी को पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. इसके अलावा महबूबा ने अपने मंत्रिमंडल में अपने करीबी रिश्तेदार फारूक़ अनदराबी को भी शामिल किया है. लेकिन यह देखना बेदह रोचक होगा कि पार्टी पर मुफ्ती परिवार का असर बढ़ने का पार्टी के वरिष्ठ नेता किस तरह अपनी प्रतिक्रिया देते हैं. तारिक हमीर कुर्रा पहले ही यह साफ कर चुके हैं कि एक लोकतांत्रिक पार्टी में नेताओं का चुनाव और पदों का बटवारा लोकतांत्रिक तरीके से और राजनीतिक सिद्धांतों के मुताबिक ही होना चाहिए. कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पार्टी में मुफ्ती परिवार का वर्चस्व पढ़ने से पार्टी बिखर सकती है. जाहिर है कि ऐसी परिस्थिति में महबूबा मुफ्ती के सामन दोहरी चुनौती है. यदि महबूबा भाजपा के साथ कदम मिलाने के साथ पार्टी में संतुलन बनाने में सफल होती हैं तो यकीनन वह जम्मू -कश्मीर की एक बड़ी नेता बनकर उभरेंगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

देश काल से परे का एक अद्भुत अनुभव जो आता है बारह वर्षों में
उज्जैन तैयार है
श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए।
मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी
www.simhasthujjain.in /SimhasthUjjain2016 /Simhasth

बहस

अल्लाह नहीं मुल्ला का क़ानून है मुस्लिम पर्सनल लॉ

शरिया अदालतों में बैठे ज़्यादातर लोग न तो जज बनने की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और न ही उनके पास क़ानूनी समझ है. इन अदालतों में लोगों का रसूख़ देखकर मनमाने फैसले कराए जाते हैं. यह परंपरा ख़त्म होनी चाहिए. मुसलमानों को भी यह बात समझनी चाहिए कि जब हम क्रिमिनल मामलों और बाक़ी तमाम मामलों में देश की अदालतों के फैसले मानते हैं तो फिर शादी, तलाक़ और विरासत से जुड़े निजी मामलों में अदालत के फैसले मानने पर आपत्ति क्यों हो...?

यूसुफ़ अंसारी

तलाक के तीन मामलों में सुप्रीम कोर्ट और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बीच की खींचतान के बीच कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट करके ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड से सवाल पूछा है कि क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरियत संविधान से ऊपर है. लेकिन बोर्ड तो पहले ही कई बार कह चुका है कि सुप्रीम कोर्ट को शरियत की समीक्षा का अधिकार नहीं है. क्योंकि ये क़ुरान की रोशनी में बना अल्लाह का क़ानून है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद इस मालमे में सुप्रीम कोर्ट में बाक़ायदा हलफ़नामा दायर करके तलाक़ के तीन मामलों में पार्टी बन गया है. उसका भी यही कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ क़ुरान पर आधारित अल्लाह का क़ानून है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद 1986 के बहुचर्चित शाह बानो केस में भी पार्टी बना था. नतीजा सबके सामने है.

दरअसल बोर्ड और जमीयत उलेमा-ए-हिंद झूठ बोल रहे हैं. सच्चाई तो यह है कि भारत में लागू शरियत अल्लाह का नहीं बल्कि मुल्ला का बनाया हुआ क़ानून है. इसके कई प्रावधान क़ुरान की आयतों के उलट और इसकी मूल भावना के ख़िलाफ़ है. कई प्रावधान महिलाओं और यतीमों को उनके अधिकारों से वंचित करते हैं. यह क़ानून सूरः निसा की आयत नंबर 35 में वर्णित तलाक़ की पूर्व शर्त आर्बिट्रेशन के ज़रिए आपसी सहमति बनाने की कोशिश किए बग़ैर ही तलाक को मान्यता दे देता है. क़ुरान की सात सूरतों में तलाक़ से संबंधित कुल 44 आयते हैं. इनमें तलाक़ का तरीक़ा एकदम साफ़-साफ़ बताया गया है. इसके मुताबिक़ अगर पति-पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं हैं और तलाक़ की नौबत आती है तो पहले दोनों की तरफ़ से एक-एक वकील तय होगा. दोनों मिलकर पति-पत्नी के बीच सुलह कराने की कोशिश करेंगे. सुलह की कोई सूरत न होने पर पति पत्नी को तलाक़ देगा. तलाक़ माहवारी ख़त्म होने पर पाकी की हालत में दी जाएगी. तलाक़ के बाद पति-पत्नी का अलग-अलग बिस्तर होगा. इस तलाक़ की इद्दत तीन महीने दस दिन या तीन माहवारी तक होगी. इस बीच अगर दोनों में सुलह हो जाए तो तलाक़ ख़त्म हो जाएगा. अगर सुलह नहीं होती है तो दो विकल्प हैं. पहला, या तो पति पत्नी को रोक ले यानी उससे निकाह कर ले या फिर दूसरा, उसे तलाक़ देकर विदा कर दे. इस पर भी इद्दत की अवधि में सुलह करने और इद्धत के बाद दोनों को आपस में निकाह करने का अधिकार है. (सूरः बक़र आयत न. 228 और 232) लेकिन तीसरी बार तलाक़ देने के बाद निकाह की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी. ऐसी सूरत में दोनों तभी निकाह कर सकते हैं जब औरत पहले किसी और से निकाह कर ले और उसका शौहर मर जाए या फिर उसे तलाक़ दे दे. (सूरः बक़र आयत न. 230) यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके दूसरे शौहर को भी उसे दो बार तलाक़ देकर फिर से निकाह करने का अधिकार है. लिहाज़ा दोनों के बीच शादी का रास्ता एक हद तक बंद होता है. इसीलिए क़ुरान साफ़ कहता है तलाक़ दो बार है. (सूरः बक़र आयत न. 229) मगर अफ़सोस की बात यह है कि हमारे समाज ने इसी आयत का सहारा लेकर हलाला जैसी बिदअत(कुरीति) को आम बना दिया. वास्तव में हलाला तलाक पाई बेबस औरत पर किया गया सबसे घटिया दर्जे का अपराध है. हलाला मुस्लिम समाज में एक लानत बन चुका है, मगर तमाम मुल्ला बेशर्मी के साथ इसकी न सिर्फ़ वकालत करते हैं बल्कि कई बार ख़ुद को ही एक रात का दूल्हा बनाकर पेश कर देते हैं. ये क़ुरान के साथ मज़ाक़ ही नहीं बल्कि खुल्लम-खुल्ला खिलवाड़ है.

भारतीय शरियत क़ानून यतीम पोते को दादा की विरासत में हिस्सा नहीं देता. यह क़ानून कहता है कि अगर बाप की मौजूदगी में बेटा मर जाए तो उसका हिस्सा पोते-पोती को नहीं मिलेगा. ऐसी स्थिति में पोते-पोती (यतीम बच्चे) महज़ूब हो जाएंगे. महज़ूब होने का मतलब महरूम यानि वंचित होने से ही है. जबकि अल्लाह ने यतीमों का हक़ मारने वालों की जगह जहन्नुम बताई है. (सूरः निसा आयत न.8-10) अल्लाह की इतनी सख़्त हिदायत के बावजूद मुल्लाओं ने यतीमों का हक़ मारने का रास्ता भी निकाल लिया है. देश में इस क़ानून की शिकार लाखों मुस्लिम औरतें अपने यतीम बच्चों के हक़ के लिए दर-दर की ठोकरें खाती घूम रही हैं. लेकिन दिन में सैकड़ों बार बिस्मिल्ला हिर्हमान हिर्हीम पढ़कर अल्लाह के कृपालु और दयालु होने की गवाही देने वाले मुल्लाओं को न तलाक़ की मारी बेबस औरतों पर दया आती है और न ही बेवा होने पर यतीम बच्चों के साथ सुसराल से निकाल दी गई औरतों पर. यतीम बच्चों की हक़ तल्फ़ी पर भी इनका दिल नहीं पसीजता. ऊपर से तुर्रा यह है कि मुल्लाओं ने धनवान मुसलमानों को भी यह समझा दिया है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या फिर इतनी ही क़ीमत की ज़मीन या घर है उसे ज़कात देना भी जायज़ नहीं है. धनवान मुसलमानों से ज़कात का ज़्यादातर पैसा मुल्ला मदरसों रहने वाले यतीम बच्चों के लिए वसूल लेते हैं लेकिन वह पैसा उन तक पहुंचता ही नहीं है. उन बेचारों को तो दो वक़्त की रोटी मिल जाए तो ग़नीमत है. उन बच्चों का संरक्षक बनकर मुल्ला ख़ुद ही सारा पैसा हड़प लेते हैं. ज़कात के पैसों से ही ये अपनी निजी मिल्कियत की तरह मदरसे की आलीशान इमारत और अपना निजी महल खड़ा करते हैं. परिवार का पेट भी उसी ज़कात के पैसे से पालते हैं. और यह सब होता है अल्लाह के हुक्म यानी क़ुरान की आयतों के ख़िलाफ़ (सूरः निसा आयत न. 1-2 और 6). इसमें सबसे शर्मनाक बात तो यह है पढ़े लिखे मुसलमानों ने भी मुल्लागर्दी की आधीनता स्वीकार कर रखी है. ऐसे सामाजिक मुद्दों पर समाज के भीतर से कभी कोई मज़बूत आवाज़ नहीं उठती. कभी कभार कोई कोशिश करता भी है तो उसके ख़िलाफ़ कुफ़्र के फ़तवे की तलवार म्यान से बाहर आ जाती है. इस पर तथाकथित मुस्लिम बुद्धिजीवी भी गर्दन झुकाकर और आंखे नीची करके मुल्लाओं की हां में हां मिलाते नज़र आते हैं. तथाकथित सेकुलर राजनीतिक दलों को मुसलमानों का वोट चाहिए, लिहाज़ा वो क्यों बर्र के छत्ते में पत्थर मारेंगे. कभी कभार संघ परिवार, बीजेपी, या फिर सुप्रीम कोर्ट बोलता है तो इसे शरियत और क़ौम के निजी मामलों में दख़ल बताया जाता है. इसके बाद इस्लाम ख़तरे में होने का हौव्वा ख़ड़ा करके मुसलमानों के भावनात्मक शोषण का खेल शुरू होता है.

ग़ौरतलब है कि भारत में मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ अनुप्रयोग अधिनियम-1937 से शासित होते हैं इसके तहत शादी, मेहर, तलाक़, रख-रखाव, उपहार, वक़्फ़ और विरासत के मामलों में उनके परंपरागत निजी क़ानूनों को मान्यता मिली हुई है. लेकिन ये क़ानून स्पष्ट और संहिताबद्ध नहीं हैं. अदालतों में सारी बहस क़ुरान की आयतों, परस्पर विरोधी हदीसों के हवालों और सदियों पुराने फतवों केआधार पर होती है. जजों को भी फ़ैसला करने में परेशानी होती है. इसलिए कभी-कभी ऐसे फैसले भी आ जाते हैं जिन्हें इस्लाम विरोधी कहकर बवाल मचाया जाता है. 1986 में आए शाह बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर मचे बवाल ने तात्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार को संसद में बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया था. उस वक्त राजीव गांधी की कैबिनेट में मंत्री रहे आरिफ़ मोहम्मद ख़ान ने सरकार के इस क़दम का पुरज़ोर विरोध किया था. लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई. तब संघ परिवार ने कांग्रेस पर मुल्लाओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया था. इससे हिंदू समाज में उपजी नाराज़गी को शांत करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया. उसके बाद क्या हुआ, किसे नहीं पता...? एक ग़लत फैसले का ख़ामियाज़ा देश आज तक भुगत रहा है. लेकिन आज पी. चिदंबरम और दिग्विजय सिंह जैसे कई दिग्गज कांग्रेसी नेता क़ुबूल कर चुके हैं कि शाह बानो मामले में तात्कालीन सरकार का फैसला ग़लत था.

जम्मू-कश्मीर में 2007 में ही वहां की विधानसभा ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े दीवानी मामलों को सुलझाने के लिए एक विधेयक पास करके क़ानून बना दिया. यह क़ानून राज्य के सभी फिरक़ों और सोच वाले मुसलमानों पर समान रूप से लागू होता है. अगर यह काम जम्मू-कश्मीर की विधानसभा कर सकती है तो देश की संसद ऐसा क्यों नहीं कर सकती.

हैरानी की एक और बात यह है कि देश में मुसलमानों के लिए शादी का कोई क़ानून नहीं है. लेकिन शादी तोड़ने के लिए मुस्लिम विवाह विच्छेदन अधिनियम-1939 मौजूद है. यह क़ानून मुस्लिम महिलाओं को अपने पति से तलाक़ लेने का अधिकार देता है. इसके तहत महिलाओं को तलाक़ लेने के 9 आधार दिए गए हैं. यहां यह सवाल पैदा होता है कि अगर गुज़ारा भत्ते से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बदलने के लिए देश की संसद क़ानून बना सकती, तलाक़ के लिए क़ानून बन सकता है तो फिर शादी, विरासत, वक़्फ़ और बाक़ी मामलों के लिए संसद में क़ानून क्यों नहीं बन सकता...? जवाब थोड़ा तीखा है. इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि इससे भोले भाले मुसलमानों पर चल रही मुल्लाओं की हुकूमत पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी. सारे मामले अगर अदालतों में तय होने लगेंगे तो फिर मुल्लाओं को कौन पूछेगा. उनकी भूमिका तो सिर्फ मस्जिद में नमाज़ और मदरसों में बच्चों को पढ़ाने तक ही सीमित होकर रह जाएगी.

दरअसल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल का विरोध करने वाले अन्य मुस्लिम संगठनों की असली चिंता इस्लाम और मुसलमानों को बचाने की नहीं बल्कि अपनी दुकानों को बचाने की है. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लंबे अरसे से हर ज़िले में एक शरिया अदालत गठित करने, इन्हें क़ानूनी मान्यता देने और इन अदालतों में फैसले करने वाले मुफ्तियों और आलिमों को जज का दर्ज़ा देने की मांग कर रहा है. लेकिन बोर्ड की शरिया अदालतों में बैठे ज़्यादातर लोग न तो जज बनने की शैक्षिक योग्यता रखते हैं और न ही उनके पास क़ानूनी समझ है. इन अदालतों में लोगों का रसूख़ देखकर मनमाने फैसले कराए जाते हैं. यह परंपरा ख़त्म होनी चाहिए. मुसलमानों को भी यह बात समझनी चाहिए कि जब हम क्रिमिनल मामलों और बाक़ी तमाम मामलों में देश की अदालतों के फैसले मानते हैं तो फिर शादी, तलाक़ और विरासत से जुड़े निजी मामलों में अदालत के फैसले मानने पर आपत्ति क्यों हो...?

जम्मू-कश्मीर में 2007 में ही वहां की विधानसभा ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े दीवानी मामलों को सुलझाने के लिए एक विधेयक पास करके क़ानून बना दिया. यह क़ानून राज्य के सभी फिरक़ों और सोच वाले मुसलमानों पर समान रूप से लागू होता है. अगर यह काम जम्मू-कश्मीर की विधानसभा कर सकती है तो देश की संसद ऐसा क्यों नहीं कर सकती. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अड़ियल रवैया छोड़कर देश-दुनिया के क़ानूनी जानकार और क़ुरान व हदीसों के जानकारों की कमेटी बनाकर शादी, तलाक़, मेहर, गुज़ारा भत्ता, विरासत, गोद लेना और वक़्फ़ जैसे मसलों पर पुख्ता क़ानून का मसौदा तैयार करके संसद को सौंप देना चाहिए. इसके बाद संसद से पास होने वाला क़ानून सभी फिरक़ों के मुसलमानों पर समान रूप से लागू होगा. एक इस्लाम और एक क़ुरान पर यक़ीन रखने वाले मुसलमान आख़िर सबके लिए एक क़ानून पर राज़ी क्यों नहीं होंगे...? अगर इस्लाम औरतों, मज़लूमों और यतीमों को उनका हक़ देने की बात करता है तो शरियत में इसकी झलक भी दिखनी चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भाजपा वन मैन शो बन गई है

कश्मीर में क्या हो रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वह देशद्रोही है. यह निरर्थक बात है. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जय हिन्द बोला करते थे. नेताजी बोस इन लोगों के पसंदीदा नेता हैं. इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने आज़ाद हिन्द फ़ौज का नाम दिया था. उन्होंने उर्दू का इस्तेमाल किया था. उन्होंने अपनी सेना को हिंदी में स्वतंत्र भारत सेना नहीं कहा था. जय हिन्द का नारा उन्होंने दिया था, जिसे कांग्रेस ने अपनाया है. अगर भाजपा भारत माता की जय कहती है तो इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है. लेकिन चूंकि आज आप सत्ता में हैं तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि हर किसी को भारत माता की जय कहना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि कल कांग्रेस सत्ता में आती है और वह भी यह कहने लगे कि सबको जय हिन्द कहना पड़ेगा. यह कैसा बचकाना तर्क है.

आखिरकार एनडीए और भाजपा ने वैसी राजनीति करने का फैसला कर ही लिया जिसे हम भारत में देखते आए हैं. फिलहाल उन्होंने अपनी सरकार बनाने के लिए प्रतिद्वंद्वी खेमे के विधायकों को तोड़ने का खेल शुरू कर दिया है. यह खेल अरुणाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक खेला गया. अब उनकी उत्तराखंड पर नज़र है. दरअसल, इसमें दो समस्याएं हैं. पहली, अगर भाजपा ने यह समझ लिया है कि भारतीय लोकतंत्र के काम करने का यही तरीका है तो उसने दिल्ली में ऐसा क्यों नहीं किया? जबकि उसके पास 31 विधायक थे और उसे सरकार बनाने के लिए केवल पांच विधायकों की आवश्यकता थी. अगर उसने वहां ऐसा करके सरकार बना ली होती तो केजरीवाल का कहीं नाम नहीं होता. ऐसा करने के बजाए उसने यह दिखाने की कोशिश की कि हम सबसे अलग (अच्छी) पार्टी हैं. हम किसी दूसरी पार्टी में तोड़-फोड़ नहीं करेंगे. हम चुनाव लड़ेंगे. दरअसल उस वक्त उन्होंने उच्च नैतिक आचरण धारण कर रखा था. इसका नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल ने उनका सफाया कर दिया.

उन्हें यह समझना चाहिए कि विपक्ष से लोगों को तोड़कर सरकार बनाना जनता को पसंद नहीं है. बहरहाल, पूर्वोत्तर के राज्य कमजोर हैं और उन्हें केंद्र सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है भले ही कोई भी पार्टी केंद्र की सत्ता में हो. लिहाज़ा जब एनडीए/भाजपा सत्ता में हैं तो पूर्वोत्तर के तमाम राज्य आपकी झोली में आ जाएंगे. आप आसानी से वहां सरकार गिरा सकते हैं और अपनी सरकार बना सकते हैं. ऐसा करने से आप की पार्टी मज़बूत नहीं होगी. अगर आप समझते हैं कि अधिक संख्या में राज्यों में सरकार आपको मज़बूत बनाएगी तो यह आपकी भूल है, क्योंकि बड़े राज्यों में आम लोगों के बीच लोकप्रियता महत्वपूर्ण होती है.

उत्तराखंड में जो कुछ हुआ वह बहुत बुरा है क्योंकि यदि किसी को सोमवार को सदन के पटल पर बहुमत साबित करना है और आप रविवार को वहां राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं तो इसे नैतिक, क़ानूनी और संवैधानिक तौर पर एक बेढंगा फैसला माना जाएगा. संसद का सत्र चल रहा था. यह सत्र के बीच की अवधि थी. राष्ट्रपति शासन लगाकर उनका बजट पास करने के लिए संसद स्थगित (प्रोरोग) कर दी गई ताकि अध्यादेश जारी किया जा सके. यह बेढंगेपन की इंतहा है. भारत में शासन करने का यह तरीका नहीं हो सकता. मुझे प्रधानमंत्री के सलाहकारों पर दया आ रही है कि वे उन्हें अच्छी सलाह भी नहीं दे सकते.

हर पार्टी दूसरी पार्टी में तोड़-फोड़ करती है, इसलिए आप भी कर सकते हैं. लेकिन यदि यह काम आप अभी कर रहे हैं तो आपने दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बनाई? दिल्ली चुनाव में आपने किरण बेदी, जो कि एक आउटसाइडर थीं उन्हें मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट किया. इसलिए मैं नहीं समझता कि भाजपा में सबकुछ सुव्यवस्थित है. ऐसा लगता है कि वहां चीज़ों पर गहन सोच-विचार नहीं हो रहा है. मुझे याद है कि आडवाणी, वाजपेयी, जसवंत सिंह, मुरली मनोहर जोशी जैसे लोगों के पास चीजों से निपटने का अपना तरीका था. अब तो लगता है कि पार्टी बन-मैन शो बनकर रह गई है. आप चाहें तो इसमें अमित शाह को भी शामिल कर सकते हैं. भाजपा किस राह पर जाएगी इसके लिए वह भी किसी तरह की रणनीति बनाने में असमर्थ है. अमित शाह भाषण दे रहे हैं कि लोगों को अगले पच्चीस वर्षों तक भाजपा को चुनने के लिए अपना मन बना लेना चाहिए. वह कह क्या रहे हैं? भारत एक ऐसा देश नहीं है जो कल ही पैदा हुआ हो. इसका इतिहास और संस्कृति काफी पुरानी है. इसे समझे बगैर भारत पर शासन करना असंभव है.

आप चुनाव जीतकर सरकार बना सकते हैं, जैसा कि आपने किया. इसके बाद बाद दो वर्ष गुज़र चुके हैं जो बेहद उत्साहजनक नहीं रहे हैं, इसलिए पहली बात जिसपर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए वह यह है कि उनकी आगे की रणनीति क्या हो. जब उनकी आलोचना होती है, तब वह कहते हैं कि कांग्रेस ने भी ऐसा किया है. ऐसे में यह सवाल उठ सकता है कि क्या वे कांग्रेस की खराब नकल मात्र हैं. इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आप कांग्रेस का सम्मान कर रहे हैं.

दूसरा मुद्दा. कश्मीर में क्या हो रहा है? एक तरफ आप कहते हैं कि जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा वह देशद्रोही है. यह निरर्थक बात है. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जय हिन्द बोला करते थे. नेताजी बोस इन लोगों के पसंदीदा नेता हैं. इंडियन नेशनल आर्मी को उन्होंने आज़ाद हिन्द फ़ौज का नाम दिया था. उन्होंने उर्दू का इस्तेमाल किया था. उन्होंने अपनी सेना को हिंदी में स्वतंत्र भारत सेना नहीं कहा था. जय हिन्द का नारा उन्होंने दिया था जिसे कांग्रेस ने अपनाया है. अगर भाजपा भारत माता की जय कहती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है. लेकिन चूंकि आज आप सत्ता में हैं तो आप यह नहीं कह सकते

प्रधानमंत्री अपनी क्षमता के मुताबिक ठीक-ठाक काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री सऊदी अरब और ईरान से रिश्ते सुधारने की पहल कर रहे हैं, जो ठीक है. लेकिन पाकिस्तान एक समस्या है और यह समस्या रहेगी. हाल ही में उसने अपनी संयुक्त जांच टीम यहां भेजी. इसके बाद वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि यहां उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिला. वे यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जांच के लिए केवल 55 मिनट का समय मिला. इससे कुछ भी हल नहीं होगा. यशवंत सिन्हा और दूसरे लोगों की तरफ से जो सुझाव आए हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत बंद कर देनी चाहिए, मुझे ठीक लगता है. चीजों को ठंडा हो जाने दिया जाए, थोड़ा इंतज़ार किया जाए, क्योंकि इस मामले में बहुत अधिक विकल्प नहीं हैं. अगर दो पड़ोसी देश समृद्ध होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने रिश्ते अच्छे करने होंगे. लेकिन जिस तरह वे आगे बढ़ रहे हैं वह ठीक नहीं है.

हैं कि हर किसी को भारत माता की जय कहना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि कल कांग्रेस सत्ता में आती है और वह भी यह कहने लगे कि सबको जय हिन्द कहना पड़ेगा. यह कैसा बचकाना तर्क है. यह मूर्खतापूर्ण काम है.

एक दूसरी चरमपंथी पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाना इस मुर्खता में इज़ाफे की तरह है. दरअसल यह राजनीतिक स्वार्थ है, क्योंकि पीडीपी ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में कहा था कि अफज़ल गुरु की फांसी गलत थी. आप ऐसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार क्यों बना सकते हैं? क्योंकि आप वहां पैसे की लूट में हिस्सा लेना चाहते हैं. आप अपनी कलई इस तरह खोल रहे हैं जैसे कांग्रेस ने भी नहीं खोली थी. आपको अच्छी तरह मालूम है कि चंद मंत्री पद लेकर या महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनाकर आप कश्मीर या कश्मीरी जनता के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते. यह सत्ता का खेल है. चुनावी नतीजों ने त्रिशंकु जनादेश दिया और आपने पीडीपी के साथ सरकार बनाई, लेकिन नतीजे आपके सामने हैं. कश्मीर में छात्रों की समस्या सुलझाने के लिए आप क्यों नहीं गए? आपने पुलिस को क्यों भेजा? यदि पुलिस और सेना भारत में गवर्नेंस के लिए ज़िम्मेदार हैं तो चुनाव और राजनीति की जरूरत क्या है? लोकतंत्र खत्म हो गया! देश के हर कोने में पुलिस अपना काम कर रही है. वह अच्छी, बुरी, उदासीन, भ्रष्ट जैसी भी हो. पुलिस या सेना समस्या का हल नहीं हो सकती. समस्या का हल राजनेता होगा जिसे जनता का जनादेश मिला है.

कश्मीर में वे ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं. जिसकी वजह से कश्मीरियों में अलगाव की भावना और प्रबल हो जाएगी. दरअसल कश्मीर समस्या का आदर्श समाधान यह होगा कि कश्मीर विधानसभा चुनाव में सिर्फ कश्मीरी पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने दिया जाए. न कांग्रेस चुनाव लड़े और न भाजपा. यदि कश्मीर के बाहर की पार्टियां यहां चुनाव नहीं लड़ेंगी तो क्या नुक़सान हो जाएगा? कुछ भी नहीं. उनमें से जो भी जीतेगा वह मुख्यमंत्री होगा. यह भारतीय संविधान के मुताबिक होगा और इस वजह से कश्मीरियों में आत्मविश्वास पैदा होगा कि वे अपना शासक चुन सकते हैं. यहां वे अपना शासक चुनते हैं लेकिन सरकार दिल्ली से बनती है. जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983-84 में किया था. जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं. पिछले 30-32 सालों से कश्मीर को पाकिस्तान की वजह से तकलीफें नहीं उठानी पड़ रही हैं, बल्कि फारुक़ अब्दुल्लाह की सरकार को हमने चलने नहीं दिया. आधी रात को उनकी सरकार गिरा दी गई और जीएम शाह के रूप में एक कठपुतली सरकार बिठा दी गई. इससे कश्मीर की जनता को यह संदेश मिला कि दिल्ली उन्हें उनका नेता नहीं चुनने देगी. इसे बंद होना चाहिए. मुझे नहीं मालूम कि सरकार के सलाहकार कौन हैं? लेकिन मुझे मालूम है कि मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं जो बहुत अनोखा हो. ये बातें हर किसी को मालूम हैं. लेकिन जो लोग भाजपा को चला रहे हैं या जिनके पास सत्ता है उन्हें संयम से काम लेना चाहिए.

जब ऐसी मामूली चीजें सही तरीके से संचालित नहीं हो सकतीं तो आप सरकार से चीन, पाकिस्तान या डिप्लोमेसी या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं. यहां मैं यह जरूर कहूंगा कि वे अपनी क्षमता के मुताबिक ठीक-ठाक काम कर रहे हैं. प्रधानमंत्री सऊदी अरब और ईरान से रिश्ते सुधारने की पहल कर रहे हैं, जो ठीक है. लेकिन पाकिस्तान एक समस्या है और यह समस्या रहेगी. हाल ही में उसने अपनी संयुक्त जांच टीम यहां भेजी. इसके बाद वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि यहां उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिला. वे यह शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जांच के लिए केवल 55 मिनट का समय मिला. इससे कुछ भी हल नहीं होगा. यशवंत सिन्हा और दूसरे लोगों की तरफ से जो सुझाव आए हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत बंद कर देनी चाहिए, मुझे ठीक लगता है. चीजों को ठंडा हो जाने दिया जाए, थोड़ा इंतज़ार किया जाए, क्योंकि इस मामले में बहुत अधिक विकल्प नहीं हैं. अगर दो पड़ोसी देश समृद्ध होना चाहते हैं, तो उन्हें अपने रिश्ते अच्छे करने होंगे. लेकिन जिस तरह वे आगे बढ़ रहे हैं वह ठीक नहीं है.

हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह सरकार कुछ ठोस रणनीति लेकर सामने आएगी. लेकिन देखना यह है कि वह एक नई तरह की शासन व्यवस्था देगी या फिर वह कांग्रेस की नकल करना चाहती है. इसमें भी कोई समस्या नहीं है क्योंकि हर पांच वर्ष में चुनाव होंगे. कोई जीतेगा और कोई हारेगा. इसमें देश का कोई खास नुक़सान नहीं होगा. यदि आरएसएस यह सोच रहा है कि हाफ पैंट पहनकर या भारत माता की जय बोलकर वह देश में एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है तो उनसे बहुत की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे समस्या का समाधान नहीं होगा. लेकिन जेएनयू के छात्र, छात्र तो छात्र होते हैं. उनमें से कोई आईएएस बनता है कोई शोधकर्ता बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, लेकिन आप वहां पुलिस भेजकर एक छात्र नेता को बड़ा नेता बनाने की कोशिश करते हैं. किस लिए? इससे कौन सा मक़सद हल हो जाएगा? मुझे लगता इन सभी चीज़ों पर पुनर्विचार की ज़रुरत है. इसपर जितनी जल्दी विचार होगा उतना ही बेहतर होगा.■

feedback@chauthiduniya.com

एक देश की चिंता

एच के दुआ

पैंसठ वर्ष पहले भारत नियति से साक्षात्कार (ट्रिस्ट विद डेस्टिनी) करने के लिए स्वतंत्र हुआ. एक नव स्वतंत्र राष्ट्र का सांप्रदायिक दंगों, लाखों शरणार्थियों को बसाने, कश्मीर में युद्ध, देशी रियासतों के एकीकरण, अंग्रेजी शासन द्वारा विरासत में मिली लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और लंबे समय तक चली आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोगों से किए गए वादे पूरे करने की आशाओं-आकांक्षाओं जैसी कई गंभीर चुनौतियों से सामना हुआ. विभाजन की पीड़ा और दो सौ वर्षों की दासता के बोझ के बावजूद भारत अपने भविष्य एवं उसकी अनिश्चितताओं की ओर बड़ी आशा और विश्वास के साथ देख रहा था. घोर ग़रीबी में जीवनयापन कर रही और सदियों से भेदभाव का शिकार रही 33 करोड़ आबादी वाले देश की शासन व्यवस्था संभालने वाले लोगों के सामने ऐसी चुनौतियां थीं, जो किसी भी नए शासक वर्ग को धराशायी कर देतीं. हमारे महान नेता अपनी दूरदर्शिता और दृढ़ इच्छाशक्ति (जो उनमें जेल की सजा काटते वक्त आई थी) के बल पर एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे, जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके.

आज़ादी के पहले पहर में ये किसी भी तरह की शासन पद्धति का चुनाव कर सकते थे. लोग उनके किसी भी निर्णय के साथ होते, क्योंकि लोगों को उन पर यकीन था. आज़ादी के कुछ महीने बाद ही महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई, लेकिन जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉ. बीआर अंबेडकर एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं ने भविष्य के मद्देनज़र एक ऐसे संविधान का निर्माण करने का निर्णय लिया, जो संसदीय लोकतंत्र, स्वतंत्र न्यायपालिका, एक जवाबदेह कार्यपालिका और स्वतंत्र प्रेस की ओर ले जाता हो. सबसे साहसी निर्णय उन्होंने वयस्क मताधिकार देने का लिया. हर भारतीय, चाहे वह अमीर हो या ग़रीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, प्रभावशाली हो या शोषित यानी किसी भी जाति-धर्म, वर्ग-क्षेत्र-लिंग का हो, को मतदान का अधिकार दिया गया. उन्होंने पश्चिमी देशों के व्यंग्य को नज़रअंदाज़ करते हुए देश के सुदूर इलाकों में रहने वाले लोगों पर भी विश्वास जताया कि उनमें इतनी समझ है कि वे अपने शासक का चुनाव कर सकें.

नया नेतृत्व एक ऐसे राष्ट्र-राज्य (नेशन स्टेट) का गठन करना चाहता था, जो लोकतांत्रिक हो, अपने नागरिकों के लिए न्यायसंगत हो और इतना शक्तिशाली भी कि किसी भी स्थिति में उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश भी फिर से अधीन न कर सके. उन्होंने ग़रीबी, अशिक्षा एवं गैर बराबरी के ख़िलाफ़ लड़ाई और बड़ी परियोजनाओं, औद्योगिक प्लांटों एवं बांधों पर सोच-विचार किया. इस राह में विभिन्न बाधाओं के बावजूद उन्होंने कुछ दूरी ज़रूर तय की. वे दिन अलग थे. उस दौर के नेताओं में कुछ अलग बात थी, उनके लक्ष्य बड़े थे. उन्हें स्वयं और जनता पर यकीन था. बदले में जनता ने भी उन पर विश्वास करते हुए उनके सपने और अरमान अपने मान लिए. वह समय बेहद रोमांचक था. एक तरह से कहा जाए, तो हाल में स्वतंत्र हुए एक देश द्वारा इतिहास रचा जा रहा था. यह 21वीं सदी की शुरुआत है और यह समय बिल्कुल अलग है. इस नई सदी में देश में इतिहास रचने की भावना का अभाव दिखाई पड़ रहा है. ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र भविष्य की फ़िक्र के बजाय अपने भीतर की चिंताओं में उलझा हुआ है.

आज भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है. उसके पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है. वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में मिली सफलताओं के चलते वह दुनिया के चुनिंदा परमाणु हथियार संपन्न देशों में शामिल है. आगामी एक-दो वर्षों में भारत चांद पर क़दम रखने जा रहा है और अगले पांच वर्षों में मंगल ग्रह पर भारतीय दल भेजने की तैयारी चल रही है. इन प्रभावशाली उपलब्धियों के बावजूद इस देश में एक व्यापक निराशा का वातावरण बन रहा है. अधिकांश नागरिकों द्वारा देश के भविष्य को लेकर चिंता या शंका ज़ाहिर की जा रही है, जो बताती है कि देश भर में अपरिभाष्य गुस्सा व्याप्त है. इस गुस्से की वजह से भारत के सामने इनवर्ड लुकिंग कंट्री (अपनी ही समस्याओं में उलझे रहने वाला देश) बनने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है. इसी वजह से वह अब तक दुनिया के सामने कोई बड़ी पहल करने और अपना उचित स्थान हासिल करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा है. एक ऐसा शख्स, जो अपनी आंतरिक चिंताओं से ग्रस्त हो, अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता नहीं तलाश सकता. यही तथ्य राष्ट्रों पर भी लागू होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा. देश की

वह समय बेहद रोमांचक था. एक तरह से कहा जाए, तो हाल में स्वतंत्र हुए एक देश द्वारा इतिहास रचा जा रहा था. यह 21वीं सदी की शुरुआत है और यह समय बिल्कुल अलग है. इस नई सदी में देश में इतिहास रचने की भावना का अभाव दिखाई पड़ रहा है. ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र भविष्य की फ़िक्र के बजाय अपने भीतर की चिंताओं में उलझा हुआ है.

रचनात्मक ऊर्जा बर्बाद हो रही है और उसकी जगह क्षयकारी नकारात्मकता ने ले ली है, जो मौजूदा राजनीतिक वातावरण के चलते पैदा हो रही है.

विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. बीआर अंबेडकर एवं अन्य बड़े नेताओं की धारणा भिन्न थी, विचार भिन्न थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत विचार कभी देश पर हावी नहीं होने दिए. जिस भावना के साथ उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, उसे देश ने भी पसंद किया और उन्हें निर्णय लेने का एक नैतिक अधिकार दे दिया, जिसका आज के संपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य में अभाव दिखता है. देश में सिर्फ़ नेतृत्व की गुणवत्ता में ही गिरावट नहीं आई, बल्कि यह गिरावट देश के संचालन के लिए संविधान में परिकल्पित प्रमुख संस्थाओं यानी संसद, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के कामकाज में भी आई है. आज़ादी के बाद अच्छी शुरुआत करते हुए उक्त संस्थाओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया था. तब लोग उक्त संस्थाओं का सम्मान करते थे, लेकिन समय के साथ उनकी कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण होती चली गई. इस वजह से लोगों का उनसे विश्वास उठ गया. लोगों के बीच सम्मान ह्रास होने की वजह से लोकतंत्र की गुणवत्ता और शासन के मानकों का भी क्षय हो रहा है.

संस्थागत गिरावट का सबसे खराब उदाहरण संसद स्वयं है. संविधान ने संसद को बहुत-सी ज़िम्मेदारियां एवं अधिकार दिए थे, इसलिए लोग उससे डरते थे और उसका सम्मान भी करते थे. लेकिन, आज वह लोगों के उपहास का विषय बन गई है. कई सांसदों के बर्ताव के चलते संसद लोगों के तिरस्कार की वस्तु बन गई है. एक समय था, जब सभी राजनीतिक दल अपने सर्वश्रेष्ठ नेताओं को संसद भेजते थे. जवाहर लाल नेहरू स्वयं संसद की बहस सुनते थे और कई बार बहस के बीच में सरकार की नीतियों और निर्णय स्पष्ट करते थे. उस दौर में गोविंद वल्लभ पंत, जगजीवन राम, डॉ. बीआर अंबेडकर जैसे सक्षम सांसद सत्ता पक्ष के साथ होते थे, वहीं सीपीआई के हीरेन मुखर्जी, भूपेश गुप्ता एवं इंद्रजीत गुप्ता, भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी, स्वतंत्र पार्टी के मीनू मसानी एवं नारायण दांडेकर, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाथ पाई एवं एचवी कॉमथ, सोशलिस्ट पार्टी के राम मनोहर लोहिया एवं मधु लिमये, सीपीआई (एम) के एके गोपालन और आचार्य कृपलानी (जो किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं थे) आदि ने मिलकर संसद की बहसों में तीखे तर्कों, तीक्ष्ण आलोचनाओं, तानों, हास्य, बुद्धि-विवेक और ज़िम्मेदारी की भावना से जान डाल दी थी. आज की पीढ़ी के सांसदों में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

नीतीश का महिला आंदोलन

नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी घोषित कर दी है. बिहार अब उन चुनिंदा राज्यों में शुमार हो गया है, जहां पूर्ण नशाबंदी लागू है. वे लोग जो शराब पीते थे, परेशान हैं. जो शराब बेचते थे, उनसे ज्यादा परेशान हैं. सबसे ज्यादा खुश बिहार की महिलाएं हैं. जिनसे नीतीश कुमार को हृदय से आशीर्वाद मिल रहा है. आज से 6 महीने पहले जब नीतीश कुमार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि वह बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे. तब मेरे पास कई तरह की ख़बरें आईं, जिनमें सबसे बड़ी ख़बर थी कि नीतीश कुमार शराब बंदी की घोषणा करेंगे लेकिन वह ऐसा कई चरणों में करेंगे. पहले चरण में देसी शराब के ऊपर पाबंदी होगी. इसके लिए यह तर्क सामने आया कि बिहार के शराब व्यापारी बिहार के एक बहुत बड़े राजनीतिक नेता से मिले हैं और उनसे उन्होंने राजनीतिक चंदा देने की बात कही और कहा कि शराब दो चरणों में बंद की जाए. संयोग से मेरे पास इस ख़बर के आने के 4-5 दिन बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहा कि पहले चरण में हम देसी शराब बंद करेंगे. मुझे लगा कि मेरे पास जो शराब माफियाओं के यहां से जो ख़बर आई है उसमें कुछ दम है. इसी बीच मेरी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई. मैंने नीतीश कुमार से बातचीत में शराबबंदी की बात छेड़ी, जिसके ऊपर नीतीश कुमार ने बताया कि किस तरह विधानसभा चुनाव के दौरान वह एक जगह बैठे थे और अपना भाषण दे चुके थे तब औरतों ने उनसे शराबबंदी के मसले पर अपनी राय भी रखी और उनसे उत्तर भी मांगा. नीतीश कुमार दोबारा मंच पर गए और उन्होंने बिहार की महिलाओं से वादा किया कि अगर वह चुनाव जीत जाते हैं, तो पूर्ण शराबबंदी लागू करेंगे. और नीतीश ने बहुत ही मुस्कुराते चेहरे से लेकिन सख्ती के साथ कहा कि मैं उस वचन का पालन करूंगा. मैं बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करूंगा.

मेरे पास एक और ख़बर आई कि जैसे ही बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी की पहली घोषणा की. देश के कुछ शराब निर्माताओं के पास अचानक 5 हजार करोड़ से ज्यादा का एडवांस बिहार के शराब माफिया की तरफ से आ गया. उन्होंने शराब निर्माताओं से कहा कि हमें जब शराब लेनी होगी, ले लेंगे, लेकिन आप ये हमारा एडवांस रखिए ताकि शराबबंदी की स्थिति में आप हमें शराब सप्लाई कर सकें. जब मैंने नीतीश कुमार को यह बात बताई, तो नीतीश कुमार ने कहा कि यह पता करना चाहिए कि किस तरीके से शराब बिहार में आएगी. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप के जरिए शराब निर्माता मेरे पास ख़बर पहुंचा रहे हों. मैंने उनसे कहा कि कोई इस तरीके से ख़बरें नहीं पहुंचाता, लेकिन यह सच है कि आपकी घोषणा के साथ शराब निर्माताओं की बाछें खिल गई हैं, क्योंकि उनसे ब्लैक में शराब खरीदकर बिहार में सप्लाई करने का तंत्र तैयार हो रहा है. नीतीश कुमार ने फिर मुझसे कहा, फिर भी अगर संभव हो तो उनकी सप्लाई लाइन क्या होगी. इसके बारे में जरूर पता कीजिए. मैंने उनसे वादा किया कि इसके बारे में अगर कोई ख़बर होगी, तो मैं आपको बताऊंगा. जब नीतीश कुमार की यह घोषणा आई कि पहले वह देसी शराब बंद करेंगे और फिर विदेशी शराब, तो वह पैसा जो एडवांस में शराब निर्माताओं के पास आया था वापस हो गया. और शराब निर्माता जो अंग्रेजी शराब बनाते हैं या सप्लाई करते हैं. उन्हें एक निश्चिंतता मिली कि बिहार में कम से कम उनका व्यापार चलता रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार शराब से मिलने वाले टैक्स का जब तक पर्याय नहीं सोच लेते तब तक वह शायद इसे बंद न करें और सबसे पहले वह देसी और कच्ची शराब बंद करें. जिसमें वो महिलाओं की सहायता ले सकते हैं.

पर अचानक नीतीश कुमार ने घोषणा कर, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी. मैंने फिर शराब निर्माताओं को खंगाला और शराब निर्माताओं की बाछें खिली हुई मिलीं. बिहार में शराब बेचने वाले माफिया ने या तस्करी करने वाले माफिया ने उन्हें इस बार 6 हजार करोड़ रुपये का एडवांस दे दिया और बिहार में कैसे शराब जाएगी, इसका इंतजाम करना शुरू कर दिया. मैंने जानना चाहा

शायद हमारा सिस्टम इतना सड़ गया है कि किसी को भी कोई भी गलत काम करने के लिए किसी नई व्यवस्था की जरूरत नहीं है. उस व्यवस्था में ही ऐसे तत्व मिल जाएंगे जो 80 प्रतिशत लोगों को अपने जाल में लेकर उस गलत काम को बेखौफ और बेहिचक करते दिखाई दे जाएंगे. बिहार की शराबबंदी उत्तर प्रदेश के शराब निर्माताओं की खुशी और उनका ये ओवरकॉन्फिडेंस कि उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग ही बिहार में सप्लाई करेगा और बिहार का आबकारी विभाग इसको पहुंचाएगा, ये कमाल की चीज है. यहीं पर नीतीश कुमार के लिए चुनौती खड़ी होती है और मैं ये नीतीश कुमार को बता देना चाहता हूं कि आप सरकारी कर्मचारियों के जरिए इस तस्करी के ऊपर रोक लगाने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं.

कि आखिर शराब को बिहार में भेजने का शराब निर्माताओं के पास क्या रास्ता है या बिहार में जो शराब बेचते हैं, वो शराब बिहार की सीमा में कैसे लाएंगे इसका वो क्या रास्ता निकालने वाले हैं. तब मुझे जो बात पता चली वो इतनी साधारण लेकिन इतनी गंभीर और महत्वपूर्ण है कि मैं नीतीश कुमार को ये सार्वजनिक रूप से बताना चाहता हूं. मुझे ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग यानी जिसके ऊपर शराब को जिलों में पहुंचाने की जिम्मेदारी है और बिहार का आबकारी विभाग जिसके पास बिहार में शराबबंदी की जिम्मेदारी है, दोनों में इतना अंतरंग रिश्ता बना हुआ है कि किसी और व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है. ये व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश से शराब बिहार में भेजेगी और वो जो सरकारी व्यवस्था जिसके ऊपर शराब रोकने की जिम्मेदारी है, वो बिहार के जिलों-जिलों में कस्बों-कस्बों में गांव-गांव में शराब फैलाएगी. मैं ये बात 100 प्रतिशत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि यही मुझे सूचना मिली है. हालांकि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरी ये सूचना गलत साबित हो. इसका मतलब कि तस्करी का पूरा तंत्र सरकार के विभाग की देख-रेख में चलने वाला है.

शायद हमारा सिस्टम इतना सड़ गया है कि किसी को भी कोई भी गलत काम करने के लिए किसी नई व्यवस्था की जरूरत नहीं है. उस व्यवस्था में ही ऐसे तत्व मिल जाएंगे जो 80 प्रतिशत लोगों को अपने जाल में लेकर उस गलत काम को बेखौफ और बेहिचक करते दिखाई दे जाएंगे. बिहार की शराबबंदी उत्तर प्रदेश के शराब निर्माताओं की खुशी और उनका ये ओवरकॉन्फिडेंस कि उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग ही बिहार में सप्लाई करेगा और बिहार का आबकारी विभाग इसको पहुंचाएगा, ये कमाल की चीज है. यहीं पर नीतीश कुमार के लिए चुनौती खड़ी होती है और मैं ये नीतीश कुमार को बता देना चाहता हूं कि आप सरकारी कर्मचारियों के जरिए इस तस्करी के ऊपर रोक लगाने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं. आपको अगर शराबबंदी लागू करनी है और शराब के इस अवैध व्यापार को रोकना है. तब आपके पास बिहार की महिलाओं के अलावा और कोई हथियार नहीं है. आप बिहार की महिलाओं को सशक्त कीजिए, ताकि वो महिलाएं, जहां भी शराब आ रही है उसको पकड़ें, उनकी रिपोर्ट के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे और कार्रवाई भी अगर करनी है, तो महिलाओं को ही इसका जिम्मा दीजिए कि वो स्थानीय स्तर पर उसके ऊपर जो फैसला करना चाहें जिस तरह का फैसला करना चाहें उसे करें. शायद महिलाओं की ये ताकत बिहार में शराबबंदी तो लागू करवाएगी ही, हो सकता है बिहार के नवनिर्माण में या बिहार के पुनर्निर्माण में होने वाले भ्रष्टाचार के नियंत्रण का एक नया सूत्र नीतीश कुमार के पास आ जाए और नीतीश कुमार देश में पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएं जो जनता की ताकत, खासकर महिलाओं की ताकत को संगठित कर अपने विकास के एजेंडे को मजबूती के साथ लागू कर पाएं.

ये जितना इम्तिहान नीतीश कुमार का है उससे ज्यादा बड़ा इम्तिहान बिहार की महिलाओं का भी है. बिहार के सीमावर्ती राज्यों में जिनमें उत्तर प्रदेश विशेष है, यहां के आबकारी विभाग का तो इम्तिहान है ही, क्योंकि उन्हें भी ये साबित करना है कि शराब माफिया का ये मानना कि आबकारी विभाग ही तस्करी में उनकी मदद करेगा इसे झूठा साबित करना उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी एक बड़ा सवाल है. देखते हैं वो इसका कैसे उत्तर देते हैं. ■

editor@chauthiduniya.com

आर्टिकल-356 पर बहस होनी चाहिए

मेघनाद देसाई

पचास के दशक के मध्य में परीक्षाओं में अकसर इस तरह के सवाल पूछे जाते थे कि भारत एक संघ है जिसका झुकाव एकात्मक (यूनिटरी) व्यवस्था की तरफ है. टिप्पणी करें. यह उससे भी पहले की बात है जब जवाहर लाल नेहरू ने केरल में जनता द्वारा चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त करके अपना दामन दागदार नहीं किया था. इसके बाद स्थिति लगातार खराब होती चली गई. इंदिरा गांधी ने नियमित रूप से राज्य सरकारों को बर्खास्त किया. अंततः बोम्मई केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामले में हस्तक्षेप किया.

संघवाद (फेडरलिज्म) और लोकतंत्र दो ऐसे स्तंभ हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए. आर्टिकल-356 की उत्पति 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हुई है, जिसके तहत गवर्नर जनरल को सूबों की निर्वाचित सरकारों पर अधिक अधिकार मिले थे. भारत में लोकतंत्र के आने से पहले ही एक्जीक्यूटिव के अधिकार स्थपित हो चुके थे, जो अब तक बरकरार हैं. फर्क केवल इतना है कि राष्ट्रपति अब चुना जाता है और मंत्री परिषद (जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है) के मशवरे पर काम करता है.

जैसे संघीय सरकार चुनकर आती है उसी तरह राज्य सरकारें भी चुनकर आती हैं. इन सरकारों की बर्खास्तगी की शर्त विधायिका का अविश्वास और कुशासन (जैसा के पहले के मामलों में होता था) है. पहली शर्त को पूरा करने में दल-बदल क़ानून ने जटिलता पैदा कर दी है. इस क़ानून ने पार्टी के नेता को अधिक ताक़तवर बना दिया है, जिसके कारण सभापति का महत्व बढ़ जाता है. लिहाज़ा, चुनकर आए सदस्यों/विधायकों की पार्टी से असहमति जताने वाले लोकतांत्रिक अधिकारों की कोई हैसियत नहीं है. ऐसे में दो प्रतिस्पर्धी निर्वाचित सरकारों की रस्साकशी शुरू हो जाती है.

जैसे ही आप पार्टी स्तर पर मतभेद ज़ाहिर करते हैं आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं. ऐसे

मामलों में अत्यधिक शक्तिशाली केंद्र को केवल न्यायपालिका ही रोक सकती है. लेकिन यहां भी निचली और उच्च अदालतें हैं और जैसा कि हमने उत्तराखंड मामले में छोटी खंडपीठ और बड़ी खंडपीठ को देखा.

आर्टिकल-356 का झगड़ा संविधान की एक खामी को उजागर करता है. इसमें साफ़ नहीं है कि राज्य सरकार को बर्खास्त करने का आखिरी फैसला किसका होगा. आर्टिकल-356 को लागू करने का राष्ट्रपति का फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिया जा सकता है. (जैसा कि हमने एनजेएसी मामले में देखा कि सुप्रीम कोर्ट खुद से जुड़े मामले में भी संसद के फैसले को रद्द कर सकता है. लिहाजा न्यायपालिका खुद के सुधार को भी रोक सकती है.)

यह समस्या केवल मौजूदा सरकार या पूर्व की सरकारों की नहीं है. यह समस्या इसलिए है क्योंकि भारत आज़ाद रियासतों का संघ नहीं है, जैसा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. यह एक ऐसी संघीय व्यवस्था है जहां सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ आती है. आज़ादी के बाद इसमें संघीय प्रावधान किए गए थे. संविधान केंद्र को नए राज्य बनाने, उनकी सीमाएं पुनर्निर्धारित करने इत्यादि का अधिकार देता है. जबकि अमेरिका में संघीय सरकार के पास न तो राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार है और न ही उनकी सीमाओं के पुनर्निर्धारण का. उत्तराखंड मामले में क्या होगा यह तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह समस्या बरकरार रहेगी कि इस मामले में आखिरी फैसला किसका होगा.

अगर केंद्र सरकार द्वारा राज्य की एक निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और न्यायपालिका उसके फैसले को रद्द कर देती है, ऐसे में यह सवाल ज़रूर उठेगा कि ऐसे मामलों में अंतिम फैसला किसका होगा?

केंद्र सरकार को केवल संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है. केंद्र में राष्ट्रपति शासन की कोई व्यवस्था नहीं है. लिहाज़ा यह कहा जा सकता है कि केंद्र में लोकतंत्र की सत्ता है जबकि राज्यों में ऐसा नहीं है. आर्टिकल-356 पर बहस अत्यंत आवश्यक है. अगर भारत एक लोकतंत्र है तो यहां का हर एक जन प्रतिनिधि (सांसद/विधायक) बराबर है. और यदि भारत संघ है तो केंद्र को राज्यों को बराबरी का सम्मान देना चाहिए. ■

भारत आज़ाद रियासतों का संघ नहीं है, जैसा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. यह एक ऐसी संघीय व्यवस्था है जहां सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ आती है. आज़ादी के बाद इसमें संघीय प्रावधान किए गए थे. संविधान केंद्र को नए राज्य बनाने, उनकी सीमाएं पुनर्निर्धारित करने इत्यादि का अधिकार देता है. जबकि अमेरिका में संघीय सरकार के पास न तो राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार है और न ही उनकी सीमाओं के पुनर्निर्धारण का. उत्तराखंड मामले में क्या होगा यह तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा, लेकिन यह समस्या बरकरार रहेगी कि इस मामले में आखिरी फैसला किसका होगा.

feedback@chauthiduniya.com

VCSM®
विश्व कम्प्यूटर साक्षरता मिशन
A program initiated by Sanjeeo Technological System (P.) Ltd.
ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 Certified
VCSM की फ्रेंचाइजी बनिए और अपने साथ-साथ हजारों के कैरियर बनायें।
विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें : जूही अलका 9386551901

नक्सल और आपराधिक गतिविधियां हुईं तेज

पंचायत चुनाव में गरजेंगी बंदूकें!

राजेश सिन्हा

चुनावी बुखार की तपिश में तप रहे बिहार का प्राकृतिक तापमान आमजनों को परेशान तो कर ही रहा है, राजनीतिक तापमान प्रत्याशियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है. टपटपाते पसीने से सराबोर प्रत्याशियों द्वारा घर-घर दस्तक देकर मतदाताओं को अपनी-अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन मतदाताओं की खामोशी टूटने का नाम ही नहीं ले रही है. किसी इलाके में विकास नहीं होने से मतदाता नाराज हैं, तो किसी जिले में विकास कार्य के नाम पर हुई लूट को लेकर मतदाताओं के बीच नाराजगी है. वार्ड से लेकर पंचायत स्तर तक पसरे चुनावी गहमा-गहमी के बीच चुनावी मोहरों को सजाने का दौर चल रहा है. दस चरणों में सम्पन्न होने वाले पंचायत चुनाव में कौन-कौन प्रत्याशी बनेंगे जीत के नायक और किनके-किनके नसीब में लिखी है हार, यह कहना तो शायद जल्दबाजी होगी. लेकिन चुनावी बिसात पर जीत हार की तिकड़म गढ़ने में लगे प्रत्याशियों के अलग-अलग दावे हैं और अलग-अलग राजनीतिक गणित. कोई विकास का दावा करने में लगा है, तो कोई विकास को झूठ की पोटली साबित करने का दावा कर अपनी जीत की उम्मीद पाल रखा है. सुबह से लेकर देर रात्रि तक विभिन्न पंचायतों का नजारा देखने लायक होता है. दर्जनों समर्थकों के साथ पंचायतों का भ्रमण करने में लगे विभिन्न पंचायत चुनाव प्रत्याशियों द्वारा अपने-अपने तरीके से चुनावी गणित समझाकर अपनी-अपनी जीत का दावा किया जा रहा है. लेकिन यह कहने में शायद कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि पंचायत चुनाव का नगाड़ा बजते ही बिहार में न केवल प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है बल्कि अपराधियों तथा नक्सलियों की गतिविधियों में भी अचानक तेजी आ गई है. प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा जहां भयमुक्त तथा निष्पक्ष माहौल में पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं बिहार के दियारा इलाके में अपराधियों की बढ़ती गतिविधियां इस बात का संकेत देने लगी हैं कि दस चरणों में सम्पन्न होने वाले पंचायत चुनाव के दौरान अपराधियों की बंदूके गरज सकती हैं. नक्सल प्रभावित इलाके में विशेष चौकसी के बीच पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने का दावा किया जा रहा है और दावे के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए जा रहे हैं. लेकिन लगता नहीं है कि पुलिस नक्सलियों और अपराधियों के मंसूबे को कुचल पाएगी. क्योंकि पंचायत चुनाव का नगाड़ा बजते ही नक्सलियों के द्वारा मतदान को प्रभावित करने की रणनीति जहां तेज हो गई है, तो वहीं अपराधियों के द्वारा दियारा इलाके में स्थापित की गई मिनी गन फैक्ट्रियों ने हथियार भी उगलना शुरू कर दिया है. यह बात अलग है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त अशोक कुमार चौहान का दावा है कि चुनाव के दौरान जिलों में सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की जाएगी और किसी भी कीमत पर निष्पक्ष व भयमुक्त माहौल में पंचायत चुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे. पुलिस महानिदेशक पी.के. ठाकुर का भी दावे के साथ कहना है कि सभी जिलों में विशेष छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों सहित अन्य असामाजिक तत्वों के विरुद्ध साकारात्मक कार्रवाई की जा रही है. हिंसामुक्त माहौल में पंचायत चुनाव सम्पन्न कराने की मुहिम में जुटे डीजीपी ने यह भी कहा है कि चुनाव के दौरान नकदी व शराब के वितरण पर प्रभावी कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है. और अर्द्धसैनिक बलों के साथ-साथ रोड ओपनिंग पार्टी अर्थात आरओपी को तैनात कर हर हाल में हिंसामुक्त माहौल में चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा. चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने वालों की खैर नहीं होगी. बिहार के पुलिस महानिदेशक पी.के ठाकुर के दावों में कितना दम है, यह तो आगामी 24 अप्रैल से 30 मई तक दस

चरणों में सम्पन्न होने वाले पंचायत चुनाव के बाद ही स्पष्ट तौर पर कहना सही होगा. लेकिन जानकारों की अगर मानें तो बिहार में पंचायत चुनाव का नगाड़ा बजने के बाद से ही विभिन्न आपराधिक गिरोहों के द्वारा हथियारों का जखीरा जमा किया जाने लगा है और धीरे-धीरे नक्सल गतिविधियां भी परवान चढ़ने लगी हैं. मुंगेर जिले के हथियार तस्करों सहित अन्य जिले के अपराधियों द्वारा दियारा इलाके में जगह-जगह मिनी गन फैक्ट्री को स्थापित कर हथियारों का जखीरा पैदा किया जाने लगा है और विभिन्न इलाकों में भेजा भी जाने लगा है. इतना ही नहीं पंचायत चुनाव के इस मौसम में मुंगेर के हथियार निर्माणकर्ताओं के द्वारा निर्मित हथियारों की न केवल मांग बढ़ गई है बल्कि कीमत में भी इजाफा हो गया है. आमतौर पर कल तक दो हजार रुपये में बिकने वाला मुंगेर निर्मित थ्री-नट फिलहाल तीन से चार हजार रुपये में बेचा जा रहा है. पिस्टल सहित अन्य तरह के हथियारों की बढ़ती मांग के कारण हथियार तस्करों ने कीमत में इजाफा कर दी है. सुलभ तरीके से गोलियां उपलब्ध होने वाले हथियारों की कीमत अधिक है जबकि अन्य तरह के हथियारों की अलग-अलग कीमत तय किए जाने की जानकारी भी मिल रही है. छोटे-छोटे आपराधिक गिरोहों के द्वारा हथियार तस्करी किए जाने के कारण दियारा इलाका हथियारों की मंडी बनकर रह गया है. पुलिस की बढ़ती चौकसी को देखकर अपराधियों के द्वारा हथियार तस्करी में गरीब स्कूली बच्चों का जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है. छोटे-छोटे स्कूली बच्चों को रुपये का लोभ देकर हथियारों को इधर से उधर भेजा जा रहा है. स्कूली बैग के जरिए हो रही हथियारों की तस्करी पर फिलहाल पुलिस की नजर नहीं रहने की वजह से अपराधियों की बल्ले-बल्ले तो है ही, पंचायत चुनाव प्रभावित होने के आसार भी बढ़ते जा रहे हैं. हालांकि स्कूली बच्चों के द्वारा हथियार तस्करी कराए जाने का मामला पहली बार सामने नहीं आ रहा है. विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने के पूर्व से ही इस तरह की बातें इसलिए जुगाली करती रही हैं, क्योंकि दो स्कूली बच्चों को स्कूली बैग के जरिए हथियार तस्करी करते हुए खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में पकड़ा गया था. उसके बाद यह खुलासा हुआ था कि मुंगेर जिले के हथियार तस्करों द्वारा स्कूली बच्चों के जरिए हथियार तस्करी कराए जा रहे हैं. हथियारों को एक-दूसरे इलाके में भेजे जाने के लिए जलमार्ग अपराधियों के लिए सुगम मार्ग बना हुआ है. वीरान दियारे इलाके में न ही पुलिस फटकना चाहती है और न ही स्थानीय लोग अपराधियों के विरुद्ध मुंह खोलना पसंद कर रहे हैं. नतीजतन दियारे इलाके में पैदा किए जा रहे अवैध हथियारों को छोटे-छोटे नौका के जरिए नदी पार कराकर सुरक्षित जगहों पर रखा जा रहा है. फिर वहां से गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चुनावी बुखार में तप रहे बिहार में सम्पन्न होने वाले पंचायत चुनाव के मतदान की तिथि जैसे-जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे-वैसे न केवल प्रशासनिक गतिविधियां चरम पर पहुंचती जा रही हैं, बल्कि दियारा में आपराधिक गतिविधियां भी परवान चढ़ती दिख रही हैं. प्रशासनिक दावों के बीच अपराधियों व नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियां कहीं न कहीं दस चरणों में सम्पन्न होने वाले पंचायत चुनाव को प्रभावित करती दिख रही हैं और आमजनों के साथ-साथ प्रत्याशियों की भी नजर प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न आपराधिक गिरोहों पर भी है.■

feedback@chauthiduniya.com

ट्रॉमा सेंटर

कहां तो तय था नौ, मिला एक भी नहीं

सुनील सौरभ

बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रतिदिन हादसे दर हादसे हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं. लेकिन आज तक एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं बन पाया है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर हादसों का शिकार हो रहे लोगों की जानें बचाई जाएं. दक्षिण बिहार के केंद्र बिंदु और झारखंड से लगे गया जिले में स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज(अस्पताल) में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य कुछ वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, लेकिन पिछले तीन वर्षों से इस ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य बंद पड़ा है. दो राष्ट्रीय राजमार्गों राष्ट्रीय राजमार्ग-2 और 83 से जुड़े गया जिले में ट्रॉमा सेंटर के निर्माण कार्य की स्वीकृति 2009-10 में मिली थी. इसके लिए 6 करोड़ रुपये का प्रबंध केंद्र सरकार की ओर से किया गया था और 80 लाख रुपये मिल भी चुके थे, जिससे अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य शुरू हुआ. लेकिन वर्तमान में इस ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य बंद पड़ा है. जिसके कारण सड़क हादसों के शिकार हो रहे लोगों को जान देनी पड़ रही है. राज्य के नौ स्थानों में से किसी एक स्थान पर भी सुपर स्पेशियलिटी वाले तमाम सुविधाओं से लैस ट्रॉमा सेंटर रहता, तो कई ऐसे हादसे हुए हैं, जिसमें लोगों की जानें बचाई जा सकती थीं. ट्रॉमा सेंटर किसी भी अस्पताल का एक विभाग होता है, जहां तमाम आधुनिक संसाधनों के साथ विशेष प्रशिक्षित डॉक्टर होते हैं, जहां मुख्य तौर पर वैसे मरीजों का इलाज होता है जो गंभीर अवस्था में अस्पताल लाए जाते हैं. उदाहरण के तौर पर ऊंचाई से गिर जाने, वाहन दुर्घटना तथा गोली लगने पर मरीजों को यहां लाया जाता है. ट्रॉमा सेंटर हर हाइवे के पास होता है, जैसे दिल्ली-जयपुर, दिल्ली-आगरा हाइवे पर ट्रॉमा सेंटर हैं. देश के अन्य कई स्थानों पर भी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया है. बिहार में चार स्थानों गया, पुर्णियां, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में लेवल-2 और किशनगंज, गोपालगंज, अररिया, सासाराम व मधेपुरा में लेवल-3 ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य प्रस्तावित है. इन सभी स्थानों से विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों का गुजरना होता है. दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है जो देश के वयस्तम राजमार्गों में से एक है. बिहार व उत्तर प्रदेश की सीमा कर्मनाशा नदी पर बने पुल से यह राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार में प्रवेश करता है, जो डोभी व बाराचट्टी होते हुए झारखंड में प्रवेश कर जाता है. बिहार में यह सड़क 202 किलोमीटर तक फैली हुई है. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-83 पूरी तरह राज्य में ही है और पटना से शुरू होकर डोभी तक जाता है. यह राजमार्ग जहानाबाद, गया और बोधगया होकर गुजरता है. इसकी कुल लम्बाई 130 किलोमीटर है. गया जिले में पड़ने वाले इन दोनों राजमार्गों पर एक साल में लगभग 500 गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हुईं हैं. गया जिले की पुलिस, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग से मिले आकड़ों के अनुसार 2015 में ही सड़क दुर्घटना के 492 गंभीर मामले सामने आए, जिन्हें बेहतर इलाज की जरूरत पड़ी. इनमें 289 ऐसे मामले आए, जिसमें सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत हो गई. इन सब के आलावा कुछ ऐसे मामले भी होते हैं, जिनमें

पीड़ित परिवार निजी अस्पतालों में जाकर इलाज करवाते हैं. गया के दोनों राजमार्गों पर होने वाले हादसों के शिकार लोगों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज लाया जाता है. यहां ट्रॉमा सेंटर नहीं होने के कारण गंभीर मरीजों को पटना रेफर कर दिया जाता है, लेकिन अधिकतर मरीजों की मौत पटना पहुंचने से पहले ही रास्ते में हो जाती है. गया स्थित अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के साथ सबसे बड़ी विडम्बना है कि यहां किसी भी तरह की सुपर स्पेशियलिटी सुविधा नहीं है. ऐसे में बड़ी दुर्घटनाओं के लिए मगध मेडिकल कॉलेज की भूमिका सिर्फ रेफर करने वाले की रह जाती है. ऐसे गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों के इलाज के लिए दो विशेषज्ञ न्यूरोसर्जन व कार्डियोलॉजिस्ट का होना बहुत जरूरी है. हालांकि 2010 में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर लेवल-2 बनाने की योजना बनाई गई थी. ट्रॉमा सेंटर को तमाम सुविधाओं और इसे सुपर स्पेशियलिटी बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय हुआ था. शुरू में इसके लिए 80 लाख रुपये का आवंटन किया गया था और इस रुपये से कुछ काम हुआ, फिर इसके बाद काम बंद हो गया. इस संबंध में आधिकारिक रूप से कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है. बताया जाता है कि 2009 में मिले 80 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार की ओर से केंद्र को नहीं भेजा गया, जिसके कारण आगे की राशि नहीं मिल पाई. इस बात की सूचना केंद्रीय स्वास्थ व परिवार कल्याण मंत्रालय ने गया के सांसद हरि मांझी के पूछे गए सवाल के जवाब में दिया है. अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉ. सुधीर कुमार सिन्हा का कहना है कि यहां ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जाए और साथ ही विशेषज्ञ डॉक्टर का पदस्थापन भी किया जाए. इस पर राज्य सरकार को पहल करनी होगी. इस मामले में कई बार विभाग तथा सरकार को लिखा गया है, लेकिन अबतक कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है. राज्य व केंद्र सरकार के स्तर पर ट्रॉमा सेंटर निर्माण का मामला कहां जाकर फंसा है यह बताना मुश्किल है. बिहार के गया जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही प्रति वर्ष लगभग पांच सौ सड़क हादसे होने के आंकड़े से अनुमान लगाया जाना चाहिए कि बिहार के विभिन्न स्थानों से गुजरने वाले अन्य राजमार्गों पर होने वालों हादसों की संख्या प्रतिवर्ष कई हजार में जा सकती है. एक अनुमान के मुताबिक बिहार में सड़क हादसों में प्रतिदिन दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है. इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रतिवर्ष सड़क हादसे में लोगों की कितनी मौतें होती होंगी. बिहार के नौ स्थानों में से कुछ स्थानों पर भी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण हो जाए, तो सड़क हादसे के शिकार हुए सैकड़ों लोगों की जाने बच सकती हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

किसानों का लोन खा गए विधायक जी!

मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एडीबी शाखा का है. पीड़ित किसान मुंसी सदा, चंदन कुमार, नीलम देवी, लालो देवी, बुलबुल देवी सहित 27 लोगों ने जनता दरबार में दिए गए शपथ पत्र एवं आवेदन में साफतौर पर विधायक चंदन राम और उनके पिता अर्जुन राम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि दोनों लोगों ने सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा कर किसी को चालीस हजार तो किसी को आठ हजार रुपये दिए हैं. हमें बाद में पता चला कि बैंक से एक लाख और पचास हजार का ऋण स्वीकृत हुआ है. इस के.सी.सी ऋण धोखाधड़ी मामले में नियम को ताख पर रख कर दिए गए लाखों के लोन में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी की संभावना है. अगर पूरे मामले की जांच हो तो करोड़ों की राशि की हेरा-फेरी का मामला सामने आ सकता है. जिलाधिकारी साकेत कुमार ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं. चूंकि मामला एसबीआई से जुड़ा है, इसलिए इसी बैंक के समन्वयक को जांच करने का निर्देश दिया गया है.

मनेन्द्र कुमार

खगड़िया जिले के अलौली विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक चंदन राम के पिता अर्जुन राम पर गरीब किसानों के साथ ठगी का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है. इस ठगी में शक की सुई विधायक चंदन राम के आस पास भी घूम रही है. विधायक और उनके पिता पर के.सी.सी ऋण के नाम पर दर्जनों लोगों ने ठगी का आरोप जिलाधिकारी के जनता दरबार में लगाया है. बिहार में के.सी.सी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल जारी है, लेकिन अलौली में जो मामला सामने आया है इसमें विधायक और विधायक के पिता अर्जुन राम पर गोल-माल करने का आरोप लगाया जा रहा है. वहीं इस मामले में बैंक प्रबंधक की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का सही ढंग से अवलोकन किया जाए तो मामले से संबंधित जानकारी उजागर हो सकती है. इस फर्जीवाड़े के सामने आते ही जिले का राजनीतिक पारा गर्म हो गया और आरोप प्रत्यारोप के बीच राजद नेता अर्जुन राम की भी परेशानी बढ़ती जा रही है.

चंदन राम

बिहार में के.सी.सी के नाम पर फर्जीवाड़े का खेल जारी है, लेकिन अलौली में जो मामला सामने आया है इसमें विधायक और विधायक के पिता अर्जुन राम पर गोलमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है. वहीं इस मामले में बैंक प्रबंधक की जिम्मेदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का सही ढंग से अवलोकन किया जाए तो मामले से संबंधित जानकारी उजागर हो सकती है. इस फर्जीवाड़े के सामने आते ही जिले का राजनीतिक पारा गर्म हो गया और आरोप प्रत्यारोप के बीच राजद नेता अर्जुन राम की भी परेशानी बढ़ती जा रही है. आरोप है कि अलौली में किसानों से ठगी प्रकरण में घर पर ही कई कागजातों पर अंगूठा लगाने के बाद किसानों को कुछ रकम दे दी गई.

आरोप है कि अलौली में किसानों से ठगी प्रकरण में घर पर ही कई कागजातों पर अंगूठा लगाने के बाद किसानों को कुछ रकम दे दी गई. छह महीने के बाद जब किसानों को पता चला कि लोन की रकम बहुत ज्यादा है, तो अनपढ़ किसानों के होश उड़ गए. यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एडीबी शाखा का है. पीड़ित किसान मुंसी सदा, चंदन कुमार, नीलम देवी, लालो देवी, बुलबुल देवी सहित 27 लोगों ने जनता दरबार में दिए गए शपथ पत्र एवं आवेदन में साफतौर पर विधायक चंदन राम और उनके पिता अर्जुन राम पर धोखा-धड़ी का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा है कि दोनों लोगों ने सादे कागज पर हस्ताक्षर करवा कर किसी को चालीस हजार तो किसी को आठ हजार रुपये दिए हैं. हमें बाद में पता चला कि बैंक से एक लाख और पचास हजार का ऋण स्वीकृत हुआ है. इस के.सी.सी ऋण धोखाधड़ी मामले में नियम को ताख पर रख कर दिए गए लाखों के लोन में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी की संभावना है. अगर पूरे मामले की जांच हो तो करोड़ों की राशि की हेरा-फेरी का मामला सामने आ सकता है. जिलाधिकारी साकेत कुमार ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं. चूंकि मामला एसबीआई से जुड़ा है, इसलिए इसी बैंक के समन्वयक को जांच करने का निर्देश दिया गया है. जबकि एसडीएम सजल चटराजन ने एसबीआई के जिला समन्वयक को पत्र लिख कर इस मामले की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट मांगा है. यह मामला जब आपदा प्रबंधन मंत्री सह बीस सूत्रीय प्रभारी प्रो. चंद्रशेखर के सामने आया तो उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी रूप में हो इसे रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. बैंक प्रबंधक की बात माने तो एलपीसी की जांच से इस पूरे प्रकरण का मामला उजागर हो सकता है. इस मामले में जिला जन शिकायत कोषांग प्रभारी सुधीर कुमार ने बताया कि 27 लोगों ने बैंक से मिले लोन में बड़े पैमाने पर राशि की गोलमाल की शिकायत डीएम के जनता दरबार में की है. जिसमें चंदन राम, अर्जुन राम एवं एसबीआई के फील्ड ऑफिसर अरुण राय पर एसबीआई एडीबी शाखा से ऋण की राशि में हेराफेरी का आरोप लगाया है. पूरे मामले की जांच का आदेश सदर एसडीओ को दिया गया है.

वहीं अलौली विधायक चंदन राम ने कहा है कि किसानों को ऋण मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है. राजनीतिक साजिश के तहत आरोप लगा कर छवि खराब करने वालों को बेनकाब किया जाएगा. जबकि एडीबी शाखा के प्रबंधक भवेश कुमार खां ने कहा कि लोन वितरण में कहीं से भी कोई धांधली नहीं हुई है फिर भी किसी को कोई शिकायत है, तो पूरे मामले की जांच होगी, क्योंकि लाभ पाने वाले किसानों के हाथों में ही ऋण की राशि दी गई है. वहीं विधायक के पिता सह राजद नेता अर्जुन राम ने कहा कि साजिश के तहत मुझे फंसाया जा रहा है. इस पूरे मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है. शिकायत करने वाले किसान मुझे पहचानते तक नहीं होंगे. सारे आरोप बेबुनियाद हैं.

अरुण राय ने कहा कि मुझे पता भी नहीं हैं कि ऋण वितरण में धांधली का क्या मामला है. मुझे फसाने की कोशिश की जा रही है.

वहीं राजद के छात्र नेता चंदन यादव का आरोप है कि बिचौलिए और बैंक प्रबंधन की मिली भगत से करोड़ों के लोन मामले में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी हुई है. पूरा मामला सामने आने के बाद झूठे मुकदमें में फंसा कर गरीबों की अवाज दबाने की साजिश हो रही है. गरीबों के हक पर डाका डालने वाले चाहे कितने ही ताकतवर क्यों न हों उन्हें सलाखों के पीछे जाना ही होगा. गरीबों के हक की हकमारी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस पूरे मामले में अलौली के पूर्व विधायक सह जदयू नेता राम चन्द्र सदा का कहना है कि पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

इस मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

(सभी किसानों ने एसबीआई के एडीबी शाखा से लोन लिया है तथा शपथ पत्र देते हुए डीएम के जनता दरबार में शिकायत की है.)

लोन धारक का नाम	स्वीकृत लोन	मिली राशि
धरम यादव	50000	10000
सिया राम पासवान	50000	8000
संतोष पासवान	50000	8000
संगम तांती	50000	8000
बिलास तांती	50000	8000
सुगंठ महतों	50000	8000
मानो देवी	50000	8000
जयमाला देवी	50000	8000
मुन्नी देवी	50000	8000
फुला देवी	50000	8000
देवकी देवी	50000	8000
रीना देवी	50000	8000
गुलाबी देवी	50000	8000
प्रर्मीला देवी	50000	8000
सरीता देवी	50000	8000
रूबी देवी	50000	8000
मंडली देवी	50000	8000
जटही देवी	50000	8000
बबीता देवी	50000	8000
रेशम देवी	50000	8000
बिंदी देवी	50000	8000
समतोला देवी	50000	8000
राधा देवी	50000	8000
बिमला देवी	50000	8000
पुतुल देवी	50000	8000

HPL Electric & Power Pvt. Ltd.
www.hplindia.com
POWER OF TECHNOLOGY
C/o : C&FA SURYA UDYOG
Ist Floor, Bhagat Sadan, Sahi Lane, S.P. Verma Road, Patna-1
Ph No. : 0612-3260738
Mob. No. : 7541895555
E-mail : surya.udyog.br@gmail.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ., साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बताये। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते समय लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम झीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मैं क्या करूं? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मित विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करूं? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिश्न में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डड ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ., साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कप पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बतायें। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें :
REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला
फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- मोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेडर्स 9903175579, देव मार्कटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -बिजापुर 9341610592 गुलबर्ग:9343834519

गर्मी की मार से बचें

ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

Dr.A.K. Gupta
MBBS, DCH SASARAM

गर्मियां जोरों पर है। प्रायः सबको गर्मियों के दौरान लू लगने और त्वचा की समस्या होती है। गर्मी के मौसम में हवा के गर्म थपेड़ों और बढ़े हुए तापमान से लू लगने का खतरा बढ़ जाता है, खासकर धूप में घूमनेवालों, खिलाड़ियों, बच्चों, बूढ़े और बीमारों को लू लगने का डर ज्यादा रहता है। डॉ एन.के. गुप्ता सासाराम के अनुभवी चिकित्सक ने अपने चिंता जाहिर की और इस गर्मी की मार से बच कर रहने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि लू से बचने के लिए खुब पानी पियें। इस मौसम में पेट की समस्या बढ़ती है इसलिए चिकना चीज न खायें। यदि लूज मोसन हो तो ओ आर एस का घोल लें नहीं रहने पर एक चुटकी नमक और एक चुटकी चीनी घोलकर लें। इस मौसम में पूरे बांह का कपड़ा पहनें और ज्यादा से ज्यादा ठंडा चीज खायें। आजकल मलेरिया तथा टायफायड ज्यादा है इससे बचने के लिए मच्छरदानी के साथ साथ फुल बांह के शर्ट के साथ-साथ पानी को गर्म कर पुनः ठंडा कर पीयें। अन्य सावधानियों में – लू से बचने के लिए शरीर में पानी की कमी न होने दें, स्वच्छ पानी पीएं। तेज गर्म हवाओं में बाहर जाने से बचें। नंगे बदन और नंगे पैर धूप में न निकलें। निकलना आवश्यक हो तो पूरे और ढीले कपड़े पहनकर निकलें, ताकि उनमें हवा लगती रहे। सिर ढक कर रखें ज्यादा टाइट और गहरे रंग के कपड़े न पहनें। सूती कपड़े पहनें। सिंथेटिक, नायलॉन और पॉलिएस्टर के कपड़े न पहनें खाली पेट बाहर न जाएं और ज्यादा देर भूखे रहने से बचें। धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करें। इसके अलावा, सिर पर गीला या सादा कपड़ा रखकर चलें। चश्मा पहनकर बाहर जाएं। चेहरे को कपड़े से ढक लें। घर से पानी या कोई ठंडा शरबत पीकर निकलें, जैसे आम पना, शिकंजी, खस का शर्बत आदि। साथ में भी पानी लेकर चलें।बहुत ज्यादा पसीना आया हो तो फौरन ठंडा पानी न पीएं। उच्च रक्तचाप के रोगी शिकंजी में सेंधा नमक का प्रयोग करें। रोजाना नहाएं और शरीर को ठंडा रखें। ■ -भारती

NOKSIRA
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

URSLIV Tab.
Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT
Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX
Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap
Omeprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

संस्कृति सहेजने वाली भावना

नवीन चौहान

आपने यह तो सुना ही होगा कि बनारस का पान खाने से अक्ल का ताला खुल जाता है, लेकिन बनारस का यह मशहूर पान आखिर मिलता कहां है, यह पान बनता कैसे है और यह पान किस तरह बनारस की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा हो जाता है. डॉक्युमेंट्री फिल्मों की युवा निर्माता भावना रघुवंशी अपनी लघु फिल्म, पान-अ वे ऑफ लाइफ इन वाराणसी के जरिए ऐसे ही सवालों को ढूंढने की कोशिश करती दिखती हैं. उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है. यहां की संस्कृति, खान-पान, बोल-चाल, मेल-जोल सबमें विविधता है. यहां के हर स्थान की अपनी अलग पहचान है. उत्तर प्रदेश की संस्कृति के कई ऐसे ही नायाब पहलुओं को सहेजने और फिल्मों के जरिए उसे लोगों को दिखाने का जज्बा है भावना रघुवंशी में. उनकी दो डॉक्युमेंट्री बनारस के खान और पान पर ही बनी है. बनारस के बारे में क्या खूब लिखा गया कि यह जगह नहीं बल्कि मनोदशा है. जहां खान, पान, भांग और स्नान ही पहचान है. उसी तरह राजधानी लखनऊ को शहर-ए-तहजीब कहा जाता है. लखनऊ की नज़ाकत के बारे में तो सबने सुना है लेकिन लखनऊ की हर गली अपने अंदर कला, संस्कृति और इतिहास का एक पन्ना छिपाए हुई है. भावना अपने कैमरे से उन्हीं पन्नों पर जमी धूल हटाने का काम कर रही हैं.

भावना ने अपनी डॉक्युमेंट्री पान-अ वे ऑफ लाइफ इन वाराणसी में दिखाया है कि पान किस तरह बनारस की संस्कृति में रचा बसा है. विश्वनाथ गली स्थित दीपक तांबूल भंडार बनारस की सबसे पुरानी पान की दुकान है. जहां के पान का अपना अनूठा स्वाद है. उस तरह बीएचयू के लंका स्थित केशव पान भंडार की भी अपनी विशिष्ट पहचान है. लोग यहां दूर दूर से पान खाने आते हैं. पान यहां सम्मान और व्यवहार का सूचक है. इसी तरह वाराणसी- द मेल्टिंग पॉट ऑफ फूड कल्चर में भावना ने बनारस के खान-पान की विविधता और विशिष्टता दिखाई है. बनारस के छोटी दिखने वाली पुरानी दुकानों में वो गज़ब का स्वाद है जो आज भी लाजवाब है. इन दुकानों में कचहरी बाजार स्थित राम भंडार है जो 1888 में शुरू हुई जहां लोग आज भी देसी घी में बनी कचौड़ी और जलेबी का नाश्ता करने आते हैं. बनारस के खाने में शुद्धता और स्वाद का बेजोड़ संगम है. ठंड में मिलने वाली मलइयो बनारस की विशिष्ट पहचान है. मार्कंडेय जी की दुकान में मिलने वाली मलइयो खाने के लिए आपको घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है. यदि आप दिसंबर और जनवरी के महीने में बनारस आते हैं तो मलइयो खाना न भूलें. ऐसी ही कहानी रामनगर स्थित शिवप्रसाद लस्सी भंडार और ब्लू लस्सी भंडार की भी है. जहां मिलने वाली दही रबड़ी वाली और फ्रूट लस्सी का अपना अनूठा स्वाद है.

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान के बारे में भावना कहती हैं कि आप किसी से उत्तर प्रदेश की कला-संस्कृति की बात कीजिए लेकिन लोगों के जहन में इसकी कोई साफ छवि उभरकर सामने नहीं आती है. चाहे बनारस हो, लखनऊ हो, आगरा हो या कोई और शहर इन शहरों की संस्कृति, कला, इतिहास और खान-पान के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है. जबकि दूसरे राज्यों के लोग अपने-अपने शहर, क्षेत्र-प्रदेश के खान-पान, संस्कृति और परिधान के बारे में जानते हैं और उस पर गर्व करते हैं. कभी-कभी लगता है कि हम नए आकाश ढूंढने के चक्कर में अपने घोसलों और अपनी जड़ों से दूर हो गए हैं. ऐसे में आपके लिए अपनी पहचान को बनाए रखना मुश्किल हो गया. और इसी पहचान को बचाए रखने के लिए मैंने डॉक्युमेंट्री फिल्में बनाने की शुरूआत की है. पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनकी कहानी की पृष्ठभूमि में भी उत्तर प्रदेश के छोटे शहर ही रहे हैं. इस बात से भावना बेहद उत्साहित हैं कि देर सबेर बॉलीवुड को उत्तर प्रदेश की सुध तो आई. लेकिन उनका मानना है कि इसमें भी एक दरार है, क्योंकि जो भी फिल्में यहां बन रही हैं, उनमें प्रदेश के रिप्रेजेंटेशन की जगह उसका कैरिकेचर लोगों के सामने पेश किया गया है. पान, बीड़ी, गाली-गलौज से हटकर उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ है. लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, मैं उसी दिशा में काम कर रही हूं. भावना लोगों को एक कहानीकार और निर्देशक के रूप में प्रदेश की ऐसी कहानियां बताना चाहती हैं जो हटकर हों और उन विषयों में लोगों की दिलचस्पी हो. उनमें लोग अपना बचपन और अपने शहर को ढूंढ सकें. ऐसी कहानियां पूरे प्रदेश में भरी पड़ी हैं और उन्हें लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं.

भावना कहती हैं कि ऐसा समय आ गया है जब देश का हर शहर शक्ल-सूरत में एक जैसा नज़र आता है. लोगों का पहनावा एक जैसा है, इमारतें एक जैसी हैं, ऐसे में हर शहर के सामने अपनी पारंपरिक पहचान को बनाए रखने का प्रश्न आ खड़ा हुआ है. आज बड़ी संख्या में लोग विदेशों में काम करते हैं और वहां अपने परिवार के साथ रहते हैं, ऐसे में वह अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रह पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे. अपनी जड़ों से दूर जाना अपने आपको न पहचान पाना. हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं. इन सवालों के जवाब किसी न किसी को देने ही होंगे. ऐसे में भावना को लगा कि क्यों न मैं इन सवालों के जवाब तलाशूं. यही सवाल उन्हें दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस ले आए और उन्होंने यहीं से इन सवालों के जवाब तलाशने शुरू किए. वह कहती हैं कि बनारस के बहुत से ऐसे पहलू हैं जिन्हें लोगों के सामने लाना चाहिए. बनारस पर उनकी और भी कई डॉक्यूमेंट्री आने वाली हैं जिनपर अभी काम चल रहा है उनमें मुख्य रूप से बनारस का जीवन दर्शन नज़र आएगा. वह कहती हैं कि उस दर्शन के कई पहलुओं के पास पहुंची हूं और बहुत से पहलुओं तक पहुंचना अभी बाकी है.

लोकगीत हमारी संस्कृति का एक ऐसा अंग हैं, जिन्हें पर्व-त्यौहार और मनोरंजन के लिए गाया जाता है. उदाहरण के लिए आल्हा और फाग. लेकिन इनकी पहचान भी खत्म होती जा रही है. इनका दायरा गावों तक सीमित रह गया है. भावना कहती हैं कि लोकगीतों का आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इतना महत्व है कि लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं. बॉलीवुड म्यूजिक के अलावा भी देश में ऐसा संगीत है जिसे लोग बड़े चाव से सुनते हैं, वह कहती हैं कि हमारी पीढ़ी के भी बहुत से लोग बहुत सी चीजों से अनभिज्ञ हैं ऐसे में आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? इन्हें सहेजने की जिम्मेदारी हमारी-आपकी है. पहले खेलकूद और पढ़ाई लिखाई में हमें इन चीजों के बारे में जानने का समय नहीं मिला, लेकिन अब लगता है कि इनकी जो वास्तविकता है और इसे लेकर लोगों का जो दृष्टिकोण है मैं उसे जानूं और लोगों को उससे रूबरू करवाऊं. उसे लेकर लोगों में जो पैशन है उसकी कहानियां बताऊं.

क्योंकि ये सभी जुड़कर उत्तर प्रदेश का चरित्र बनाते हैं. फिलहाल उन्होंने राज्य सरकार के पास वित्तीय मदद करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, वह मानती हैं कि यह अभी शुरुआत है. लोगों को उनका काम पसंद आ रहा है, लोग उनके काम की प्रशंसा भी कर रहे हैं. जल्दी ही यह उत्तर प्रदेश सरकार के पास अच्छा प्रस्ताव लेकर जाने वाली हैं. उन्हें आशा है कि सरकार उनकी मदद करेगी, क्योंकि जब भी कोई आप अच्छा काम अच्छी नीयत और अच्छे विचार के साथ करते हैं तो आपको हर जगह लोगों की मदद मिलती है. बाकी खट्टे मीठे अनुभव तो होते हैं. अतः वह उत्तर प्रदेश को कैरीकेचर के दायरे से बाहर लाकर उसके असली रंग लोगों को दिखाना चाहती हैं और वह अपनी शुरुआती प्रयास में सफल भी हुई हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन

ऐसे बनेगा कांग्रेस मुक्त भारत

राजकुमार शर्मा

भाजपा और मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस मुक्त भारत के तहत उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारे में मोदी सरकार की इस तानाशाही की चर्चा जोरों पर है. यह बिल्कुल साफ है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर लिया गया. जबकि 28 मार्च को महामहिम राज्यपाल डॉ. कृष्णकांत पॉल ने हरीश रावत को विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहा था. लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि मोदी सरकार को विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत साबित करने का मौका देना चाहिए था. क्या भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं को इस बात का डर था कि कांग्रेस की हरीश रावत सरकार विधानसभा में बहुत साबित कर लेगी? इसलिए बहुमत साबित करने से पहले ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया. उत्तराखंड विधानसभा के कुल 70 विधायकों में कांग्रेस के 36 विधायक थे जिनमें से 9 बागी हो चुके हैं. भाजपा के 28 विधायक हैं जिनमें से एक निलंबित है. बसपा के दो, निर्दलीय तीन और एक विधायक उत्तराखंड क्रांति दल का है.

इससे पहले राष्ट्रपति शासन लगाने के पहले ही उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया था कि भाजपा लगातार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की धमकी दे रही है. उन्होंने कहा था कि अहंकार में चूर केंद्र का शासक दल एक छोटे से सीमांत राज्य को राष्ट्रपति शासन लागू करने की धमकी दे रहा है. रावत ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में संविधान की महत्वपूर्ण धाराएं हैं और एक सर्वमान्य प्रक्रिया है जो अदालती फैसलों पर आधारित है. उनका कहना था कि सभी राज्यों ने इस संदर्भ में प्रक्रियाओं का आदर किया है. उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि उत्तराखंड प्रशासनिक मशीनरी के चरमराने का असली उदाहरण है और संविधान के लिहाज से जो कुछ भी गलत हो सकता था वो वहां हुआ है. आप दिए गए समय का इस्तेमाल प्रलोभन देने और रिश्वत देने में कर रहे हैं जो कि संविधान का उल्लंघन है.

राजनीतिक समीक्षकों का कहना है कि कांग्रेस के 9 विधायकों के बागी होने से सरकार के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो गया था, लेकिन यह कोई ऐसा गंभीर संवैधानिक संकट नहीं था कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता वह भी इतने उतावलेपन में. विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के बाद सदन का अंकगणित पूरी तरह से हरीश रावत के पक्ष में था. कुल 70 में से 9 विधायकों के घटने के बाद सदन की संख्या 61 रह गई. कांग्रेस के 27 और पीडीएफ(पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट) के 6 विधायकों को मिलाकर हरीश सरकार को कुल 33 विधायकों का समर्थन प्राप्त है और साथ ही कांग्रेस के पास मनोनीत एक विधायक भी है.

भाजपा ने शायद इसी समीकरण से डर कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया. अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की विदाई के महीने भर बाद ही उत्तराखंड की सत्ता से भी कांग्रेस को अपदस्थ कर दिया गया. अब देखना है कि अगली बारी कौन से प्रदेश की आती है, मणिपुर या हिमाचल प्रदेश की. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और अब यह मामला न्यायालय में है. इस समस्या का समाधान मोदी सरकार राजनीतिक तरीके से निकाल सकती थी, लेकिन इस मामले को जानबूझकर कानूनी पचड़े में फंसा दिया गया.

उत्तराखंड की जनता के मन में एक सवाल है कि 2017 में राज्य में चुनाव होने ही थे, तो क्या केवल 10 महीने का इंतजार नहीं किया जा सकता था? 2017 में जनता खुद फैसला करती कि उसे किसकी सरकार चाहिए और कौन ईमानदार है कांग्रेस या भाजपा. राज्य में राष्ट्रपति शासन के बाद उत्तराखंड की जनता का मूड देखकर यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है.

राज्य में घूम-घूम कर हरीश रावत का यह कहना कि मुझे आवाम ने नहीं हटाया, मेरा तो कत्ल प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है. यह बात जनता को सोचने पर मजबूर कर रही है. इस सच्चाई से इंकार नहीं किया जा सकता कि सत्तारुढ़ होने के बाद रावत की राजनीतिक चाल के आगे प्रदेश में अमित शाह की हर चाल को मात मिल रही थी.

सूबे में भाजपा अपने दिग्गजों के आपसी कलह को अब तक रोक नहीं पाई है जिसकी वजह से मोदी मंत्रिमंडल में राज्य का एक भी सांसद मंत्री नहीं है. कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि जनतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों के खिलाफ जो तलवारें चलाई जा रही हैं वह सब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत के संकल्प का एक हिस्सा है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इशारे पर देश को धर्मयुद्ध की तरफ धकेला जा रहा है. प्रधानमंत्री ने जनता से जो वादा किया था उस पर पूरी तरह उनका असफल होना और उनकी अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए धर्म का सहारा लिया जा रहा है. उन्होंने मोदी सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा एवं संविधान के खिलाफ आचरण पर प्रहार किया. उन्होंने कहा, जो लोग शाह, मोदी के षड्यंत्र का शिकार होकर कांग्रेस से बगावत की राह पर हैं, उन लोगों ने भाजपा के साम्प्रदायिक नीतियों के खिलाफ जनमत हासिल किया था. उन्हें अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए. दिग्विजय सिंह का कहना है, जो लोग घर वापस आना चाहते हैं वो बगावत का रास्ता छोड़कर घर आएं. उनके लिए कांग्रेस का दरवाजा हमेशा खुला है. ■

feedback@chauthiduniya.com

11 निर्दोष सिखों को आतंकी बता कर मारने वाले 47 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद

आधा इंसाफ 25 साल बाद

तीर्थयात्रा से लौट रहे सिख परिवारों पर टूटा था कहर | **पुलिस ने एक युवक की लाश ही गायब कर दी** | **सीबीआई ने जांच से बड़े अफसरों को बख्श दिया**

पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ मामले में 57 पुलिसवालों को आरोपी बनाया गया था. सुनवाई के दौरान इनमें से 10 की मौत हो गई. बाकी बचे 47 पुलिसवालों को अदालत ने अपहरण व हत्या का दोषी ठहराया था. सारे दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा भुगतने के साथ-साथ रैंक के मुताबिक जुर्माना भी भरना पड़ेगा. थानाध्यक्ष या थाना प्रभारी को 11 लाख रुपये जुर्माना के बतौर भरने होंगे. इसी तरह दारोगा को आठ लाख रुपये और सिपाही को पौने तीन लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

दीनबंधु कबीर

अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर निकले सिख परिवारों के 11 नवयुवकों को बस से उतार कर यूपी पुलिस ने उनकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस हत्याकांड को मुठभेड़ बताया और मरने वाले सिखों को आतंकवादी. पुलिस ने खूब वाहवाहियां बटोरीं और तरक्कियां पाईं. 12 जुलाई 1991 को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पुलिस ने यह जघन्य कृत्य किया था. घटना के 25 साल बाद सीबीआई की अदालत ने जब 47 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो पुलिस वाले अपने मौलिक चरित्र पर आ गए. कोर्ट में ही खूब हंगामा किया और तोड़फोड़ की. दोषी साबित हुए पुलिसवाले कोर्ट में चार घंटे तक बवाल मचाते रहे और कोर्टरूम से गैलरी तक हंगामा खड़ा कर दिया. पुलिसकर्मियों ने चिल्ला-चिल्ला कर अदालत पर भेदभाव का आरोप लगाया और कठघरे में लात मारी. उन लोगों ने कोर्टरूम की खिड़कियां भी तोड़ डालीं. बहरहाल, भारतवर्ष की विलंबित ताल से चलने वाली कानूनी प्रक्रिया में 25 साल बाद ही सही, अदालत ने उम्मीद की लौ तो दिखाई ही है. जिस परिवार के 11 युवा सदस्य आतंकवादी बता कर मार डाले गए, उन्हें इस फैसले से क्या मिलने वाला! गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल के अध्यक्ष सरदार अमीर सिंह विर्क ऐसा कहते हुए उन पीड़ित परिवारों की वेदना जाहिर करते हैं, जो तीर्थ यात्रा की मौज-मस्ती करते हुए पीलीभीत में मातम में तब्दील होने के लिए आ रहे थे.

पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ कांड में दोषी ठहराए गए सभी 47 पुलिसवालों को सीबीआई की विशेष अदालत ने पिछले दिनों लखनऊ में उम्रकैद की सजा सुनाई. विशेष अदालत के जज लल्लू सिंह ने सभी हत्यारे पुलिसवालों को उनके पद के हिसाब से जुर्माना भी लगाया और फर्जी मुठभेड़ में मारे गए 11 सिखों के परिवार को 14-14 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश भी दिया. सीबीआई की विशेष अदालत ने पुलिस के बड़े अफसरों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सख्त टिप्पणियां की हैं और कहा है कि सीबीआई की जांच में व्यवस्थागत दिक्कतों की वजह से ट्रायल से बच गए पुलिस के आला अफसरों पर दोबारा केस चलाने की सारी संभावनाएं हैं. अदालत ने साफ-साफ कहा कि जब तक एनकाउंटर से प्रमोशन तय होंगे, निरीह और निर्दोष लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और पुलिस वाले निरीह लोगों की इसी तरह हत्याएं करते रहेंगे. एनकाउंटर पर एसआई को इंस्पेक्टर बना दिया जाता है तो इंस्पेक्टर को डीएसपी. प्रमोशन का यही लालच पुलिसवालों को फर्जी एनकाउंटर के लिए उकसाता है. इन्हें रोकने के लिए प्रमोशन को एनकाउंटर से अलग करना होगा. अदालत ने यह सवाल भी उठाया कि मारे गए सभी लोग यदि चरमपंथी थे तो उनके पास से कोई हथियार क्यों नहीं बरामद हुए और तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में एक ही रात में मुठभेड़ कैसे हुई. जबकि पीलीभीत पुलिस ने पहले यह कहा था कि मारे गए लोगों के पास से हथियार बरामद हुए थे. लेकिन बाद में यह बात झूठी पाई गई.

पीलीभीत फर्जी मुठभेड़ मामले में 57 पुलिसवालों को आरोपी बनाया गया था. सुनवाई के दौरान इनमें से 10 की मौत हो गई. बाकी बचे 47 पुलिसवालों को अदालत ने अपहरण व हत्या का दोषी ठहराया था. सारे दोषी पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा भुगतने के साथ-साथ रैंक के मुताबिक जुर्माना भी भरना पड़ेगा. थानाध्यक्ष या थाना प्रभारी को 11 लाख रुपये जुर्माना के बतौर भरने होंगे. इसी तरह दारोगा को आठ लाख रुपये और सिपाही को पौने तीन लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.

फर्जी मुठभेड़ की सीबीआई जांच पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं. सीबीआई ने मुठभेड़ के पीछे दिशा-निर्देश देने वाले आला अधिकारियों को क्यों छोड़ दिया और उनके खिलाफ छानबीन क्यों नहीं की? सीबीआई ने उन बड़े अफसरों को क्यों बचाया? जिस तरह 11 सिख पुरुषों को तीन हिस्सों में बांटा गया और अलग-अलग इलाकों में ले जाकर उनकी हत्या की गई, उससे यह स्पष्ट होता है कि सिखों को गोलियां मारने का निर्देश आला अधिकारियों से मिल रहा था. पुलिस के सामान्य अधिकारी या कर्मचारी बिना सीनियर अधिकारियों के निर्देश के इस तरह का हत्याकांड नहीं कर सकते. लेकिन सीबीआई ने अपनी जांच से उन्हें दूर रखा. हालांकि, सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाते वक्त कहा भी कि फर्जी मुठभेड़ में पर्दे के पीछे से निर्णायक रोल अदा करने वाले आला अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी संभावना है.

उल्लेखनीय है कि 12 जुलाई 1991 को तीर्थ यात्रा से लौट रहे सिख यात्रियों की बस को पीलीभीत पुलिस ने कछाला घाट के पास रोका और 11 युवकों को उतारकर पुलिस की नीली बस में बैठा लिया. बाद में इनमें से दस की लाश मिली जबकि शाहजहांपुर के तलविंदर सिंह का आज तक पता नहीं चला. उस रात पीलीभीत जिले के तीन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में तीन एनकाउंटर हुए दिखाए गए. अगले दिन पुलिस ने न्यूरिया, बिलसंडा और पूरनपुर थाना क्षेत्र में हुई तीन मुठभेड़ों में दस खालिस्तानी आतंकियों को मारने का दावा किया. पुलिस ने यह भी कहा था कि मारे गए लोगों में से कई के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं. मारे गए सभी सिख युवकों का आनन-फानन में पोस्टमॉर्टम कराया गया और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी करा दिया गया.

उस वक्त तो पुलिस के इस एक्शन की हर जगह प्रशंसा हुई थी लेकिन कुछ समय बाद ही यह भेद खुला कि तीनों एनकाउंटर फर्जी थे. पुलिस ने अपनी एफआईआर में इन सभी को चरमपंथी बताते हुए पुलिस पर हमला करने का आरोप लगाया था लेकिन मारे गए लोगों के परिवारजनों ने आरोप लगाया कि मुठभेड़ फ़र्जी थी. पीलीभीत के रहने वाले हरजिंदर सिंह कहलों को इस एनकाउंटर पर पूरा शक था, क्योंकि मरने वाले लोगों में कुछ लोगों को वह बेहद करीब से जानते थे. उन्हें पुलिस की चरमपंथी वाली थ्योरी हजम नहीं हो रही थी. वह इन एनकाउंटर की जांच के लिए पुलिस के पास गए लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की. जब जांच को लेकर उन्हें पुलिस की मंशा सही नहीं लगी तो वह दिल्ली गए और वहां के सिख समुदाय के कुछ नामी गिरामी लोगों की मदद से मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गए.

हरजिंदर सिंह कहलों कहते हैं कि सीबीआई अदालत के फैसले के खिलाफ वे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. इस अपराध की सजा फांसी से कम नहीं होनी चाहिए. जिन परिवारों ने अपना बेटा, भाई, पति और पिता को इस फर्जी मुठभेड़ में खो दिया, उन्हें पूरा न्याय दिलाने तक अन्याय के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी. पुलिसकर्मियों पर अदालत में दोष सिद्ध हो चुका, उन्हें फांसी दिलाने और इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे तत्कालीन आइजी जोन, बरेली रेंज के डीआइजी व पुलिस अधीक्षक को सजा दिलाने के लिए भी वह कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. वरिष्ठ अधिकारियों के संरक्षण के बिना इंस्पेक्टर और सिपाही इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते. इस प्रकरण में तीन आईपीएस अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है. उन्हें उम्मीद थी कि सीबीआई इन तीनों की भूमिका की भी जांच करेगी. लेकिन सीबीआई ने छोटी मछलियों को शिकार बनाया, सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में पीलीभीत के तत्कालीन एसपी आरडी त्रिपाठी सहित तीन अधिकारियों के नाम शामिल नहीं किए थे. आखिर क्या कारण था कि सीबीआई ने इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए सरकार से अनुमति भी नहीं मांगी.

हालांकि सजा का फैसला अभी सीबीआई अदालत का है और मामले की सुनवाई आगे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होगी. इसलिए अंतिम फैसला आने में अभी और वक्त लगेगा. लेकिन सीबीआई अदालत के फैसले से पीड़ित परिवारों को थोड़ी ठंडक तो पहुंची ही है. फर्जी मुठभेड़ मामले में पीलीभीत पुलिस ने बाकायदा पूरनपुर, न्यूरिया और बिलसंडा थाने में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे. विवेचना के बाद पुलिस ने इन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा कर फाइल बंद कर दी थी. हरजिंदर सिंह कहलों की तरफ से वकील आरएस सोढ़ी ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 1992 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. सीबीआई ने मामले की विवेचना के बाद 57 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सबूतों के आधार पर चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 178 गवाह बनाए और पुलिसकर्मियों के हथियार, कारतूसों समेत 101 सबूत इकट्ठा किए. सीबीआई ने 207 कागजातों को भी अपनी 58 पन्नों की चार्जशीट में साक्ष्य के तौर पर शामिल किया था. सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद 12 जून 1995 को इसका संज्ञान लिया गया और 3 फरवरी 2001 को इसे सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया. 20 जनवरी 2003 को सत्र न्यायालय ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे. कोर्ट ने साफ-साफ कहा कि सिखों की हत्याएं हुई हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है. सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री (सीएफएसएल) के रिटायर्ड वैज्ञानिक सत्यपाल शर्मा के बयान का विश्लेषण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि उसी बस में गोलियों के निशान पाए गए थे, जिस बस में 11 सिख युवकों को बैठाकर ले जाया गया था. इस मामले के गवाह डॉ. जीजी गोपालदास और फार्मासिस्ट डीपी अवस्थी ने अपना विचित्र बयान दिया था कि घटना के वक्त न्यूरिया थानाध्यक्ष जीपी सिंह जिला अस्पताल पीलीभीत के इमरजेंसी वार्ड में अपना इलाज करा रहे थे. जबकि थानाध्यक्ष ने खुद ही थाने की जीडी में दर्ज किया था कि वे घटनास्थल पर थे. कोर्ट ने कहा कि युवकों को पहले ही मार दिया गया था. केवल रात के आने और गुजरने का इंतजार किया जा रहा था, ताकि रात में मुठभेड़ दिखाई जा सके. पोस्टमार्टम करने वाले डॉ. विमल कुमार का कहना था कि युवकों के शरीर पर केवल गोलियों के जख्म और चोटें ही नहीं थीं, बल्कि चोटों के अन्य निशान भी थे. यानी, युवकों को मारा पीटा गया, घसीटा गया और फिर उन्हें गोलियां मारी गईं. पीएसी के प्लाटून कमांडर दयान सिंह और पीएसी के कुछ अन्य जवानों ने बयान दिया कि तीनों थाना क्षेत्रों में घटना के दिन थाने में उनकी आमद और रवानगी का गलत उल्लेख किया गया था. पीएसी ने किसी भी मुठभेड़ में हिस्सा नहीं लिया. तीनों थानों की जीडी में पीएसी की आमद और रवानगी जिस समय दिखाई गई, उस समय पीएसी के जवान अपने अपने कैंपों में थे. केवल मुठभेड़ को सही साबित करने के लिए पीएसी के जवानों को 13 जुलाई 1991 की सुबह तीन बजे थाने पर बुलाया गया और ड्यूटी का पर्चा भी दिया गया.■

मृत्युदंड से अधिक कष्टकर है आजीवन कारावास

सीबीआई की विशेष अदालत जब अपना फैसला सुना रही थी, तब सीबीआई अभियोजक एससी जायसवाल ने सभी आरोपियों को मृत्युदंड देने की मांग की. इस पर कोर्ट ने कहा कि मृत्युदंड वास्तव में बहुत छोटी सजा है, जो बहुत कम पीड़ा के साथ समाप्त हो जाती है. जबकि आजीवन कारावास को भोगने वाला व्यक्ति रोज मरता है.

फर्जी मुठभेड़ में सजा एक न्यायपूर्ण फैसला

उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व आईजी एसआर दारापुरी ने पीलीभीत फर्जी पुलिस मुठभेड़ के मामले में 47 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सज़ा को एक न्यायपूर्ण फैसला बताया है. सजा सुनाने के निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि हम लोग अपनी न्याय व्यवस्था में भरोसा रख सकते हैं. दारापुरी ने कहा कि सीबीआई की विवेचना में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें केवल निम्न स्तर के पुलिस अधिकारियों को ही दोषी सिद्ध किया गया और किसी भी उच्च अधिकारी के खिलाफ जांच भी नहीं की गई. खास तौर पर पीलीभीत के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के खिलाफ सीबीआई का जांच नहीं करना संदेहास्पद है. पुलिस महकमे में काम करने वाले सभी लोग जानते हैं कि जिले में कोई भी फर्जी मुठभेड़ पुलिस अधीक्षक की जानकारी और सहमति के बिना नहीं हो सकती है.

पूर्व आईजी ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस फर्जी मुठभेड़ के मामले में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को दंडित किया जाना उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए करारी सीख है. इसके वे जरूर कुछ सबक लेंगे और भविष्य में ऐसी फर्जी मुठभेड़ करने से बचेंगे.

बस से उतारकर इन्हें मारा गया

1. नरिंदर सिंह उर्फ निंदर, पिता दर्शन सिंह, पीलीभीत
2. लखविंदर सिंह उर्फ लाखा, पिता गुरमेज सिंह, पीलीभीत
3. बलजीत सिंह उर्फ पप्पू, पिता बसंत सिंह, गुरदासपुर
4. जसवंत सिंह उर्फ जस्सा, पिता बसंत सिंह, गुरदासपुर
5. जसवंत सिंह उर्फ फौजी, पिता अजायब सिंह, बटाला
6. करतार सिंह, पिता अजायब सिंह, बटाला
7. मुखविंदर सिंह उर्फ मुखा, पिता संतोख सिंह, बटाला
8. हरमिंदर सिंह उर्फ मिंटा, पिता अजायब सिंह, गुरदासपुर
9. सुरजनसिंह उर्फ बिट्टो, पिता करनैल सिंह, गुरदासपुर
10. रनधीर सिंह उर्फ धीरा, पिता सुंदर सिंह, गुरदासपुर
11. तलविंदर सिंह, पिता मलकैत सिंह, शाहजहांपुर (लाश भी नहीं मिली)

feedback@chauthiduniya.com

निर्देशकों के बीच अभिनेता बनने की होड़

अनंत विजय

अपने छात्र जीवन में या यों कहें कि स्कूल के दिनों में जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्रि की फिल्म हीरो देखी थी. उस फिल्म में उसके निर्देशक सुभाष घई चंद पलों के लिए दिखाई दिए थे. तब सुभाष घई को फिल्म में देखकर सिनेमा हॉल में तालियां बजी थीं और थोड़ा शोर भी हुआ था. तब मुझे इस बात को लेकर बहुत जिज्ञासा हुई कि निर्देशक फिल्म में क्या करने आया था. बाद में लोगों ने बताया कि सुभाष घई अपनी हर फिल्म के किसी ना किसी सीन के कुछ फ्रेम में अवश्य नज़र आते हैं. फिल्म से जुड़े लोगों का मानना है कि सुभाष घई इसको अपनी फिल्मों के लिए शुभ मानते हैं. उनको लगता है कि वो जिस फिल्म में थोड़ी देर के लिए भी दिखाई देंगे वो फिल्म हिट हो जाएगी. उस वक्त मेरे लिए निर्देशक का पर्दे पर आना विस्मय था. तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि फिल्मों के निर्देशक खुद नायकों की भूमिका में नजर आने लगेंगे. अभी हाल ही में हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक प्रकाश झा की फिल्म आई है जय गंगाजल. अपनी इस फिल्म का निर्देशन भी प्रकाश झा ने ही किया है और उसमें मुख्य भूमिका में भी वही हैं. साठ साल के प्रकाश झा की एक्टिंग की चारों तरफ तारीफ अवश्य हुई. पुलिस अफसर की भूमिका में उनकी डॉयलॉग डिलीवरी से लेकर स्टंट आदि के सीन में भी उनके अभिनय की प्रशंसा हुई, इसके बावजूद फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही. जय गंगाजल के फ्लॉप होने के बावजूद अभिनय को लेकर प्रकाश झा के हौसले बुलंद हैं. फिल्म के जानकारों के हवाले से खबर ये है कि प्रकाश झा अपनी अगली फिल्म में बतौर नायक काम करने जा रहे हैं. यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रकाश झा को जिन दर्शकों ने निर्देशक के तौर पर भरपूर प्यार दिया, वो उनको अभिनेता के तौर पर कितना पसंद करते हैं. लंबे वक्त से फिल्मों से जुड़े प्रकाश झा को अभिनय की बारीकियों का तो पता है ही.

ऐसा नहीं है कि प्रकाश झा इकलौते ऐसे निर्देशक हैं, जिन्होंने फिल्म में अभिनय करना शुरू कर दिया है. इसके पहले अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में करण जौहर ने भी भूमिका निभाई थी. इस फिल्म में करन जौहर निगेटिव रोल में थे. छोटे पर्दे पर अपनी सफलता से उत्साहित करन जौहर ने फिल्मों में काम करना शुरु किया लेकिन वो यहां कोई कमाल नहीं दिखा पाए. अनुराग कश्यप की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी. जबकि इस फिल्म में करन जौहर के अलावा अनुष्का शर्मा और रणबीर कपूर भी थे. यह फिल्म लेखक ज्ञान प्रकाश के उपन्यास मुंबई फेबल्स पर बनी थी. सिर्फ करन जौहर और

प्रकाश झा

करण जौहर

तिग्मांशु धूलिया

प्रकाश झा ही क्यों नए निर्देशक के तौर पर अपनी पहचान कायम करने वाले तिग्मांशु धूलिया ने भी कई फिल्मों में काम किया. अपनी फिल्म साहब बीवी और गैंगस्टर में भी तिग्मांशु ने अभिनय किया. जिमी शेरगिल, माही गिल और रणदीप हुड्डा के साथ तिग्मांशु भी इस फिल्म में थे. यह फिल्म भी कोई जोरदार बिजनेस नहीं कर पाई, लेकिन सफलता के लिहाज से ठीक-ठाक रही. कहा गया था कि इसने अपनी लागत निकाल ली थी. तिग्मांशु ने तो अनुराग कश्यप की बहुचर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में मुख्य विलेन का किरदार निभाया था. तिग्मांशु भी इस फिल्म में निगेटिव रोल में थे और इस फिल्म में उनके अभिनय की भी काफी तारीफ हुई थी और इसने बिजनेस भी अच्छा किया था. इस फिल्म को देश विदेश में कई पुरस्कार भी मिले थे. जहां तक मुझे याद पड़ता है कि अनुराग कश्यप ने भी किसी फिल्म में अभिनय किया है.

नब्बे के दशक के शुरुआत में लमहे और उसके बाद फिल्म हिमालयपुत्र के साथ बतौर सहायक निर्देशक जुड़े फरहान अख्तर इन दिनों बेहद कामयाब हीरो हैं. फरहान अख्तर ने सबसे पहले 1991 में फिल्म लमहे का सहायक निर्देशन किया लेकिन निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म रही दिल चाहता है. इस फिल्म से फरहान अख्तर को एक नई पहचान तो मिली ही निर्देशक के तौर पर सम्मान भी मिला. इसके बाद फरहान अख्तर ने दो हजार चार में लक्ष्य फिल्म बनाई और उसी साल बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हुई. उन्होंने ब्राइड एंड प्रीज्यूडिस के लिए गाने लिखे. फरहान बेहद प्रतिभाशाली हैं और अपने पिता जावेद अख्तर की तरह लेखन में भी सिद्धहस्त हैं. निर्देशक के तौर पर उन्होंने शाहरुख खान को हीरे लेकर फिल्म डॉन बनाई जो कारोबार के लिहाज से सुपर हिट रही थी. सहायक निर्देशक के तौर पर करियर शुरू करने के सत्रह साल बाद फरहान अख्तर ने दो हजार आठ में रॉक ऑन के साथ अपने अभिनय के करियर की शुरुआत की. इस फिल्म को दर्शकों ने काफी सराहा और जमकर पुरस्कार आदि मिले. इसके बाद फरहान अख्तर ने फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में सह अभिनेता का रोल किया. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान के अभिनय की प्रशंसा हुई तो उनके हौसले बुलंद हो गए. उसके बाद उन्होंने भाग मिल्खा भाग से अपने अभिनय के झंडे गाड़ दिए. अभी हाल ही में उनकी एक फिल्म आई है बजीर जिसमें उन्होंने सदी के महानायक अभिताभ बच्चन के साथ अभिनय किया है. फरहान ने निर्देशक और अभिनेता के मिश्रण का एक आदर्श प्रस्तुत किया जिसमें वो दोनों भूमिकाओं में सफल रहे हैं. उनके बाद ये फेहरिश्त लंबी होनी शुरू हो गई है.

अब सवाल यही है कि फिल्मों ने निर्देशकों ने अभिनय करना क्यों शुरू कर दिया है. जो सबसे पहली बात सतह पर दिखाई देती है वो है ग्लैमर और लोगों के बीच अपने को पहचाने जाने की चाहत. पर्दे के पीछे के प्रोड्यूसर के मन में कहीं ना कहीं यह आकांक्षा दबी होती है कि वह भी पर्दे पर दिखे और लोग उनको भी पहचानें. जैसे न्यूज चैनल में खबरों को बनाने वाले प्रोड्यूसर्स को कोई जानता नहीं है, क्योंकि वो कभी टीवी स्क्रीन पर नजर नहीं आता है. उसी तरह फिल्मों में भी प्रोड्यूसरों और निर्देशकों को कोई जानता नहीं है. पोस्टरों पर उनका नाम अवश्य होता है लेकिन उनकी तस्वीर आदि कहीं नहीं छपती. प्रोड्यूसर निर्देशक को लगता होगा कि जो अभिनेता उनकी मर्जी से अभिनय करते हैं, उनके कहे अनुसार किरदार में ढलते हैं. फिर सफल होकर लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, तो क्यों ना वो खुद भी इस भूमिका में आएं. न्यूज चैनल के प्रोड्यूसर्स पर तो पेशगत व्यस्तता भी होती है, क्योंकि उनको कई और काम करने होते हैं. लेकिन जो खुद फिल्म बना रहा है या जो खुद फिल्मों में पैसे निवेश कर या करवा रहा है, उसको अभिनय करने से कौन रोक सकता है. एक तो ये मानसिकता हो सकती है जो निर्देशकों को अभिनय की ओर खींच कर लेकर आती है. दूसरी बात यह हो सकती है कि कुछ निर्देशकों को लगता होगा कि अभिनेताओं को बताने के बाद भी अगर वह किरदार को पर्दे पर सही तरीके से उतार नहीं पा रहे हैं तो वह खुद उस किरदार में घुसकर उसको जीवंत कर सकते हैं. यह सोच भी निर्देशकों के अभिनेता बनने की राह तैयार करती है. एक और बात है वह यह कि जब से हिंदी फिल्मों में चॉकलेटी हीरो का दौर खत्म हुआ है और हर तरह के चेहरे मोहरे, काले गोरे हीरो हिट होने लगे हैं तो निर्देशकों के सामने भी सुंदर होने या दिखने की बाध्यता खत्म हो गई है. उनको लगता है कि दर्शक को बेहतर अभिनय के आधार पर किसी भी अभिनेता को पसंद या नापसंद करते हैं. लिहाजा वो खुद से यह अपेक्षा करते हैं या मान लेते हैं कि किसी खास किरदार के लिए वही सबसे फिट हैं. अब अगर जय गंगाजल की बात की जाए और उसमें डीएसपी की भूमिका में प्रकाश झा की बात हो तो यह लगता है कि वो इस किरदार के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल थे. जिस तरह से उन्होंने लखीसराय के अधेड़ और घूसखोर सर्कल बाबू की भूमिका निभाई है, उसमें वो फिट बैठते हैं. फिर अब तो कम उम्र हीरो के सफल होने की बात भी बीते दिनों की बात हो गई. अब तो लगभग सभी सुपर स्टार पचास पार के हैं. ऐसे में निर्देशकों को भी लगता है कि किसी भी उम्र में वो अभिनय करने के लिए उतर सकते हैं और अपनी सफलता का परचम लहरा सकते हैं. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

पुस्तक समीक्षा

हिचकी: नए साहित्यिक सृजन की ओर एक क़दम

शफीक आलम

पिछले दिनों नोएडा में एक भव्य कार्यक्रम में कला, साहित्य, संस्कृति और मानविकी को समर्पित एक नई हिंदी मासिक पत्रिका हिचकी का लोकार्पण हुआ. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि साहित्य के विकास में साहित्यिक पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है. ये पत्रिकाएं जहां एक तरफ नए और पुराने साहित्यिक विमर्शों से पाठकों को अवगत रखती हैं. वहीं नए और पुराने रचनाकारों के बीच पुल का काम भी करती हैं. मौजूदा दौर में जहां विचार और विमर्श का मूल्यांकन भी एक वस्तु की तरह हो रहा है, उसमें एक साहित्यिक पत्रिका निकालना चुनौती पूर्ण क़दम है. हिचकी के सम्पादकीय में कार्यकारी संपादक डॉ. अमी आधार निडर इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नज़र आते हैं. वह लिखते हैं कि साहित्य जगत में आज एक गंभीर चुनौती है प्रयोजन की. प्रायोजित साहित्य बाज़ार पर तेज़ी से आक्रमण कर रहा है और मौलिक रूप से साहित्य सृजन में जुटी पत्र-पत्रिकाओं को प्रतिकूल परिवेश में अपनी यात्रा जारी रखनी पड़ रही है.

हिचकी का यह पहला अंक है. और जैसा कि इसके आवरण पृष्ठ पर ही उधृत किया गया है कि यह कला, साहित्य, संस्कृति और मानविकी पर केंद्रित पत्रिका है. लिहाज़ा इस में अंक में जहां एक तरफ कहानियां, कविताएं, यात्रावृतांत शामिल है. वहीं संस्कृति, इतिहास, राजनितिक तथा साहित्यिक विमर्शों पर भी भरपूर सामग्रियां मौजूद हैं. आज के राजनितिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीयता एक ज्वलंत विषय बन गया है, इसलिए इसे समझना अत्यंत आवश्यक हो गया है. इस विषय पर आगरा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और इस पत्रिका के संरक्षक प्रोफेसर अगम प्रसाद माथुर का एक-एक आलेख शामिल है. जिसमें प्रोफेसर माथुर ने इस मुद्दे पर भरपूर बहस की है. कहानियों में जहां प्रियंका सोनी प्रीत की कहानी कुकुरमुत्ते की तरह हमारे समाज के एक अंधकारमय कोने में पड़ी ज़िंदगी को टटोलने का प्रयास है. वहीं ज्योति नारायण की कहानी उसकी मुस्कान समाज में व्याप्त अमीरी और गरीबी के बीच की खाई को बड़े मासूम और सहज अंदाज़ में दिखाने की कोशिश की है. इसके अलावा बुन्देली संस्कृति और लोक जीवन पर डॉ. सरोज गुप्ता का आलेख बुन्देलखंड की संस्कृति के उन पहलुओं पर रौशनी डालती है, जो आम पाठकों की नज़रों से दूर थी. हिंदी कहानीकार जयश्री रॉय की कहानी संग्रह कायांतर पर डॉ. किरण पोपकर का शोध आलेख, डॉ. सपना मांगलिक का आलेख *संपादन और साहित्य का शिखर: धर्मवीर भारती*, जय भगवन गुप्त का फिल्म गीतकार कवि प्रदीप पर आलेख, कल्पना श्रीवास्तव का अंग्रेजी के प्रभाव से बिगड़ती हिंदी पर आलेख इस अंक में शामिल सामग्रियों की विविधता को ज़ाहिर करते हैं और पाठक को इस दौड़ती भागती ज़िन्दगी में थोड़ी देर रुक कर सांस लेने तथा अपने और अपने समाज के बारे में सोचने की दावत देते हैं.

पत्रिका: हिचकी (मासिक)
प्रकाशन स्थान: आगरा
मूल्य: 40 रूपये
वर्ष: 1, अंक: 1
पृष्ठ: 84

दरअसल, जहां इस अंक में कहानी और आलोचना को पूरी नुमाइंदगी दी गई है. वहीं कविता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. इस अंक में शामिल सामग्रियों पर एक नज़र डालने से यह अंदाज़ा हो जाता है कि इस पत्रिका में पुराने लिखने वालों के साथ-साथ नई प्रतिभावों और नए हस्ताक्षरों को भी भरपूर प्रतिनिधित्व मिलेगा और पाठक साहित्य के साथ-साथ देश के अलग-अलग क्षेत्रों की संस्कृत से भी वाकिफ होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं वंदना

दुःख-निवृत्ति : मायूसी कम कैसे हो

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

बाबा की राह पर चलते-चलते जब इंसान को मायूसी चारों ओर से घेर ले तो वह क्या करे?

एक कविता में मैंने लिखा था- जब दिल उदास हो तो साईं का नाम लेना. इंसान जीवन में दुःख और पीड़ा का सामना करते-करते कभी-कभी जरूर मायूसी अनुभव करता है. परन्तु जितने सत्य यह दुःख और पीड़ा हैं, उतने ही सत्य सुख और आनंद भी हैं. बाबा को दोनों ही परिस्थितियों में देखना चाहिए. सुख में बहुत आनंदित न होकर व्यर्थ समय गंवाए बिना अगर हम बाबा के नाम से दूसरों की मदद करें या बाबा के कार्य करें तो उससे जिस सुख की अनुभूति होगी, वह चिरस्थायी होगी, जबकि भौतिक सुख क्षणिक होता है एवं उसके चले जाने पर दुःख पहुंचता है. जब दुःख पहुंचे तो बाबा का कथन- आगे-आगे देखो होता है क्या? याद करें. बाबा का सान्निध्य और चिंतन करने से दुःख कम होता है. साईं सच्चरित्र पढ़ने से, बाबा के भजन गाने से दुःख जरूर कम होता है. बुरे वक्त में जितना हो सके बाबा के बारे में पढ़ना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जपना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और दूसरे दुखियों की मदद करनी चाहिए ताकि जिस पाप-कर्म से दुःख मिला था, वह पाप-कर्म कट जाए.

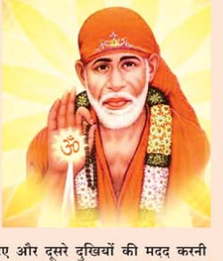

समस्याओं का समाधान

अनेक लोग अपनी विभिन्न समस्याओं का समाधान चाहते हैं. उन लोगों को क्या करना चाहिए?

मैं बाबा के भक्तों से यही कहता हूं कि उन्हें जो कुछ मांगना है वह मात्र बाबा से मांगें. देने वाले तो बाबा ही हैं. वह मंदिर में बैठकर ध्यान लगाएं, फूल-माला चढ़ाएं. बाबा की आरतियां-जो अधिकांशतः मराठी में और कुछ संस्कृत में हैं- उन्हें पढ़कर उनका अर्थ समझें. साथ ही, श्री साईं-सच्चरित्र का पाठ करें. कुछ लोग इस बात को अभी समझ नहीं रहे हैं कि उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कहीं न कहीं श्री साईं सच्चरित्र में है. मैं यह दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उन्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर श्री साईं-सच्चरित्र में निश्चित रूप से मिल जाएंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

गर्मियों में त्वचा की देखभाल कैसे करें

डॉ. दीपाली भारद्वाज

सनस्क्रीन

ऐसे तो इसकी आवश्यकता पूरे वर्ष पड़ती है, लेकिन इसका इस्तेमाल गर्मियों में अधिक किया जाता है. अपनी त्वचा का ख्याल रखने के लिए, खुद को सूरज की किरणों से बचाने के लिए कम से कम 30 एसपीएफ (सन प्रोटेक्शन फैक्टर) सनस्क्रीन का प्रयोग करें. सनस्क्रीन सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है. ये किरणें हमारी त्वचा को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे त्वचा बूढ़ी और खराब हो जाती है और त्वचा कैंसर होने का भी खतरा होता है. जिनकी त्वचा पर अधिक तेल हो उन्हें जेल आधारित सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए. जिनकी त्वचा सूखी हो उन्हें मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए. हर 6 महीने के अंदर अपना प्रोडेक्ट बदलते रहना चाहिए.

बॉडी स्क्रब

गर्मियों में स्किन काफी ख़राब हो जाती है, मृत स्कीन को फिर से स्वस्थ्य रखने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है. सभी प्रकार की त्वचा के लिए गर्मी के दिनों में एक दो बार इसका उपयोग करना जरुरी है. उदाहरण के लिए मुंहासे वाले त्वचा की जरूरत मुल्तानी मिट्टी, चंदन, पानी, तुलसी, गुलाब है, जबकि सूखी परिपक्व त्वचा के लिए सफेद अंडे, नींबू, दही, हल्दी की एक चुटकी और बेसन का उपयोग किया जा सकता है.

स्कीन मॉइस्चराइजर

गर्मियों के दिनों में मॉइस्चराइजिंग त्वचा को स्वस्थ्य बनाए रखना आवश्यक है. सामान्य प्रकार की त्वचा के लिए पानी आधारित मॉइस्चराइजर काफी लाभदायक है और तैलीय त्वचा के लिए जेल आधारित मॉइस्चराइजर काफी उपयोगी है. इसके अलावा, गर्मियों के दिनों में अधिक पानी पीना चाहिए. ज्यादा पानी पीने से गर्मियों में शरीर हाइड्रेटेड रहता है और निर्जलीकरण को रोकने में काफी लाभदायक होता है. आपको ज्यादा देर तक प्यासा नहीं रहना चाहिए.

गर्मियों का आहार- पानी अधिक पीना चाहिए. तरबूज, ककड़ी और नारियल पानी का सेवन करना चाहिए. फल इत्यादि खाने चाहिए, पौष्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए.

अन्य उपाय: हो सके तो गर्मियों में दोपहर को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उस वक्त सूर्य की रोशनी काफी तेज होती है. उस समय घर पर ही आराम करना चाहिए. धूप में निकलने से पहले टोपी का इस्तेमाल करना काफी जरूरी है. इसके अलावा गर्मियों के दौरान बालों में शैम्पू करने से उन्हें स्वस्थ्य बनाए रखने में मदद मिलती है. ■

(लेखिका दिल्ली में द स्कीन एंड हेयर क्लीनिक चलाती हैं)

feedback@chauthiduniya.com

चार गेंदों में चार छक्के जड़कर वेस्टइंडीज बना विश्व चैंपियन

ब्रेथवेट ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए

नवीन चौहान

आईपीएल और बिग बैश जैसी क्रिकेट लीग्स के शुरू होने के बाद कैरेबियाई खिलाड़ियों को पैसे कमाने के ज्यादा अवसर दिखाई देने लगे और ये खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा लीग क्रिकेट को वरीयता देने लगे. लेकिन टी-20 विश्व कप जीत की सफलता का रहस्य भी इसी में छुपा है. वेस्टइंडीज के खिलाड़ी दुनियाभर में होने वाली टी-20 क्रिकेट लीग्स में खेलते हैं, उनके पास टी-20 क्रिकेट का अच्छा अनुभव है. वे टी-20 फार्मेट के विशेषज्ञ बनकर उभरे हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाड़ी डेवेन ब्रावो ने जब चैंपियन, चैंपियन गीत लिखा, उस वक्त उन्होंने यह सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका यह गीत वेस्टइंडीज की टी-20 विश्वकप जीत का विजय गीत बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा. कारलोस ब्रेथवेट के बल्ले से विजयी छक्का लगते ही सारी दुनिया चैंपियन, चैंपियन गीत की धुन के साथ जश्न में डूब गई. कैरेबियाई ऑलराउंडर कारलोस ब्रेथवेट ने इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए विश्वकप फाइनल में चार गेंदों पर चार छक्के जड़कर कोलकाता के ईडन गार्डन में इतिहास रच दिया और वेस्टइंडीज को दूसरी बार फटाफट क्रिकेट का बादशाह बना दिया. यह साल कैरेबियाई क्रिकेट के लिए सफलताओं का साल है. महज 49 दिन में वेस्टइंडीज की टीम तीन बार विश्वचैंपियन बनी. सबसे पहले वेस्टइंडीज की अंडर-19 टीम बांग्लादेश में भारत को हराकर विश्वविजेता बनी. इसके बाद 3 अप्रैल की शाम को स्टेफनी टेलर के नेतृत्व वाली वेस्टइंडीज की महिला क्रिकेट टीम ने पिछले तीन बार की विश्वविजेता ऑस्ट्रेलिया के विजय रथ को रोककर टी-20 विश्वकप पर पहली बार क़ब्जा किया. महिलाओं ने बाद बारी थी पुरुषों की. जिन्होंने बड़े ही बेखौफ और धमाकेदार अंदाज में इंग्लैंड को चार विकेट से मात देकर उनके दूसरी बार टी-20 विश्वकप जीतने के सपने पर पानी फेर दिया.

बेहद रोमांचक रहे फाइनल मुक़ाबले में वेस्टइंडीज को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यक्ता थी, स्ट्राइक पर थे पहली बार विश्वकप खेल रहे कारलोस ब्रेथवेट, जिन्हें केरन पोलार्ड के चोटिल होने के बाद अंतिम समय में टीम में जगह मिली थी. गेंद थी इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज बेन स्ट्रोक्स के हाथों में. पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था. ब्रेथवेट ने पहली गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग, दूसरी गेंद पर लॉन्ग आन, तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ और चौथी गेंद पर डीप मिडविकेट पर छक्का जड़कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए. किसी भी मैच में अंतिम ओवर में एक छक्का लगाकर जीतना भी बेहद मुश्किल होता है, वहीं विश्वकप फाइनल जैसे अहम मुक़ाबले के अंतिम ओवर में ब्रेथवेट ने चार गेंदों पर चार छक्के जड़कर इंग्लैंड के मुंह से जीत छीन ली और कैरेबियाई टीम को दूसरी बार टी-20 विश्व चैंपियन बना दिया. इससे पहले साल 2012 में श्रीलंका में आयोजित हुए टी-20 विश्वकप में कैरेबियाई टीम पहली बार टी-20 चैंपियन बनी थी. एक दिवसीय विश्व कप भी दो बार जीतने वाली पहली टीम बनने का कारनामा वेस्टइंडीज ने 1975 और 1979 का विश्व कप जीतकर किया था. साल 2012 के विश्वकप फाइनल की तरह इस बार भी मार्वन सैमुअल्स ने वेस्टइंडीज की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 155 रनों को पीछा करते वक्त सैमुअल्स ने एक छोर थामे रखा. वह 66 गेंदों में 9 चौके और 2 छक्कों की मदद से 85 रन बनाकर अंत तक नाबाद रहे.

इससे पहले टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरूआत अच्छी नहीं रही. पहले ही ओवर में सैमुअल बद्री ने जेसन रॉय को चलता कर दिया. पांचवें ओवर में टीम का स्कोर 28 रन पर तीन विकेट हो गया था. लेकिन पूरे टूर्नामेंट में इंग्लैंड के हीरो रहे जॉय रूट ने जोस बटलर के साथ मोर्चा संभाला और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. अंततः इंग्लैंड 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन ही बना सका. रूट ने इंग्लैंड की ओर से सर्वाधिक 54 रन बनाए. इसके बाद रनों का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही. पारी के दूसरे ओवर में जॉय रूट ने जेसन चार्लस और क्रिस गेल को आउट कर मैच को रोमांचक मोड़ पर ला दिया. इसके बाद जो हुआ वह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. पहली बार किसी टीम ने टी-20 विश्वकप के फाइनल मुक़ाबले में 150 रनों से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करके जीत हासिल की है.

कैरेबियाई द्वीपों में एक बार फिर क्रिकेट की जड़ें गहरी होती दिखाई दे रही हैं. पिछले कुछ साल में टी-20 क्रिकेट में कैरेबियाई क्रिकेट टीम को अच्छी सफलता मिली है. चार साल के अंतराल में दोबारा विश्वकप जीत लेना इस बात का प्रमाण है. अंडर-19 टीम की विश्वकप जीत से राष्ट्रीय टीम ने प्रेरणा ली और सारे विवादों और परेशानियों को दरकिनार कर जीत हासिल की. पिछले एक दशक में वेस्टइंडीज की टीम बेहद खराब दौर से गुजरी है. लंबे समय से खिलाड़ियों और बोर्ड के बीच विवाद चल रहा है. साल 2014 में भारत का दौरा बीच में छोड़ने के बाद बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच मतभेद गहरा गए थे. गेल और ब्रेवो जैसे स्टार खिलाड़ियों को विवादों की वजह से लंबे समय तक टीम से बाहर रहना पड़ा. साल 2007 में वन-डे विश्व कप के आयोजन के बाद वेस्टइंडीज बोर्ड की वित्तीय स्थिति बेहद खराब हो गई थी. खिलाड़ियों को वेतन और भत्तों के लिए बोर्ड से लड़ना पड़ रहा था. इस वजह से वेस्टइंडीज क्रिकेट धीरे-धीरे अपने सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया. लेकिन आईपीएल और बिग बैश जैसी क्रिकेट लीग्स के शुरू होने के बाद कैरेबियाई खिलाड़ियों को पैसे कमाने के ज्यादा अवसर दिखाई देने लगे और खिलाड़ी अंतराष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा लीग क्रिकेट को वरीयता देने लगे. लेकिन टी-20 विश्व कप जीत की सफलता का रहस्य भी इसी में छुपा है. वेस्टइंडीज के खिलाड़ी दुनियाभर में होने वाली टी-20 क्रिकेट लीग्स में खेलते हैं, उनके पास टी-20 क्रिकेट का अच्छा अनुभव है जिन टीमों की तरफ से कैरेबियाई खिलाड़ी खेलते हैं वे उस टीम की मुख्य ताकत होते हैं.

ये सभी खिलाड़ी टी-20 विशेषज्ञ बनकर उभरे हैं. इसीलिए कप्तान सैमी हर वक्त यह कहते रहे कि उनकी टीम में 15 मैच विनर्स हैं. ऐसे में जरूरत केवल खिलाड़ियों को एकजुट करने और टीम को संतुलित करने की थी. बोर्ड के साथ विश्व कप से पहले हुए कॉन्ट्रैक्ट विवाद ने टीम को एकजुट कर दिया. इनके पास बोर्ड के सामने अपनी काबीलियत साबित करने का जीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं था. जो उन्होंने कर दिखाया है. टी-20 लीग क्रिकेट में मिलने वाले पैसे की वजह से कैरेबियाई देशों में युवा एक बार फिर क्रिकेट को बतौर करियर अपना रहे हैं. विश्व विजेता बनने के बाद सैमी ने कहा कि टी-20 की सफलता को हमें वन-डे और टेस्ट क्रिकेट में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है. अंडर-19 टीम की विश्व कप जीत यह बताती है कि हमारे यहां प्रतिभा की कमी नहीं है. जरूरत है तो उन्हें सही दिशा देने की. वेस्टइंडीज के खिलाड़ी बोर्ड के रवैये को लेकर बेहद खफा हैं. मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी वेस्टइंडीज की विश्व विजय के बाद कर विंडीज़ टीम को टू चैंपियन बताते हुए विंडीज बोर्ड से टीम का सपोर्ट करने और उनकी चिंताओं पर ध्यान देने के लिए कहा. विश्व विजेता बनने के बाद बोर्ड के रुख पर डैरेन सैमी ने कहा कि सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने के बाद हमें हर जगह से शुभकामनाएं मिल रही थीं लेकिन हमारे क्रिकेट बोर्ड की ओर से कोई संदेश नहीं आया. हम जानते हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचे हैं. विश्वकप से पहले वेतन विवाद की वजह से टीम के विश्व कप में भाग लेने पर कई तरह की अटकलें लग रही थीं, किसी तरह विवाद सुलझा और टीम भारत पहुंची. लेकिन जब हम कोलकाता पहुंचे तब हमारे पास टीम की जर्सी नहीं थी. विश्वकप में भाग लेने के लिए खिलाड़ी दुगने वेतन की मांग कर रहे थे. विवाद को निपटता न देख बोर्ड ने विश्व कप में दूसरे दर्जे की टीम भेजने की धमकी दी थी. सैमी ने कहा कि हम अपनी बात केवल विश्वकप जीतकर ही सिद्ध कर सकते थे इसलिए जीत और सफलता की भूख टीम के हर खिलाड़ी में थी. विवाद की वजह से विश्वकप से पहले टीम ने एक भी अंतरराष्ट्रीय टी-20 मैच नहीं खेला था. इस जीत का श्रेय पूरी टीम और कोचिंग स्टाफ को जाता है. हम अपनी इस जीत को कैरेबियाई लोगों को समर्पित करते हैं.

जीत के बाद डेवेन ब्रावो ने कहा कि हमारे यहां का क्रिकेट गलत हाथों में है. हमें पता है कि वह नहीं चाहते थे और न ही उन्हें विश्वास था कि हम यह टूर्नामेंट जीत सकते हैं. सामान्यतः वो हमारे खिलाफ थे. यहां तक कि बीसीसीआई हमारे लिए बहुत करता है. हम यहां सिर्फ और सिर्फ जीत के इरादे से आए थे, क्योंकि हममें से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो साल 2020 ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्डकप का हिस्सा शायद न हो पाएं.

वेस्टइंडीज के प्रत्येक खिलाड़ी ने एक-एक मैच में टीम को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में जीत के हीरो क्रिस गेल रहे, उन्होंने 48 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाकर टीम को पहली जीत दिलाई. इसके बाद दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ गेंदबाजी में सैमुअल बद्री ने 12 रन देकर तीन विकेट लिए और आंद्रे फ्लेचर ने 64 गेंदों में 84 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिला दी. इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में सधी हुई गेंदबाजी कर गेल ने दो विकेट झटके और बल्लेबाजी में मार्वन सैमुअल्स ने 44 गेंदों पर 43 रन बनाकर टीम की सेमीफाइनल में जगह पक्की कर दी. लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में वेस्टइंडीज की टीम को हार का सामना करना पड़ा. अफगानिस्तान के 123 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज की टीम महज 117 रन बना सकी. लेकिन सेमी-फाइनल में मेजबान भारत के 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए लिंडल सिमंस की 51 गेंदों पर नाबाद 82 रनों की पारी की बदौलत 7 विकेट से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई. टीम की बल्लेबाजी केवल क्रिस गेल पर निर्भर नहीं रही. सेमीफाइनल और फाइनल जैसे अहम मुकाबलों में गेल के जल्दी आउट होने के बावजूद टीम ने जीत हासिल की. मार्वन सैमुअल्स ने टीम की ओर से 6 मैचों में सर्वाधिक 181 रन बनाए, जबकि गेंदबाजी में सैमुअल बद्री, आंद्रे रसेल और डेवेन ब्रेवो ने 9-9 विकेट लिए. बद्री ने 5.39 की औसत के साथ सबसे किफायती गेंदबाजी की.

वेस्टइंडीज की जीत सही मायने में पूरी टीम की जीत है, विपरीत समय में हर कोई एक जुट हो जाता है और हर किसी का खेल निखरकर सबके सामने आता है. यही उन्होंने कर दिखाया है और दुनिया को बताया है कि वही असली चैंपियन हैं.■

फाइनल में वेस्टइंडीज को जीत के लिए अंतिम 6 गेंदों में 19 रनों की आवश्यक्ता थी, कारलोस ब्रेथवेट स्ट्राइक पर थे. गेंद थी इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज बेन स्ट्रोक्स के हाथों में. पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था. ब्रेथवेट ने पहली गेंद पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग, दूसरी गेंद पर लॉन्ग आन, तीसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ और चौथी गेंद पर डीप मिडविकेट पर छक्का जड़कर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और इतिहास रच दिया.

आस्ट्रेलिया को हराकर कैरेबियन महिलाएं बनीं सिरमौर

वेस्टइंडीज ने कोलकाता केईडन गार्डन में खेले गए ख़िताबी मुक़ाबले में तीन बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप खिताब जीत लिया. वेस्टइंडीज की महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है. इससे पहले लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचने वाले आस्ट्रेलिया ने सलामी बल्लेबाज एलिस विलानी (52) और कप्तान मेग लैनिंग (52) के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 77 रन की साझेदारी से पांच विकेट पर 148 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया. जवाब में वेस्टइंडीज ने 19.3 ओवरों में दो विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया. हेले मैथ्यूज ने सर्वाधिक 66 रन बनाए जबकि कप्तान स्टेफ़ानी टेलर ने 59 रनों की पारी खेली. दिएंद्रा डॉटिन 18 रनों पर नाबाद लौटीं.■

विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज

टीम इंडिया के उप-कप्तान विराट कोहली को विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया. कोहली ने पांच मैचों की पांच पारी में तीन बार नाबाद रहकर 136. 50 की औसत से 273 रन बनाए. उनका उच्चतम स्कोर नाबाद 89 रन रहा जो उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में बनाए. विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाबाद 82 रनों की पारी खेलकर टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाया था. उन्हें आईसीसी की विश्व कप टी-20 टीम का कप्तान भी बनाया गया है.■

navinonline2003@gmail.com

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

बिग बी, कंगना और बाहुबली बने बेस्ट

राष्ट्रपति भवन में आयोजित 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में एस. एस. राजामौली की निर्देशित फिल्म बाहुबली : द बिगिनिंग को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला. महानायक अमिताभ बच्चन (पीकू) और कंगना रनौत (तनु वेड्स मनु रिटर्न्स) को क्रमश: सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बाहुबली ने सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है. दक्षिण भारतीय सिनेमा की कई फिल्में विजेता बनकर उभरी. वहीं, बॉलीवुड फिल्म बजरंगी भाईजान ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होल्सम एंटरटेनमेंट का पुरस्कार जीता. संजय लीला भंसाली ने बाज़ीराव मस्तानी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता. इस फिल्म में अपने अभिनय से वाहवाही लूटने वाली जानी-मानी अदाकारा तन्वी आज़मी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बाज़ीराव मस्तानी को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी (सुदीप चटर्जी) का पुरस्कार भी दिया गया. वहीं, दम लगाके हइशा ने सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फिल्म, इसी के साथ गायिका मोनाली ठाकुर ने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता. मोनाली को यह पुरस्कार मोह मोह के धागे... गाने के लिए दिया गया.

नीरज घायवन को मसान के लिए इंदिरा अवॉर्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अभिनेता-फिल्मकार समुथिरकानी को तमिल फिल्म विसरनाई के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से अलंकृत किया गया. वहीं, मलयालम फिल्म निर्णायकम को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू चुना गया. गौरव मेनन ने बेन फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार जीता.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कंगना को मिला जन्मदिन पर बेस्ट तोहफ़ा

कंगना को मिलेगा तीसरा नेशनल अवॉर्ड. बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार को अपने लिए अब तक का सबसे अच्छा जन्म दिन उपहार बताया है. तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत की झोली में आया है. इससे पहले कंगना 2008 में फैशन के लिए वे बेस्ट सपोर्टिंग और 2015 में क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड जीत चुकी हैं.

एस.एस. राजामौली की निर्देशित फिल्म बाहुबली : द बिगिनिंग को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला. बाहुबली ने सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है.

बिग बी ने फैन्स को कहा शुक्रिया

सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद प्रशंसकों से मिली बधाई पर असीम आभार जताते हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने सभी प्रशंसकों को शुक्रिया अदा किया . बच्चन ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर जिन लोगों ने मुझे बधाई दी है, उन सभी का मैं बहुत आभारी हूं. लिहाजा, अपनी भावना व्यक्त करने के लिए महज़ शुक्रिया कह देना काफी नहीं है.

अमिताभ को अब तक चार नेशनल अवॉर्ड

- 1990 में अग्निपथ के लिए बेस्ट एक्टर
- 2005 में ब्लैक के लिए बेस्ट एक्टर
- 2009 पा के लिए बेस्ट एक्टर
- 2016 में पीकू के लिए बेस्ट एक्टर

बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म बजरंगी भाईजान

बजरंगी भाईजान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया है. कोई शक नहीं कि सलमान खान फैंस इस ख़बर से बेहद उत्साहित हैं. सलमान खान की दबंग के बाद बजरंगी भाईजान दूसरी फिल्म हैं, जिसे इस कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है. बहरहाल, इस मौके पर निर्देशक कबीर खान ने खुशी जाहिर की है.

राष्ट्रीय पुरस्कारों की सूची

- बेस्ट एक्टर: अमिताभ बच्चन, पीकू के लिए
- बेस्ट एक्ट्रेस: कंगना, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए
- बेस्ट फिल्म: बाहुबली द बिगिनिंग
- बेस्ट डायरेक्टर: संजय लीला भंसाली, बाजीराव मस्तानी के लिए
- बेस्ट डॉयलॉग/स्क्रीनप्ले: जूही चतुर्वेदी (पीकू), हिमांशु शर्मा (तनु वेड्स मनु रिटर्न्स)
- बेस्ट कोरियोग्राफर: रेमो डिसूजा (बाजीराव मस्तानी)
- बेस्ट हिंदी फिल्म: दम लगा के हइशा
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: तनवी आज़मी, बाज़ीराव मस्तानी के लिए
- बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर: नीरज घायवन
- राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाली बेस्ट फिल्म: नानक शाह फकीर
- सामाजिक मूर्तों पर बेस्ट फिल्म: निर्णायकम
- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: समुथिकणी (विसारणी)
- बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट: गौरव मेनन (बेन)
- बेस्ट सिंगर (फीमेल): मोनाली ठाकुर (दम लगा के हइशा)
- बेस्ट लिरिक्स: वरुण ग्रोवर, (मोह मोह के धागे..)
- बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म: बजरंगी भाईजान
- स्पेशल जूरी अवॉर्ड: कल्किज कोचलीन (मार्गेरीटा विद अ स्ट्रॉ)
- बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन: पायल सलूजा (नानक शाह फकीर)
- बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन: बाज़ीराव मस्तानी
- बेस्ट स्क्रीनप्ले (एडेप्टेड): विशाल भारद्वाज (तलवार)
- बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (बैकग्राउंड स्कोर) : इलैयाराजा
- बेस्ट बांग्ला फिल्म: शंकचिल
- बेस्ट मराठी फिल्म: रिंगण
- बेस्ट मलयालम फिल्म: पाथेमरी
- बेस्ट तमिल फिल्म: विसारनई
- बेस्ट तेलुगु फिल्म: कंचे
- बेस्ट संस्कृत फिल्म: प्रिथमनसम
- बेस्ट कन्नड फिल्म: तिथि
- बेस्ट पंजाबी फिल्म: चौथी कूट
- बेस्ट कोंकणी फिल्म: एनिमी
- बेस्ट असमिया फिल्म: कोठनोडी
- बेस्ट हरियाणवी फिल्म: सतरंगी
- बेस्ट मणिपुरी फिल्म: ऐवुसु याओहन्बिबु
- बेस्ट मिजोरमी फिल्म: लोड बियॉन्ड द क्लास
- बेस्ट उड़िया फिल्म: पहाड़ रा लुहा
- बेस्ट वांचो फिल्म: द हेड हंटर
- बेस्ट खासी फिल्म: उनाता

भंसाली को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड

भंसाली के डायरेक्शन में बनी देवदास 2003 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होल्सम एंटरटेनमेंट रही.

ब्लैक 2005 की बेस्ट फीचर फिल्म रही. इसे भंसाली ने डायरेक्ट किया था.

भंसाली के प्रोडक्शन वाली मैरी कॉम भी 2015 में बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होल्सम एंटरटेनमेंट रही.

भंसाली को 2016 में बाज़ीराव मस्तानी के लिए बेस्ट डायरेक्टर चुना गया.

ग्लैमर की चकाचौंध दुनिया का स्याह पक्ष

नहीं रही बालिका वधू

धनेंद्र कुमार सिंह

छोटे पर्दे की लोकप्रिय अभिनेत्री और टीवी सीरियल बालिका वधू में आनंदी का किरदार निभाने वाली प्रत्यूषा बनर्जी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. प्रत्यूषा की लाश गोरेगांव में स्थित उनके आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकी मिली. उनके दोस्तों का कहना है कि प्रत्यूषा की ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह से काफी समय से अनबन चल रही थी. राहुल की पूर्व गर्लफ्रेंड सोनाली शर्मा भी प्रत्यूषा के साथ दुर्व्यवहार करती थी, जिसकी वजह से वह परेशान थी. प्रत्यूषा राहुल से शादी कर सेटल होना चाहती थी, लेकिन राहुल उससे शादी नहीं करना चाहता था. राहुल

और प्रत्यूषा के बीच अनबन थी. इस बात का सबूत है, प्रत्यूषा के ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज का कबूलनामा कि उसके और प्रत्यूषा के बीच एक अप्रैल को एक दूसरी गर्लफ्रेंड को लेकर बहस हुई थी. प्रत्यूषा ने अपनी शादी के लिए लहंगे बनवा लिए थे, जिसे पहनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया. उन्होंने व्हाट्सएप पर अपना आखिरी मैसेज स्माइली के साथ लिखा, मरके भी मुंह तुझसे न मोड़ना. प्रत्यूषा का एसएमएस यह साफ इशारा करता है कि राहुल को लेकर वह परेशान थीं. पोस्टमार्टम में पता चला कि उनकी मौत दम घुटने से हुई है. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना कि प्रत्यूषा प्रेग्नेंट थीं. लेकिन अभी रिपोर्ट आने के बाद यह साफ हो पाएगा कि सच क्या है? प्रत्यूषा मूल रूप से जमशेदपुर की रहने वाली थीं. प्रत्यूषा बनर्जी बिग बॉस से प्रसिद्ध हुई थीं और काफी नाम कमाया था. लेकिन बालिका वधू में निभाए गए आनंदी के किरादर से उनको शोहरत मिली थी. इस समय वह धारावाहिक ससुराल सिमर का में नजर आ रही थीं. उन्होंने बिग बॉस, झलक दिखला जा, पॉवर कपल, सावधान इंडिया और हम हैं न जैसे सीरियलों में काम किया था. प्रत्यूषा की आत्महत्या की खबर ने सबको चौंका दिया था. लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ज़िंदगी में इतनी सफलता पाने के बावजूद कोई शख्स कैसे अपनी जान ले सकता है. सवाल कई हैं लेकिन ठोस जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, जो बातें प्रत्यूषा के अंतिम सांसे गिनने के बाद धीरे-धीरे लोगों के सामने आ रही हैं. वो ग्लैमर की दुनिया के ख़ौफनाक सच को बयां कर रही हैं. आपको बता दें ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब टीवी या फिल्म जगत की किसी हीरोइन ने ऐसा कदम उठाया हो. इससे पहले भी बॉलीवुड में कुछ ऐसी घटनाएं घटीं, जिसने पूरी फिल्मी दुनिया के लोगों को हिलाकर रख दिया.

जिया खान

अमिताभ बच्चन जैसे सितारे के साथ फिल्म निशब्द से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री जिया खान ने महज़ 25 साल की उम्र में ही जून 2013 में आत्महत्या कर ली. जिया खान के आत्महत्या के मामले में उनके ब्वायफ्रेंड सूरज पंचोली को गिरफ्तार भी किया गया था और अब भी उन पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला चल रहा है. जिया खान ने 2007 में निशब्द, 2008 में गजनी और 2010 में हाउसफुल जैसी फिल्मों में काम किया था और तीनों ही फिल्में सफल रहीं. कहा जाता है कि जिया खान ने एक 6 पेज का सुसाइड नोट लिखा था, जो पंचोली के लिए ही था और उसमें जिया ने प्यार में धोखा दिए जाने की बात लिखी थी.

दिव्या भारती

दिव्या भारती की मौत सिर्फ 19 साल की उम्र में पांच मंजिला इमारत से गिरने की वजह से हो गई. उनकी मृत्यु के इर्द-गिर्द कई सवाल उठाए गए. किसी ने कहा कि ये एक एक्सीडेंट था, किसी ने इसे आत्महत्या कहा तो किसी ने कहा कि दिव्या साजिश का शिकार हुईं. आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि दिव्या भारती की मौत एक आत्महत्या थी, साजिश थी या एक दुर्घटना. इतनी छोटी उम्र में दिव्या की मौत सबको हैरान करने वाली खबर थी. दिव्या की मौत 5 अप्रैल 1993 में हुई थी.

शिखा जोशी

बी.ए पास फिल्म में अपनी एक छोटी सी भूमिका से लोगों का दिल जीत लेने वाली अभिनेत्री शिखा जोशी ने मई 2015 में मुंबई के वरसोवा इलाके में स्थित अपने फ्लैट में आत्महत्या कर ली थी. शिखा जोशी अदाकार और मॉडल दोनों थीं. शिखा बी.ए पास फिल्म सहित कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी थीं. शिखा के दोस्तों का कहना था कि वह डिप्रेशन का शिकार थीं.

सिल्क स्मिता

साउथ फिल्म की जानी-मानी अदाकार सिल्क स्मिता 23 सितंबर 1996 को चेन्नई में अपने घर में मृत पाई गई. वो 35 वर्ष की थीं. ऐसा कहा जाता है कि सिल्क अपने जीवन से इतना निराश हो गई थीं कि उन्होंने आत्महत्या कर ली.■

feedback@chauthiduniya.com

> प्रत्यूषा राहुल से शादी कर सेटल होना चाहती थी, लेकिन राहुल उससे शादी नहीं करना चाहता था. राहुल और प्रत्यूषा के बीच अनबन थी. इस बात का सबूत है प्रत्यूषा के ब्वॉयफ्रेंड राहुल राज का कबूलनामा कि उसके और प्रत्यूषा के बीच एक अप्रैल को एक दूसरी गर्लफ्रेंड को लेकर बहस हुई थी. प्रत्यूषा ने अपनी शादी के लिए लहंगे बनवा लिए थे जिसे पहनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया.